हरियाणा विधान सभा

की कार्यवाही

25 मार्च, 1988

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार 25 मार्च, 1988

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न त्वं उत्तर	(8)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(8)24
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(8)26
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
जिला भिवानी तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सुंडी द्वारा चने की फसल क्षतिग्रस्त होने संबंधी	(8)27
वर्ष 1988– 89 के बजट पर सामान्य चर्चा	(8)28

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 25 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में? प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोंहिन्दर सिंह चट्ठा)ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब क्वैश्चन्ज होगें।

Repair/Construction of Roads in Nilokheri Constituency

***152. Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for repairing the following roads :

(i) from villages Nigdhu to Majra Roran;

(ii) from Sita-mai to Sanwat;

(iii) from Taraori to Jhanjhari;

(iv) from Taraori to Nadana, in Nilokheri Constitunecy;

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired ;

(c) whether there is also a proposal under

consideration of the Government to construct metalled road from Atheri to Raison in Nilokheri Constituency ; and

(d) if so, the time by which the said road is likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

(क)जी हां। यह स्पष्ट किया जाता है कि गाव का नाम जो तरावड़ी से नदाना बताया गया है वह तरावड़ी से नारायणा है। लोकल भाषा में इसे नदाना कहते हैं, जबकि डायरैक्ट्री के अनुसार यह नारायणा है।

(ख)इस सडक की मरम्मत धन की उपलब्धि पर निर्भर करती है तथा इस समय कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

(ग)हंथीरा से रायसन सडक का काये 10.60 लाख रुपये के लिये प्रशासकीय अनुमोदित है जिसकी लम्बाई 3.75 कि० मी० है। डायरैक्ट्री के अनुसार गांव अठेरी का नाम हथीरा है।

(घ)सड़क निर्माणाधीन है और यदि राशि उपलब्ध हुई तो काम अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

श्री जय सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंडी महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जिन सड्कों के बारे में मैंने पूछा है, यह सड़कें कौन से सालों में बनी हैं और इनके बनने के बाद कितनी दफा रिपेयर हुई है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, निलोखेड़ी कास्टिच्यूऐंसी में सड्कों की लम्बाई 224 किलोमीटर है। इनके ऊपर इस साल 31–1– 1988 तक पैचवर्क व बर्म–रिपेयर पर 6 लाख रुपये खर्च हुए हैं 15.66 लाख रुपये नीलोखेडी कांस्टिच्युऐंसी में कई सड्कों की विशेष मुरम्मत पर खर्च हुए पैं। इन चार सड्कों की आम मुरम्मत तथा सरफेसिंग पर 1987– 88 में 1.1.88 तक 98 हजार रुपये खर्च हुए हैं। वर्ष 1986–87 में 70 हजार रुपये खर्च हुए थे, 1985– 86 में एक लाख 36 हजार रुपये खर्च हुए थे और 1984– 85 में 81 हजार रुपये खर्च हुए थे।

श्री जय सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अलग– अलग से कितना पैसा इन सडको पर किस–किस साल में रिपेयर के लिये खर्च हुआ, क्या यह बताने का कष्ट करेंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, निगद्धू से माजरा रोडान सड़क का ऐस्टीमेट 9–3– 1987 को पास हुआ था जो 3 लाख 19 हजार रुपये का है। इस कार्य के लिये सामग्री इकट्ठी की जा रही है और इस सड़क पर 1988– 89 में कार्य शु रू किया जायेगा।

कामरेड हरपाल सिंहः मंत्री महोदय ने यह कहा है कि 9– 3– 1987 को ऐस्टीमेट पीस हुआ है। कई दफा ऐस्टीमेट तो पास हो जाता है और उसके फलस्वरूप सड़क पर कैस्ट्रक्शन

चलती रहती है। लेकिन कई बार काम देर से पूरा होता है। यह जो देर लगती है, इस दौरान कौस्ट औफ कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाती है। अगर कौस्ट बढ़ जाती है तो क्या ऐस्टीमेट दोबारा रिवाईज नहीं करना पड़ता है या ऐसा नही होता है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः होने को तो पता नहीं क्या–क्या होता है। इनके पडौस में कांग्रेसी मैम्बर्ज बैठे हैं। इनसे पूछ लें कि क्या क्या होता है, सब पता लग जायेगा। (व्यवधान)

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय से मैं भी एक बात जानना चाहता हूं। अभी सड्कों की मुरम्मत की बातचीत चल रही है। उस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि सड्कों की मुरम्मत कराने का क्राइटेरिया क्या है? क्या यह सोचते हैं कि जो सड़कें पहले की बनी हुई हैं, उनकी पहले मुरम्मत करें या जो बाद की बनी हुई हैं उनकी मुरम्मत बाद में करें? क्या इस बारे में कोई क्राइटेरिया है कि कौन सी सड़क पहले बनेगी कौन सी बाद में बनेगी? क्या यह सही बात है कि जो सड़क 1980 में बनी है, उसकी तो मुरम्मत हो रही है लेकिन जो 1970–75 की बनी हुई थी, उसकी मुरम्मत नहीं की जा रही है? अगर यह बात– सही है तो क्या पुरानी बनी सड्कों की मुरम्मत की तरफ पहले ध्यान दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, स्पैशल रिपेयर के लिये हमारी जो रिक्वायरमैट है, वह 30 करोड़ रुपये की है।

हमें जो पैसा इस साल मिला है कि वह 1 करोड़ है। अब आप खुद ही अन्दाजा लगा ले कि कहां–कहां पर हम रिपेयर कर सकते हैं। कहां 30 करोड़ और क्हां 1 करोड़। (हंसी)इस एक करोड़ से जहां–जहां श्री भागी राम जी कहेंगे, वहां पर हम रिपेयर करवा देंगे 1

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने पहले ही शिकायत कर दी है कि बजट नहीं मिल रहा है। इस काम के लिये बजट उतना नहीं है, जितनी जरूरत है। वैसे तो यह एक सामान्य सी बात है लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं भी एक क्वैश्चन पूछ लूं।

Mr. Speaker : Chaudhri Mahendra Pratap Ji, I would request you that there should be no provocation in your supplementary.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः ऐसी कोई बात नहींहोगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा,। हरियाणा में कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां से सरकार को लाखों रुपये रोजाना आमदनी है विशेषकर मेरे हल्के में ऐसे क्षेत्र हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। यह आमदनी पहाड़ी माइनिंग से होती है। वहां पर जो सड़कें बनी हुई हैं, वे हैवी–व्हीकल्ज हजारों ट्रक चलने से जल्दी ही खराब हो जाती हैं। उनमें बड़े–बड़ा गढ्ढे पड़ चुके हैं। मैं मत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि ऐसी जगहों

की सड्कों को प्रायरिटी देकर रिपेयर करवायेगे, अगर किया जायेगा तो कब तक इनको पूरा किया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहव, इस साल हमें 18 करोड़ रुपया मिलने का अन्दाजा है और सड्कों पर करीब छः करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। मेरे साथी अन्दाजा लगा सकते हैं कि, हर कांस्टिचुएंसी में करीब छः लाख रुपया खर्च किया जा सकता है। छः लाख रुपए से जितनी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, वह की जाएगी।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, जहां से सरकार को लाखों रुपए मिलते हैं वहां की सड्कों का काम तो प्रायरिटी बेसिज पर चलाना चाहिए। क्या मन्त्री महोदय मेरी कास्टीचुएंसी में सड़क बनाने में प्रायरिटी देंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, जहां पर आठ और बारह टन के ट्रक चलसे चाहिए वहां पर अठारह टन की कैपेसिटी के ट्रक चला रहे हैं। इस तरह सड्कों का चौगुणा नुक्सान तो होगा ही।

श्री लछमन सिंह कम्बोजः स्पीकर साहब, 1982 में कुछ मैम्बर ऐसे थे जो कांग्रेस में नहीं गए थे, वे लोकदल में ही रहे। जो मैम्बर कांग्रेस में चले मए थे, उनकी कांस्टीचुऐंसीज में तो काम हुआ है लेकिन जो लोकदल मैं रहे उनकी कास्टीचुऐंसीज में कोई काम नही हुआ। क्या मन्त्री महोदय उन कास्टीचुऐंसीज में,

जिनमें पिछली सरकारें के समय काम नही हुआ, काम कराने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, जो कास्टिचुऐसीज नैग्लैक्टिड रही हैं और वहां काम नही हुआ, उनको पहले लिया जाएगा।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, भूना से उकलाना की एक सडक है। इस सड़क के पिछले नौ महीने में तीन बार ऐस्टीमेट तैयार किए गए हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। काम में डिले होने के कारण उसकी लागत वढ़ती जाती है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सड़क का काम विद इन टाईम पूरा कर दिया जाएगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः इस बारे में मैं इतना ही अब करना चाहूंगा कि जब श्री हरपाल सिंह के हल्के की बारी आएगी तो उसके ऐक्सरा अच्छी तरह से पढ़ लेंगे।

श्री सरदूल सिंहः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सफीदों से जींद रोड जो बहुत बड़ी सड़क है, उसको चौड़ा करने का कोई प्रोग्राम सरकार के विचाराधीन है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः इस पर विचार कर लेंगे।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि करनाल

जिले में खड़क से रौनक व खाचवा से खडक तक की सड़कें कब तक बना दी जाएंगी?

Mr. Speaker : It may not be possible for the Minister to reply to this question.

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, इसके लिये अलग से नोटिस चाहिये।

श्री योगेश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से वह जानना चाहता हूं कि 31 मार्च के बाद 17 जून तक कितनी सड्कों पर काम शुरू किया गया था और 17 जून के बाद अब तक कितनी सड्कों पर काम चल रहा है?

श्री ओम प्रकाश मानवः स्पीकर साहब, सारे हरियाण में इस वक्त इस तल की 20 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हैं। इसके लिये ये अलग से नाटिस दे, तब देख लेंगे।

श्री टेक चन्दः स्पीकर साहब, नरवाना से टोहाना रोड की हालत बहुत खस्ता है और पिछले दिनों सरकार की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया था कि इस सड़क को शीघ्र ही ठीक कर दिया जाएगा। दो तीन किलोमीटर का टुकड़ा था, उसको चौड़ा करने की बात थी। तो मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह काम कब तक हो जाएगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, चूकि पहले बजट में केवल 16 करोड़ का प्रोवीजन था और हम ने 25 करोड़ रुपये, की मांग की थी लेकिन यह प्रोवीजन घटकर सूखा पड़ने की वजह से 9 करोड हो गया 1 जो काम चल रहे हैं, पैसे की कमी के कारण ही वे सस्पैन्ड करने पड़े हैं। इस साल नैन साहब वाली सड़क के लिये विचार किया जाएगा।

श्री आत्मा राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, जैसे एक सडक 8 किलोमीटर की हो और उसका आधा भाग 4 किलोमीटर के करीब बन चुका हो और आधा भाग उपयोगिता पूरी न होने के कारण रह गया हो तो क्या मन्त्री महोदय आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि ऐसी सड़को को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह के कोई काम अधूरे पड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले उन कामों को पूरा करने की चेष्टा करेंगे?

तारांकित प्रश्न सख्या 414

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Drought Relief Measures in Mohindergarh District

***128. Shri Raghu Yadav and Shri Jai Narain Khundia :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the

hardships being faced by the drought affected people of District Mohindergarh; and

(b) if so, the details of the measures, if any, taken or proposed to be taken to mitigate the hardships of the aforesaid people togetherwith the expenditure incurred or likely to be incurred on the supply of foodgrains and fodder at subsidised rates, providing of drinking water and employment, and filling of ponds with water, separately?

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान):

(क)जी हां।

(ख)राज्य सरकार द्वारा किये गये या किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का बयोरा सदन के पटल पर रखा जाता है।

ब्योरा

जिला महेन्द्रगढ़ में सूखा से प्रभावित लोगों के लिए किए गए/ प्रस्तावित किए जा रहे राहत कार्यो का विवरण

(1)अनाज: सूखा राहत कार्यों में लगाये गये श्रमिकों को 155/– रुपये प्रति क्विंटल की को दर से सबसीडाईजड दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध किये जा रहे हैं। फिर भी आवश्यक वस्तुएं जैसा कि लेवी चीनी, आयातित चीनी, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल तथा आयातित– खाने योग्य तेल इत्यादि कन्ट्रोल दरों पर राशन कार्डों के विरुद्ध उचित मूल्यों की दुकानों पर उपलब्ध किए जा रहे हैं।

(2)चारा: पशु–मालिकों को चारा 50/– रुपये. प्रति क्विंटल की दर से तथा 40/– रुपये तक नगद सबसिडी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त वाहन तथा अन्य फुटकर खर्चे पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वहन किये जा रहे हैं। इस जिले के लिए 92.00 लाख रुपये की राशि चारा सबसिडी के लिए अलाट की गई है, जिसमें से 68.11 लाख रुपये की राशि अब तक खर्च की जा चुकी है।

(3)पीने का पानी: जिला महेन्द्रगढ़ मे 725 गांव हैं जिनमें से 713 गांव समस्या गांव हैं। दिनांक 29–2–88 तक पानी सप्लाई सुविधाएं 704 गांवों (703 समस्या और 1 गैर समस्या गांव)तक बढ़ा दी गई है और अन्य 21 गांवों में कार्य प्रगति पर चल रहा है। सभी 6 कस्बों में भी ट्यूबवैल/खुले कुओं के आधार पर पानी सप्लाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। टयूबवैलों की खुदाई व पानी के वाहन आदि पर हुए खर्चों पर अब तक 84 लाख रुपये की अलाटमेंट के विरुद्ध 80.33 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। इस जिला में कही पर भी पीने के पानी की समस्या बारे कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। (4)रोजगार उत्पत्तिः भूमिहीन श्रमिकों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गो के लोगों को रोजगार देने के लिए लेबर इन्टेंसिव प्रोजैक्टस चालू किए गए हैं। अब तक ऐसे कार्यो से 10,56,736 मैनडेज उत्पन्न किए गए हैं। 239.40 लाख रुपये की राशि रोजगार उत्पादन स्कीमों पर खर्च की जा चुकी है।

(5)तालाबों की भराई: विभिन्न गांवों में 241 तालाब भरे जा चुके हैं और जहां पर पर तालाब पुनः भरे जाने थे, उन्हें नहरी पानी से भरा गया।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, भानु इंडस्ट्रीज से सम्बन्धित जो सवाल था उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: वह पूछा नही, गया क्योंकि श्री रणजीत सिंह जिनका यह सवाल था, इस समय हाउस में नहीं हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, क्या मैं उगनी बीहाफ पर पूछ सकता हूं?

Mr. Speaker : No. I have not received any authorisation.

श्री मंगल सैन: मे अब इसके लिये रिक्वैस्ट कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं। The next question has already been put and answered.

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, अनाज बांटने, चारा उपलब्ध करवाने, पीने के पानी का प्रबन्ध करने रोजगार उपलब्ध कराने तथा पानी के तालाबों को भरने आदि का सभी प्रकार का प्रबन्ध तो किया गया है लेकिन क्या सरकार ने कभी इस दात का ध्यान रखा है कि जितनी लोगों को राहत दी गयी हैं, वास्तव में वे राहतें पूरी की पूरी, समय पर सम्बन्धित लोगों को मिली भी हैं कि

नही? मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा दी गई रियायतें या लाभ लोगों तक वास्तव में पहुंचे हैं या नहीं, इन सब चीजों को परखने के लिये क्या सरकारके पास कोई एजेन्सी है?

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, जो कुछ सदन को बताया गया है, यह सब कुछ हुआ है। इस बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, इसलिए जांच करने की आवश्यकता नही है।

श्री जय नारायण खुण्डियाः स्पीकर साहब, वैसे तो यह सवाल महेन्द्रगढ जिले का है लेकिन मैं आपके द्वारा मती जी से एक जनरल सवाल पूछना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लिए कितना चारा खरीदा गया, किसानों को बीज और खाद पर कितनी सबसिडी दी गई और कोडेमार दवाईयों पर कितना पैसा खर्च किया गया?

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, इन कामों पर सरकार के लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, सतनाली, बिगरोला, सुरहेटी और पथरान गांव महेन्द्रगढ़ जिले में है लेकिन ये गांव लौहारू हल्के में पड़ते हैं। इन गांवों में न तो इन्सानों के लिए और न ही मवेशियों के लिए पानी का प्रबंध है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मवेशियों के लिए पीने का पानी जोहड़ों में किन कारणों से नहीं डाला गया है? कूओं का पानी उस एरिया मे

लगभग 150 या 200 हाथ गहरा है इसलिए लोगों को पीने का पानी देने के लिए क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, 224 गांवों में 241 जोहड़ कैनाल द्वारा भर दिए गए हैं और गांवों के अन्दर जो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैट की तरफ से टूटिया लगाई हुई हैं, उनके साथ–साथ पक्की खाल बनाई गई हैं जिनके अन्दर पानी डाल कर मवेशियों को पिलाया जाता है। उन गांवों में कोई शिकायत नहीं है कि उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा।

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि 155 रुपए प्रति क्विटल के हिसाब से अनाज उपलब्ध कराया गया है। मैं मली जी से जानना चाहूंगा कि उन राशन के डिपुओं से और सस्ते राशन की दुकानों से, जनके बारे में पहले ह्वीं सदन के अन्दर काफी चर्चा हो चु की है, उनका क्या हाल है? इसके अलावा, जहां तक जोहड़ों में पानी भरने की बात है, इस बारे में मैं जानन चा हूंगा कि 25 अगस्त को नारनौल सब–डिवीजन में (शोर)

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : That is not the question. Sir, he should be restricted to ask the supplementary on this question only. He should not be allowed to make irrelevant comments.

Mr. Speaker : Please put a supplementary relevant to the question.

श्री रघु यादवः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार सवेदनहीन है या सवेदनशील? पिछले दिनों अखबारों हें छपा था कि जो चारा खरीदा गया है..... (शोर)

Shri Verender Singh : This is not the question.

Mr. Speaker : This is not the way to ask the supplementary. You only put a relevant supplementary question. Do not refer to the newspapers.

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, मैं बिछल ठीक पूछ रहा हूं। मैंने पूछा है कि क्या इस बारे मे इन्हें कोई शिकायत नहीं मिली, क्यौंकि इस बारे में पिछले दिनों अखबारों में छप था। (शोर)

श्री अध्यक्षः यादव साहब, आप फिर अखबार की खबर का जिकर कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। (शोर)

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंदी जी से जानना, चाहता हू कि क्या इनको ऐसी कोई शिकायत मिली कि मवेशियों के लिए जो चारा खरीदा गया है, वह गीता और बदबूदार था, जिसको मवेशी खा नहीं सकते थे, क्योंकि इस बारे में अखबारों के अन्दर छपा है, क्या इनको कोई शिकायत मिली है?

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, हमें आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार सवेंदनशील है, सवेंदनहीन नहीं है।

श्री जय नारायण खुण्डियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम, से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में मूखा राहत कार्य कम के अन्दर कितना चारा और कितना अनाज लोगो को बांटा जा चुका है?

श्री सूरज भानः चारे का ब्यौरा तो मेरे पास है लेकिन अनाज का ब्यौरा मेरे पास नही है। इन्होंने जो सवाल पूछा है इसका जवाब हम बाद में इनको जिला वाईज सर्कुलर भेज कर दे देंगे।

श्री रतन लाल कटारियाः क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को मुक्त चारा बांटने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है?

श्री सूरज भानः ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चौधरी तैयब हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ जिले में अभी तक कितने तालाबों को मवेशियों के लिए पानी से भरा जाना बाकी है? दूसरे यदि साथ ही साथ ये गुड़गांव जिले के बारे में भी बता दें तो इनकी मेहरबानी होगी।

श्री सूरज भानः ऐसे तालाब तो कई हो सकते हैं जिनको भरा गया है लेकिन महेन्द्रगढ़ के किसी गांव से हमें शिकायत नही मिली कि वहां पशुओं के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि फरीदाबाद जिले में किसी भी तालाब को पानी से नहीं भरा गया? वहां पर पलवल क्षेत्र के कुछ गांव व कुछ मेवात क्षेत्र को छोड़कर कर कही पर भी लोगों को सूखा राहत के तहत कोई सुविधा या सबसिडी वगैरा नहीं दी गई है। मैं इन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि खासकर तीन कान्स्टीच्यूसीज में तो पिछले कुछ दिनों से कोई राहत लोगों को नहीं दी गई। क्या यह तथ्य इनके नोटिस में है, अगर है तो क्या सरकार वहां के लोगों को कैश या काइंड में राहत देने की कोशिश करेगी? (विघ्न)

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्येक मैम्बरान से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी वे सप्लीमेन्टरी पूछें, सीधी सवाल से संबंधित पूछें। अब महेन्द्र प्रताप सिंह जी कह रहे है कि क्या यह सरकार के नोटिस में है कि वहां के लोगों को कोई राहत दी है या नही? ये सीधा सा यह सवाल पूछ सकते थे कि क्या फरीदाबाद जिले को सूखा राहत के तहत चारे पर कोई सबसिडी वगैरा दी गई है या नही। इनको या दूसरे साथियों को सीधी सप्लीमैन्टरी पूछनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप सीधा सवाल पूछें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि वहां पर किसानों को चोरे वगैरा पर कोई सबसिडी वगैरा दी गई है या नहीं। मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हू कि उन लोगों को व्यक्तिगत आधार पर सबसिडी राहत कैश एण्ड काइड पर कोई नहीं दी गई मैं जानना चाहता हूं कि अगर नहीं दी गई तो क्या सरकार यह राहत देने का विचार रखती है?

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत फरीदाबाद जिले को 5 लाख रुपये चारे वगैरा पर सबसिडी के लिए दिया गया था लेकिन वहां से पैसा वापस आ गया। वहां से हमें यह जबाब आया कि यहां पर सूखा के तहत पैसे की जरूरत नही है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि वहाँ पर भयंकर सूखा पडा है और लोग 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से चारा खरीद रहे हैं। वह सूखाग्रस्त जिला है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः महेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप मंत्री जी से चौम्बर में मिल लें और इन्हें अपनी कठिनाई बता दें। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mahender Partap Ji, this is not the

way. You know the procedure.

चौधरी तैयब हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेवात के एरिया के मवेशियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। (विध्न)

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। (विघ्न)

चौधरी तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, मुझे सिर्फ एक सप्लीमैन्टरी पूछ लेने दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। मेरी इजाजत के बगैर जो भी बोला जाये, वह रिकार्ड न किया जाये। Next question.

चौधरी तैयब हुसैनः .....

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः .....

Construction of Water Works in Village Naguran

***139. Shri Durga Dutt Atri :** Will the Minister for P.W.D. (Public Health) be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the construction of water works in village Naguran has been stopped; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the work for the construction thereof, is likely to be restarted and completed ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा): इस जल वितरण योजना का कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर, 1988 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, डीघरोता, बाढड़ा, ढालावास और नावा आदि गांवों में पानी बहुत गहरा है। वहां पर पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत है। क्या मली महोदय कोई जांच पड़ताल करके कार्यवाही करेंगे ताकि वहां की पानी की किल्लत दूर हो सके? दूसरे, क्या उनके पास 16 अक्तूबर को मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई ग्रिवैंसिज कमेटी की मीटिंग में ऐसी कोई शिकायत आयी है कि वहां पानी कि किल्लत है, अगर कोई शिकायत आयी है तो इस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर साहब, यह सवाल श्री दुर्गा दत्त अत्री जी का राजौन्द कास्टिचुऐंसी के नागुरा गांव की जलघर योजना के सम्बन्धित है लेकिन श्री हीरा नन्द जी हमारे वरिष्ठ सदस्य है और हमारे पड़ोसी भी हैं। यह बात ठीक है कि डीघरोता और नावा गांव में पानी की समस्या है। भूमि के नीचे का पानी बहुत अलारमिंग स्टेज तक चला गया है यानी सौ फुट नीचे तक चला गया है। पानी की समस्या को देखते हुए वहां पर एक अलग से ट्यूबवैल बोर करवाया गया है। उस ट्यूबवैल को जल्दी ही चालू करें देंगे।

जहां तक ग्रिवैसिज कमेटी की शिकायत की बात है, वहां पर हमारे विकास मंत्री श्री हुक्म सिंह जी जाते है। मुझे इस तरह की कोई शिकायत ग्रिवैंसिज कमेटी के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक इस योजना पर कितना धन खर्च हुआ है और कितना कार्य पूरा हुआ है? क्या इस बचे हुए धन से इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा?

श्री राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, नगुरा गांव की जलघर योजना 29 लाख 7 हजार की थी। इस पर अब तक साढ़े अठारह लाख रुपया खर्च हो चुका है और काम आगमनटेशन स्टेज पर है। टैकी बन चुकी है। दिसम्बर, 1988 तक इस स्कीम के तहत पानी देना शुरु कर देंगे।

श्री जगपाल सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, इन्टरनैशनल वाटर सप्लाई डिकेड मना रहे हैं जो सन 1990 में खत्म होगा। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस डिकेड के खत्म होने तक सभी गांवों और शहरों में पूरा पानी मिलना शुरु हो जाएगा?

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, चौधरी जगपाल सिंह इस विभाग में इंजीनियर–इन–चीफ रहे हैं। इनके द्वारा इस विभाग में काम हुआ था। हरियाणा में 6745 गांव हैं जिनमें से 5686 गांव प्रोब्लम विलेजिज के नाम से जाने जाते हैं यानी जिनमें पानी की व्यवस्था अभी करनी है। सन 1990 तक हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे।

चौधरी तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, मेवात एरिया की मन्त्री महोदय ने दौरा किया और उन्होंने महसूस भी किया है कि

वहां पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। इन गर्मियों में वहां पानी की किल्लत न हो, क्या मकी महोदय ऐसा कोई प्रबन्ध करेंगे?

श्री राम विलास शर्माः तैयब हुसैन जी ने ठीक फरमाया है। तीन जिले ऐसे हैं जहां पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। भूमि पर नदियों के जल की काफी कमी आयी है। खासतौर पर महेन्द्रगढ़, भिवानी और मेवात के इलाके में पानी की कमी आयी है। इस समस्या को देखते हुए सूखा राहत के तहत इस फाइनैंशियल ईयर में 274 ट्यूबवैल्ज बोर किए गए हैं। मेवात की तरफ भी विशेष ध्यान दे रहे हैं।

10.00 बजे

श्री हरनाम सिंहः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रौब्लम विलेज निर्धारित करने का क्राईटेरिया क्या है और मेरे हल्के शाहबाद में ऐसे कितने गाव हैं?

श्री अध्यक्षः ये शाहबाद में गांवों की संख्या कैसे बता सकते हैं, सवाल तो नगूरा से संबंधित है।

श्री राम विलास शर्माः इस बारे में डब्लयू०एच०ओ० ने कुछ शर्तें रखी हुई हैं। उनकी पहली शर्त यह है कि जिस गाव मे पानी 50 फुट से ज्यादा गहरा चला जाए, वह एरिया दूसरी शर्त यह है कि उस गांव के एक मील तक के एरिया में पीने के पानी की कोई व्यवस्था न हो और तीसरी शर्त यह है कि उस गांव का

पानी ब्रैकिश/सेलाईन हो यानी जहां के पानी में फलोराईड ज्यादा हो। पानी में जीवाणु हों और खनिज ज्यादा हों, क्योंकि ऐसा पानी पीने के लायक नहीं होता। पानी को टैस्ट करवाना पड़ता है और यदि पानी पीने लायक न हो तो उस गांव को प्रौब्लम विलेज घोषित किया जाता है।

डा० बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने देहातों में 1990 तक हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने के बारे में कहा है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सारे शहरों में और शहरों की बस्तियों में 199० तक पीने का पानी उपलन्ध करवाने का आश्वासन देंगे?

श्री राम विलास शर्माः डा० बृज मोहन जी इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में 75 छोटे–बड़े शहर हैं जो ए बी और सी श्रेणियों में बांटे हुए हैं। सभी नगरों और कस्बो में पानी की व्यवस्था है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, कैथल में कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम 1982 से अधर में लटक रही है जिसकी फाईल तब से सैक्रटेरियेट में चक्कर लगा रही है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह फाईल सैक्रेटेरियेट में किस लेबल पर अटकी हुई है और क्या अपने मन्त्रीत्व काल में ये इस स्कीम को पूरा करेंगे?

श्री राम विलास शर्माः फाईलों के चक्कर कटवाने वाली सरकार तो जा. चुकी है। कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम के लिए फण्डज एलोकेट कर दिए गए हैं और जगह एक्वायर की जा रही है।

श्री भगवान सहाय रावतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूगा कि जिस प्रकार शहरों में घर–घर पानी के कनैक्शन्ज दिए हुए हैं, क्या उसी प्रकार गांवों में भी घर–घर में टूटियों के लगाने की कोई स्कीम विचाराधीन है, यदि है तो यह कब तक शुरु होगी और प्रारम्भ में कितने गांवों मे यह स्कीम शुरु होगी?

श्री राम बिलास शर्माः घर घर में टूटियां लगाने की मांग बड़े–बड़े गांवों से आती है। वे मांग करते हैं कि घरों में अलग से कनैक्शन दिए जाएं। इसके लिए एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देखना पड़ता तूँ और दूसरे गांव में पानी की निकासी का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। जब तक पानी की निकासी का इन्तजाम नही होगा तब तक ऐसा कोई प्रावधान नही हो सकता।

श्री कुन्दन लाल भाटियाः फरीदाबाद में पीने के पानी की भारी समस्या है। क्या मन्त्री महोदय इस समस्या को हल करेंगे?

श्री राम विलास शर्माः इस समय ऐसी कोई शिकायत मेरी जानकारी में नहीं है कि फरीदाबाद में पानी की कमी है। लेकिन मैं श्री भाटिया की जानकारी के लिए उन्हें बताना चाहूंगा

कि 20 करोड़ रुपए की एक योजना, हुड्डा और फरीदाबाद काम्पलैक्स दोनों ने मिल कर तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ गैलन पानी यमुना नदी में ट्यूबवैल लगा कर सप्लाई किया जाएगा। दस लाख रुपए इस योजना के लिए दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि बहुत से गांवों में बैटरी पोस्ट एक जगह लगी हुई है और दूसरे एरियाज में वाटर सप्लाई के लिए कई जगहों पर टूटिया नहीं लगी हुई जिस कारण सारे गांव को पानी नहीं मिलता? एक–दो गांवों की वाटर –सप्लाई को दूसरे गांव के लिए रबड़ के पाईप से जोड़ा हुआ है। कई बार यह रबड के पाईप टूट जाते हैं और महीनों तक इनकी मुरम्मत नही होती जिस कारण पानी की सप्लाई कई–कई महीने तक रुकी रहती है। में मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए ये क्या पग उठाने जा रहे हैं?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष जी, अगर कि सी गाव की कोई विशेष समस्या हमारे नोटिस में लाई जाती है तो हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं। कई बार पी०वी०सी० पाइप लीक हो जाती है, उसकी सूचना मिलते ही हम कार्यवाही करते हैं। अगर इनकी कोई विशेष समस्या हो तों बताएं।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूगा कि सोनीपत शहर को वाटर सप्लाई देने के लिए मुरथल गांव में रिंग बोर किए गए हैं। रिंग बोर करने की वजह से गांव के नलकूप ड्राई हो गए है, क्या ऐसे गांवों को भी वाटर की सप्लाई की जाएगी?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष जी, इस बारे में हमारे पास कोई विधिवत मांग नहीं आई है। अगर डा० साहब कोई ऐसी वान बताएंगे तो जरूर विचार करेंगे।

श्री भाग मलः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की कोशिश की जा रही है लेकिन फिर भी बिजली रैगुलर नहीं मिलती। जहां पर ट्यूबवैलज लगे हुए हैं, वहां बिजली रैगुलर न मिलने के कारण कई कई दिनों तक पानी नही मिलता। क्या वहां जैनरेटर सैट लगा कर या कोई और प्रविधान करके लोगों को रैगुलर पानी की सप्लाई करने का विचार है?

श्री राम विलास शर्माः अध्यक्ष जी, बिजली की समस्या अब नही है, पहले कुछ गांवों में थी। जव समस्या थी और पानी की ज्यादा तंगी थी तो वहां हमने जैनरेटर सैट भी लगाए हैं।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, मुरथल गांव की तरफ से रैजोल्यूशन आया हुआ है और एक एकड़ जमीन भी एक्वायर कर ली गई है, अब वहां वाटर सप्लाई स्कीम चालू करने के लिए आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष जी, इसके बारे में तो अलग से नोटिस चाहिए।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्यूएंसी में ढूडिया वाली वाटर सप्लाई स्कीम से 13 गांवों को पानी दिया जाता है। जैसे डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया था कि पाइप लीक हो जाते हैं या जा भेड बकरियां चराने वाले लोग हैं, वे पानी पीने के लिए उन पाइप्स को तोड़ देते हैं–। इस वजह से कई कई दिन तक वहां पानी नहीं जाता। तो क्या इन पाइप्स की जगह पर लोहे के या कोई और पाइप लगाने का विचार है?

श्री राम विलास शर्माः यह सवाल तो नगूरा से संबंधित था लेकिन ये सिरसा में पहुंच गए। सिरसा में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, वैसे वाटर वर्कस सभी जगह लगे हुए हैं। सभी एम०एल०एज० की तरफ से यह शिकायत रहती है कि पहले से जो वाटर वर्कस लगे हुए हैं, उनके जरिए पानी की कम सप्लाई होती है क्योंकि एक स्कीम के साथ 4– 5 गांवों के ग्रुप बने हुए हैं। कई जगह इन स्कीमों की एक्स– पैन्शन हो रही है और कई जगहों पर नए वाटर वर्कस बन रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी परपोजल सरकार के विचाराधीन है–यानी नए वाटर वर्कस बनाने की या पुरानों की एक्सपैन्शन करने की?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, भाई रणजीत सिंह को मैं बताना चाहता हूं कि 6745 गांवों में से 5546 गांवों को तय किया है कि इनमें पानी की जरूरत है और इनमें से 4682 गांवों में हम फरवरी, 1988 तक पानी दे चुके हैं। बाकी जो 864 गांव बचते हैं, इनके लिए हमारी योजना है कि 1990 तक पानी देने का प्रबन्ध कर देंगे।

श्री टेक चन्दः स्पीकर साहब, पिछली सरकार के समय विभाग द्वारा नरवाना हल्के में कुछ गांवों में स्टैंड पोस्ट के नाम से कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने घरों में नाजायज कनैक्शन लगा लिए। उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राम विलास शर्माः अध्यक्ष जी, वैसे यह हमारी नीति नही है, घरों में कनैक्शन हम नही देते, परन्तु कुछ जगहों पर लोगों ने असंवैधानिक तौर पुर इस तरह का साहस किया है। हम उनको नोटिस दे रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्य– वाही कर रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि गांव के लिए जो स्टैडर्ड निश्चित है, वह 10 गैलन पर कैपिटा पर डे का है। क्या वहां पर पूरा पानी मिल रहा हैय अगर कम है तो क्यों?

श्री राम विलास शर्माः अध्यक्ष जी, 1968 से पहले जो योजनाएं बनी, वह गांव के लिए 5 गैलन और शहरों के लिए 30

गैलन की थीं। उसके बाद जो योजनाएं बनी हैं, वह गांव के लिए 10 और शहरों के लिए 40 गैलन की बनी हैं। कुछ गांवों में हम 10 गैलन, जो स्टैडर्ड है, पानी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि पानी की पर्याप्त क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल. नहीं है इसीलिए 10 गैलन से कम पानी हम गांव में दे रहे हैं।

Inclusion of Gohana Sub-Division into District Rohtak

***179. Chaudhri Kishan Singh Sangwan :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to include Gohana sub-division into district. Rohtak; if so, the time by which such a proposal is likely to materialise ?

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान): जी नहीं।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, इस बात को मैं थोडा कलैरिफाई करना चाहूंगा। एक रीआर्गेनाईजेशन कमेटी बनी हुई है। उसकी सिटिंग शुरु होने वाली है। वह सारे हरियाणा के बारे में विचार करेगी। सांगवान साहब ने प्रीमैच्योर सवाल पूछ लिया है। वह कमेटी जो बनी हुई है, वह यह सब देख लेगी।

Mr. Speaker : Next question is in the name of Shri Satbir Singh Kadian, who is not present but he has given the authority to Shri Sangwan to put this question. Shri Sangwan may, therefore, put the question.

Construction of Syphons/Bridges over Minor No. 1—R

958. Chaudhri Satbir Singh Kadian: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) whether Minor No. 1-R running through villages Brahman Majra, Kalkhan, Jondhan Khurd, Israna and Shahpur etc. of Tehsil Panipat, District Karnal has been completed:

(b) if so, whether the total quantum of water required for irrigation is released in the said Minor; if not. the reasons thereof;

(c) whether all the syphons/Bridges to be constructed on the said minor have been completed, if not, the number thereof togetherwith the reasons therefor; and

(d) the time by which the remaining syphons/Bridges are likely to be completed ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क)नहीं।

(खं)प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग)नहीं। एक पक्का सडक–क्रासिंग और दो जल निकास साईफन का अभी निर्माण होना है। लोगों की मांग के कारण बार–बार अलाइनमैंट में परिवर्तन होने से ये कार्य पूरे नहीं हो सके।

(घ)वर्ष 1988– 89 में।

चौधरी किशन सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हू कि जो पुल और साईफन अभी तक नहीं बने हैं, वह कब तक बना दिए जाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह माईनर 1984 में शरू हुई थी। स्पीकर साहब, पता नहीं किन कारणों से पिछली सरकार ने बारे–बार इसकी एलाइनमेंट चेंज की है। चूंकि काम शुरू हो चुका है इसलिए अब इसको पूरा करना ही पड़ेगा और हम पूरा करेंगे। मैं आपके नोटिस में एक बात अवश्य लाना चाहुंगा कि इस माईनर से ओरिजनली जो रकबा इरीगेट होना था, वह केवल 413 एकड है। टोटल एरिया जो अब इसको इरीगेट करना है, वह 4802 एकड़ है। इस टोटल 4802 एकड में से अगर 413 एकड हम घटा दें तो बाकी का रकबा जो रह जाता है वह दूसरी नहरों से इरीगेट हो रहा है, उसको उन नहरों से तोड़ कर इस माईनर में जोड़ा जाएगा। पता नहीं क्या वजह थी कि गोहाना डिस्ट्रिव्यूटरी का 1573 एकड़ रकबा, ज्वाला माईनर का 360 एकड़ रकवा, चिडाना माईनर का 1195 एकड़ रकबा, इसराना डिस्ट्रिव्यूटरी का 1388 एकड़ रकबा और नौलथा माईनर का 286 एकड रकबा इसमें लाया गया है। अब इतना रकबा वहां से शिफ्ट होकर इस माईनर पर आएगा। इस एरिया को बहुत अच्छी तरह से पानी लग रहा है। 21 लाख रुपए की यह स्कीम बनी थी। किस कसीड़ेशन से बनाई गयी, इस बारे में पुछ नहीं कहा जा सकता। अब यह स्कीम 1988–89 में मुकम्मल कर दी जाएगी। जो साईफन है वह भी और

ब्रिज एक तरफ का जो रह रहा है, वह भी कम्पलीट कर दिया जाएगा।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि पता नहीं बार–बार अलाइनमैंट क्यों चेंज की गई। यह बात ठीक है कि इनको पता नही है। क्या मन्त्री महोदय फाइलों को पढ़कर, कागजों को देखकर और अफसरों से पूछकर बता सकते हैं कि उनके सामने अलाइनमैंट चेंज करने के लिए कोई पोलिटिकल प्रैशर था या कोई और कसीड्रेशन था जिसकी वजह से बार–बार अलाइनमैंट चेंज की गई?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहबः डा० साहब अनुभवी हैं। साफ नजर आता है कि पौलिटीकल प्रैशर से ऐसा हुआ है।

Opening of PHCs and upgrading of Dispensary/Civil Hospital in Rohat Constituency

***162. Shri Mohinder :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the names of the villages, if any, where new Primary Health Centres are proposed to be opened in Rohat Constituency of Distt. Sonipat; and

(b) whether any Dispensary/Civil Hospital in Rohm Constituency of District Sonipat, is proposed to be upgraded ; if so, the time by which such upgradation is likely to be done ?

स्वास्थय तथा आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क)रोहट विधान सभा क्षेत्र में एक ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख)नहीं।

श्री मोहिन्द्रः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रूरल डिस्पैसंरी से पी० एच० सी० बनाने के लिये किन आधारभूत चीजों पर ध्यान दिया जाता है?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, सेन्टर का जो नार्म है, उसके मुताबिक पांच हजार की आबादी पर हम एक उप–केन्द्र खोलते हैं। 25– 30 हजार की आबादी पर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलते हैं और 120 लाख की आबादी पर एक कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर खोलते ऐं। अगर रोहट में किसी जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाना चाहते हैं तो माननीय सदस्य जहां पर पंचायत की जगह ले देंगे, वहां पर खोल देंगे।

श्री मोहिन्द्रः स्पीकर साहब, रोहट से सम्बन्धित प्रश्न है। प्रायरू देखा गया है कि जो डाक्टर्ज देहात में डिप्यूट किए जाते हैं, वे देहात में रिहायश का प्रबन्ध न होने के कारण वहां नहीं ठहरते। क्या मन्त्री महोदया देहातों में डाक्टर्ज की रिहायश का प्रबन्ध करने की कृपा करेंगी?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, 1977 में जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार आई थी तब हमने एक नई नीति अपनाई थी कि जो भी नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वनाया जाएगा

वहां रिहायशी मकान पहले बनाए जाएंगे। जो पुराने स्वास्थ्य केन्द्र है या रूरल डिस्पैन्सरीज हैं और जिनको अपग्रेड किया गया है, वहां रिहायश की दिक्कत आ रही है। हम बजट प्रोवीजन के अनुसार धीरे धीरे रिहायशी मकान बना रहे हैं ताकि डाक्टर्ज को दिक्कत न हो।

श्री भगवान सहाय रावतः मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या स्कूलों की तरह अस्पताल भी हैं जो हरियाणा प्रान्त में प्राईवेट भवनों में चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो ऐसे कितने अस्पताल हैं।

श्रीमती कमला वर्माः इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री मनी रामः स्पीकर साहब, चौटाला सिविल हस्पताल में डाक्टर्ज के रहने की कोई समस्या नहीं है। वहां तीन चार डाक्टर गए हैं लेकिन के छूट्टी लेकर आ गए। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, इस बारे में थोड़ी कठिनाई आ पी है कि कुछ डाक्टर्ज, इंटीरयर के गांवों में नही जाते। हमने इसके लिए काफी कोशिश की है। 6 मास में 309 डाक्टर्ज गांव मे नियुक्त किये जिन में से केवल 135 डाक्टर्ज ने ड्यूटी ज्वायन की है। इसके लिये कोई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी कि जिस डाक्टर को नौकरी दें, वह गांव में भी अवश्य जाए।

श्री आत्मा राम गोदाराः क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि सिविल अस्पताल, प्राईमरी हैल्थ सैन्टर और रूरल डिस्पैन्सरी के लिए एक साल में फ्री दवाइयां देने के लिये कितना–कितना पैसा दिया जाता है?

श्रीमती कमला वर्माः इस के लिए पासिबल तो है लेकिन यह बताना ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, सारे हरियाणा में औषधियों लिए केवल अढाई करोड़ रुपये का बजट है और एक आदमी के हिस्से साल का केवल 6 रुपय 40 पैसे खर्चा बैठता है।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि अगर किसी गांव की पंचायत अपनी तरफ से जमीन देती है और उसके ऊपर स्वयं ही भवन निर्माण कर देती है तो क्या ऐसे गांव में सरकार द्वारा तुरन्त स्वास्थ्य केन्द्र को हर लिहाज से प्राथमिकता दी जाएगी?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर सर, यह सरकार की नीति है कि अगर किसी गांव में पंचायत भवन बनाकर देती है तो उसको हम हर लिहाज से प्रायरिटी देते हैं।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदया ने सारे हरियाणा के लिए अढाई करोड़ रुपये का बजट का जिकर किया है और साथ यह भी बताया है कि प्रति व्यक्ति 6 रुपये 40 पैसे दवाइयों का खर्चा आता है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा की एक करोड़ 40 लाख की आबादी में

प्रति व्यक्ति के हिस्से 6 रुपये 40 पैसे दवाइयों का खर्चा कैसे बता दिया है? जरा इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें। मेरी समझ में उनकी यह बात नहीं आयी।

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर सर, इस बात को समझाने की जरूरत भी नहीं है। हरियाणा की सारी आबादी तो बीमार नही है हम अधिक बीमार होने ही नही देते। अब हमारी सरकार आ गयी है। हम बजट को बढ़ाकर लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने सहायक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये बताया कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या नियम बना रखे हैं, क्या–क्या क्रायटेरिया फिक्स कर रखा है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि औरंगाबाद के अन्दर 1978 में पिछली सरकार द्वारा हस्पताल बनाने के लिये 16 लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है और उसके लिये साढ़े सात एकड़ भूमि भी एकवायर हो चुकी है लेकिन इस हस्पताल का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया हे। क्या सरकार इस काम कों जल्दी करवाने की कृपा करेगी ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है वह दूर की जा सके?

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मैं पिछली सरकार की जिम्मेवारी नही ले सकती। अगर आनरेबल मैम्बर इसके लिये सैपरेट नोटिस देंगे तो मैं इंफर्मेशन दे दूंगी।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: आदरणीय स्पीकर साहब, कैथल के अन्दर 50 बैड्ज के हस्पताल की बजाय 100 बैड्ज का हस्पताल मंजूर हो चुका है और डाक्टर्ज भी वहां इसी हिसाब से नियुक्त किये गये है लेकिन बिल्डिंग अभी भी 50 बैड्ज की ही है। एक एक बैड पर दो दो मरीज लिटाये जाते हैं जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि कब तक इस हस्पताल की बिल्डिंग को 100 बैड्ज की बिल्डिंग में कंवर्ट कर दिया जाएगा?

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मेरे भाई ने जो सवाल किया है उसकी मैं प्रशंसा करती हू। अवश्य ही घन उपलब्धि होने पर कैथल के अन्दर इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

Opening of Subsidiary/Public/Community Health Centres in Gannaur Tehsil

***192. Shri Ved Singh Malik :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Subsidiary Health Centres, Public/ Community Health Centres in any of the villages in Tehsil Gannaur of District So nipat; and

(b) if so, the time by which the above said centres are likely to be opened ?

स्वास्थय तथा आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क) (1)सहायक स्वास्थ्य केन्द्र नही

(2)सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जी हां,

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना है।

श्री देव सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि सोनीपत जिले की तहसील गन्नौर के किसी गांव में भी इस तरह का कम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर खोलने पर सरकार विचार कर रही है?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, पहले तहसील गन्नौर के लिये सोचा गया था लेकिन वहां पर जमीन नही थी। तहसील गन्नौर में एक गांव पुरखास है। वहां पर 6 एकड़ के लगभग जमीन भी है और 35 हजार फुट का कवर्ड एरिया भी बन चुका है। अगर माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे तो वहां पर सामुदायिक हैल्थ सैन्टर खोलने का हमारा विचार है।

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय पुरखास गांव गये भी थे। उन्होंने वायदा किया

था कि इस को जल्द से जल्द बना दिया जाएगा लेकिन अब पोजीशन यह है कि हस्पताल नाम की कोई बात ही नही है और न ही कोई डाक्टर वहां पर पहुंचा है। मैं मन्त्री महोदया की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि उस गांव के लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री भी सरकार के नाम करवा दी है। मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि अब यह हस्पताल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, वहां पर रिहायशी भवन नहीं है। अगर सदस्य महोदय इन्तजाम कर दें तो बेहतर होगा, नहीं तो हमें रिहायशी भवन बनाने पड़ेंगे क्योंकि रिहायश के बिना डाक्टर वहां पर टिकते नहीं हैं। हम शीघ्र ही भवन निर्माण का ध्यान रखेंगे।

Setting up of Additioual Electricity Sub-Stations

***213. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up additional electricity 33 KV Sub-Stations in the State; if so, the criteria thereof; and

(b) whether any such stations are proposed to be opened between Palwal-Hodel and Hodel-Hathin; if so, the names of places where these are likely to be set up ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क)हां। एक नए ग्रिड सब–स्टेशन के लिए माप दण्ड ये हैं–

पूर्वानुमानित लोड डिमान्डः

बिजली की किस्मः

नजदीकी ग्रिड सब स्टेशन से दूरी।

(ख)इस क्षेत्र में कोई नया 33 के० वी० सब स्टेशन निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी पलवल में एक 220 के० वी० सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है तथा रिहन्ड से बिजली प्राप्त करने के लिए मंडकोला, हथीन, चन्दहट तथा हसनपुर के सब स्टेशनों को वर्तमान 33 के० वी० से 66 के० वी० के स्तर तक वनाया जाना प्रस्तावित है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, अभी क्राइटेरिया मंत्री जी ने बताया है कि एक नए ग्रिड सबस्टेशन के लिये माप दण्ड ये हैं–पूर्वानुमानित लोड डिमांड, बिजली की किस्म, नजदीकी सबस्टेशन से दूरी। इन तीनौं क्राईटेरियों को होडल और पलवल के बीच के कई ऐसे स्थान हैं जो इन्हें पूरा करते है, हथीन और होडल के बीच में भी कई ऐसे स्थान हैं जो ये तनों क्राइटेरिया पूरे करते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो स्थान इस क्राईटेरिया को पूरी करता है, क्या वहां पर 33 के०वी० का सबस्टेशन खोलने के बारे में सरकार विचार करेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, पलवल और होडल के बीच के इलाके के लिए इस बात में कोई शुबह नहीं कि वहा पर इस समय बिजली की बहुत दिक्कत है। पलवल में 220 के०वी० का सब–स्टेशन बना कर और उसके आस पास जो मैंने चार 33 केह वी० के सब स्टेशन बताए है, उनको अपग्रेड करके 66 के०वी० का बनाया जाना प्रस्तावित है ताकि उस इसके में हमेशा के लिये बिजली की दिक्कत मिट जाए। नए 33 के० वी० के सब–स्टेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन चारों 33 के० वी० के सबस्टेशंज को अपग्रेड करने से उस इलाके में बिजली की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सारे हरियाणा में ऐसे कितने 33 केः वी० सबस्टेशन हैं जो नए बनाए जाने हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

Shortage of Drinking Water in Karnal City

***236. Seth Lachhman** Dass Bajaj : Will the Minister for P.W.D. (Public Health) be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is shortage of drinking wa ter due to failure of rains and going down of water table in Karnal City at present; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be

taken to remove the said shortage ?

जन स्वास्थय मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा):

(क)नहीं।

(ख)उपरोक्त (क)भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहव, इस बात में कोई शक नही कि हरियाणा के अन्दर पीने के पानी का काफी अच्छा इन्तजाम है लेकिन मेरे हल्के में कई गांव ऐसे हैं जिनमें कुओं का पानी सूख गया है और पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हैकि मेरे हल्के में तीन चार गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की बहुत कमी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर पीने के पानी का इन्तजाम किया जाएगा?

श्री राम विलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, करनाल, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र हरियाणा के अन्दर तीन ऐ से नगर हैं जिनके अन्दर लोगों को पर कैपिटा के हिसाब से 40 गेलन तक पीने का पानी दिया जा रहा है और इसको हम बहुत अच्छी स्थिति मानते हैं। माननीय सदस्य के इलाके में कुछ जगहें ऐसी हैं जो ऊंचाई पर हैं इसलिए वहां पर पानी कम पहुंचता है क्योंकि प्रैशर कम होता है। उन जगहों के लिए अलग से तीन ट्यूवैल्ज लगाए

गए है इसलिए आने वाले कुछ दिनो में इनकी दिक्कत दूर हो जाएगी।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि करनाल में पर–कैपिटा के हिसाब से 40 गेलन पानी देना क्या स्टैन्डर्ड के मुताबिक सही है या कम है?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, स्टैन्डर्ड के हिसाब से सही है।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो तीन ट्यूबवैल्ज लगाने के बारे में बताया है, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि वे कब तक तैयार हो जाएंगे?

श्री राम विलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, वे ट्यूबवैल्ज बोर हो गए हैं, सिंचाई विभाग को इस हफ्ते के आखिर, तक कनैक्शन मिल जाएगा और वे पानी देना चालू कर देंगे।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, गांवों के अन्दर पीने का पानी 10 गेलन पर कैपिंटा के हिसाब से दिया जाता है और शहरों के अन्दर 40 गेलन पर कैपिटा के हिसाब से दिया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शहरों के लोग पानी ज्यादा पीते हैं या नहाते ज्यादा हैं, इसलिए उनको ज्यादा पानी दिया जाता है और गांव तालों कों कम दिया जाता है?

श्री राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसके नार्म्ज तय होते हैं उसके हिसाब से पानी दिया जाता है। शहरों के अन्दर पानी की निकासी की भी जरूरत पड़ती है। यह एक नैशनल स्टैन्डर्ड है।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकिंत प्रश्न का लिखित उत्तर

Purchase of Pesticide

***513. Shri Vasu Dev Sharma and Shri Hira Nand Arya** : Will the Minister of State for Agriculture be pleased to state—

(a) the total quantity of Pesticide/Aldrine, if any, purchased during the year 1987-88 (upto 15-3-88) togetherwith the cost thereof and the mode of its purchase; and

(b) whether any sample of the said Pesticide was got tested from the Laboratory; if so, the result thereof ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह): (क)और (ख)विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भाग (क)विशिष्ट अवधि के लिये खरीदी गई कीटनाशक/ एलड्रिन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

	कीटनाशकों की मात्रा	मूल्य (रुपये)	खरीद करने की विधि
(क)			
1	एल्ड्रिन 30 21,550 ई० सी० (लीटर)	12,85,181.50	कृषि विभाग के अनुरोध पर हैफेड व हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा खरीद किया गया। हैफेड ने लघु कालीन टेन्डर समाचार पदों के माध्यम से मांगे व न्यूनतम मूल्यों पर खरीद किया। हरियाणा कृषि उद्योग निगम ने हैफेड द्वारा अनुमोदित मूल्य व स्त्रोत अपनाया।
2.	फासफैमिडान 85 9,500 एल०एल० (लीटर)	14,59,000.00	निदेशक, पूर्ति एवं निपटान ने समाचार पगे मै टैडंर दिए तथा मूल्य व स्त्रोत का उच्च

			स्तरीय कमेटी से अनुमोदन करवाया। कृषि विभाग की सलाह पर अनुमोदित मूल्य पर इफको, कृभको, हैफेड व हरियाणा कृषि उद्योग निगम ने खरीद किया।
3.	आईसोप्रोट्रोन 89.50 (मि० टन)	1, 25,73,500.00	जैसा कि ऊपर क्रमांक 2 पर दियां गया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा बीज विकास निगम ने भी कुछ मात्रा उपरोक्त संस्थाओं के साथ खरीद की। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम ने इसके अतिरिक्त 24 मि० टन स्वयं भी खरीद किया।

भाग (ख)टैस्ट किये गये सैम्पलों और उनके परिणाम का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

	कीटनाशकों का नाम	नमूनों की संख्या जिन का विश्लेषण करवाया गया		विश्लेषण करवाये गए नमूनों के परिणाम			
		डिलीवरी से पूर्व	डिलीवरी के पश्चात	पास	फेल	पास	फेल
1	एल्ड्रिन 30 ई०सी०	11	39	11	-	5	34
2	फासफैमिडान 85 एस० एल०	10	3	10	-	3	-
3	आईसोप्रोटूरोन	38	36	38		21	15

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मैंने 2–3 मोशज आपकी सेवा में दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी उन मोशज का क्या हुआ? मेरी एक मोशन तो वकीलों द्वारा हड़ताल किए जाने के बारे में थी। आजकल जुडिशियरी का काम स्टैंडस्टील हो गया है और

सारा काम रुका पड़ा है। यह बहुत लोक महत्व का विषय है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमैंट इस बारे में अपनी राय स्पष्ट करे।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, यह मोशन तो मैंने डिस–अलाउ कर दी है।

Shri Mangal Sein : Speaker Sir, **I** am sorry to say that you have disallowed the Calling Attention Motion, which concerned the persons of your profession. दूसरी मेरी मोशन लिबरटी शूज फैक्टरी, करनाल में लेबर्ज द्वारा किए गए मरण–व्रत के बारे में थी।

Mr. Speaker : That I have sent to the Government for comments.

श्री मंगल सैनः तीसरी मेरी मोशन रूल 84 के तहत सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के संबंध में डिसक्शन करने के बारे में थी। उसका करा बना–है?

श्री अध्यक्षः डा० साहब, उसे डिस–अलाउ किए हुए तो काफी देर हो चुकी है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस कमीशन की रिपोर्ट केबारे में होम मिनिस्टर के व्यान अखबारों में छपे है। इसलिए मैंने इस संबंध में दोबारा आपको लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्षः आपकी यह मोशन भी चूकि सेम ग्राउंडज पर थी, इसलिये वह डिस– अलाउ कर दी गई है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है। Sir, it was not on the same grounds. स्पीकर साहब, रूल 84 में यह लिखा है कि अगर कोई मिनिस्टर स्टेटमैंट दे तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। If you kindly allow me, I can read out Rule 84.

श्री अध्यक्षः डा० साहब, हमारे पास गवर्नमैंट से जो कुमैट्स आए हैं उनमें लिखा है कि सी० एम० साहब ने कोई स्टेटमैंट नहीं दी है।

श्री मगल सैनः स्पीकर साहब, पंजाब केसरी अखबार के अन्दर सरकारिया कमीशन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में होम डिपार्टमैंट के प्रवक्ता का एक व्यान छपा है। इसलिए मैंने रूल 84 के तहत इस पर चर्चा की मांग की है। आप कहें तो मैं इसे पढ़ देता हूं।

Mr. Speaker : Doctor Sahib. that I have disallowed. That matter is closed now.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं तो रूल 84 को इसलिए दोबारा पढ़ना चाहता हू कि शायद आप मेरे प्वायंट पर राजी हो जाएं।

श्री अध्यक्षः रूल मैंने पढ़ रखा है। अब आप कितनी ही कोशिश करें, इसका मेरे ऊपर कोई असर नही होगा। आप कृपया बैठ जाये।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हमारी भी एक काल अटैन्शान मोशन 15 मार्च, 1988 को भारत् बन्द में सम्मिलित होने के लिए आ रहे लोगों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के सम्बन्ध में थी। उस का क्या हुआ?

Mr. Speaker : Comrade Sahib, that has been admitted for 29th March.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

जिला भिवानी तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सुंडी द्वारा चने की फसल क्षतिग्रस्त होने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of Call Attention Motion No, 14 from Shri Hira Nand Arya regarding damage of crops of gram by Sundi in district Bhiwani and its adjoining areas. I admit it. Shri Hira Nand Arya may read his Notice and thereafter the Minister concerned may make his statement.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि भयंकर कीड़े (सुंडी)ने चने की वर्तमान फसल को नष्ट कर दिया है जिसके कारण जिला भिवानी तथा उसके आसपास के चने की

बिजाई वाले क्षेके के किसानों में बहुत चिन्ता व्याप्त है। इस्लिये, सरकार इस भयंकर खतरे से किसानों को बचाने के लिये शीघ्र पग उठाये तथा इस बारे मैं की गई कार्यवाही से सदन को सूचित करे।

स्पीकर साहब इसके साथ ही मैं इन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि अभी फसल की पकाई का सीजन चल रहा है इसलिये अगर वक्त रहते इस बीमारी को रोकने के लिए कार्यवाही नही की गई तो सारी फसल बर्बाद हो सकती है। मैं चाहता हूं कि सरकार तुरंत कार्यवाही करके इस ओर उचित कदम उठाये।

कृषि राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह): अध्यक्ष महोदय, आर्य साहब को मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर हमने सप्रे का इंतजाम करा दिया है और जो कीड़े (सूंडी)लगे हुए हैं, अब उनका आगे प्रभाव नहीं बढ़ेगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मंत्री जी अभी जवाब दे रहे हैं या बाद में देंगे।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (भी वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, आप इन्हें समय दे दें ताकि ये बाद में डिटेल्ड जवाब दे सके।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बाद में किसी दिन जवाब दे देना।

श्री बलबीर सिंहः सर, मैं 28 मार्च, 1988 को जवाब दे दूगा।

वर्ष 1988– 89 के बजट पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब ईयर 1988–89 के बजट पर जनरल डिस्कशन होगी।

श्री भागी राम (ऐलनाबाद): स्पीकर साहब, उप–मुख्य मन्त्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में काफी बातें सुझायी गई हैं। अलग अलग मदों पर जो पैसा खर्च होगा, उसका भी व्यौरा इस बजट में दिया गया है। जो सहूलियतें इस सरकार ने दी है, वह आज तक किसी भी हिन्दुस्तान के सूबे की सरकार ने नही दी हैं, चाहे वह बुढ़ापा पेन्शन की बात है, चाहे बिना टिकट दावा करने की बात है। इस सरकार ने ही यह सहूलियत दी कि जो लोग कहीं इन्टरव्यू दो जायेंगे, वे बिना टिकट यावा कर सकते हैं। सब से पहले हरियाणा सरकार ने लोगों का कर्जा माफ किया है। इसी प्रकार यह फैसला भी इसी सरकार ने किया है कि कोई वजीर किसी जिले मे जाएगा तो वह अपना खर्चा खुद करेगा। लेकिन पहले अमूमन ऐसा होता रहा है कि मत्रिंयों का खर्चा सरकारी अफसरों को वहन करना पड़ता था। एक दिन की बात है कि .... टूर पर गए हुए थे। उनका जो वहां पर खर्चा हुआ, उसकी पेमैंट किसी अधिकारी ने की। मैंने पूछा कि यह पैसा किस की

तरफ से दिया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि मन्त्री जी की तरफ से भुगतान कर रहे हैं और हमारे महकमे की तरफ से दिया जा रहा है। मैंने पूछा कि आप इस पैसे को कैसे पूरा करोगे तो कहने लगे कि इधर उधर से करेंगे। मैंने कहा कि इधर उधर से कैसे करोगे तो कहा कि किसी काम में यह खर्चा डाल देंगे, उससे पूरा कर देंगे। चौधरी देवी लाल आने के बाद कोई भी वजीर किसी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जाता है तो उसका खर्चा कोई अधिकारी नही देता है, उसके खाने–पीने का प्रबन्ध अब कोई नहीं करेगा।

चौधरी तैयब हुसैनः स्पीकर साहब उन्होंने उस व्यक्ति का नाम लिया है वो स्वर्ग में है। उनका नाम कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्षः जो नाम भी भागी राम जी ने लिया है, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी की सरकार आने के बाद सभी काम ऐसे हुए हैं जो सभी सूबों से अलग हैं। सन 1977 में जब चौधरी देवी लाल की सरकार आयी थी उस समय भी ओलावृष्टि हुई थी। उस समय किसानों को 400 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। हरि–जनों की चौपालो के लिए उस समय सब से ज्यादा पैसा दिया गया। वह भी हिन्दुस्तान के सभी सूबों से अलग से काम किया था। स्पीकर साहब मेरा हल्का राजस्थान के साथ लगती है। वहां

पर राजस्थान के लोग आते हैं। पिछले दिनों जब नए वोट बनाने की बात आयी तो वे कहने लगे कि आप अपने हल्के में हमारा भी वोट बनवा दो। मैंने कहा कि यहां वोट क्यों बनवाना चाहते हो तो कहने लगे कि मैं बूढ़ा आदमी हूं। हरियाणा में पेन्शन बनेगी तों शायद मेरी भी पेन्शन हो जाए। आज सारे हिन्दुस्तान में इस पैन्शन की चर्चा है।

स्पीकर साहब, इन सारी बातों का इस बजट में उल्लेख किया गया है और मैं इसका पूरजोर समर्थन भी करता हू, लेकिन मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूं, उस. सिरसा जिले का भी जिक्र करना चाहता हू। स्पीकर साहब, चाहे कोई मुख्य मन्दी बना चाहे बंसी लाल बना, चाहे भजन लाल वना या कोई अन्य मुख्य मन्त्री बना, उसने अपने जिले का विशेष ध्यान रखा और मेरे जिले सिरसे के साथ भेदभाव बरता है। आज भी कोई कहने वाला कह देगा कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता गया।

लेकिन यह सही है कि सिरसा जिला के साथ भेदभाव बरता गया। सिरसा विमा में एक पी० डब्ल्यू० डी० का डिविजन था जिसे जिला भिवानी में बदल दिया गया। दूसरे, एक एक्सीयन नहर सिरसा का कार्यालय भट्टू डिविजन का सिरसा में था, उस दफ्तर को भी भजन लाल के आने के बाद सिरसा से फतेहाबाद में बदल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल के जवाब में हमारे सहकारिता मंत्री जी सिरसा मिल्क प्लांट के बारे में बता रहे थे। वे चाहे मानें या न मानें, लेकिन यह हकीकत है कि जिला सिरसा के

साथ भेदभाव इस कारण बरता गया कि यह जिला चौधरी देवी लाल का जिला है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आपने अफसरों के तबादले भी सुने होंगे। मैं तीसरी बार इस हाऊस मे आया हूं। इस दौरान मैंने देखा है कि एस० पी०, डी० सी० और छोटे–मोटे अफ्सरों के तबादले हुए और क्लास थी और क्लास फोर के भी तबादले होते रहे हैं लेकिन जिस ट्रांसफर का मैं जिक्र कर रहा हूं वह ऐसा तबादला है जो आपने कभी भी देखा या सुना नही होगा। मेरे हल्के ऐलनाबाद में बी० डी० ओ० का एक आफिस है। वहां पर एक नई जीप डीजल की आई थी और उस समय चौधरी बंसी लाल जी चीफ मिनिस्टर थे। न जाने किसने चौधरी बंसी लाल जी को बता दिया कि ऐलनाबाद में एक नई जीप आई है। अध्यक्ष महोदय, उस जीप को ऐलनाबाद से तोशाम बदल दिया गया, बिल्कुल– ऐसे जैसे किसी अधिकारी/कर्मचारी के बदली के आर्डर होवे हैं। इस जीप की बदली के आर्डर हुए और ऐलनाबाद की डीजल की जीप तोशाम में और तोशाम की एक जीप जो कि बाबा आदम के जमाने की थी और पैट्रोल से चलती थी एक फोर व्हीलर के पीछे बांध कर ऐलनाबाद भिजवा दी गई। इस तरह से जिला सिरसा के साथ शुरु से ही भेदभाव बरता जाता रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता और वै ही मेरी यह राय है कि जिस प्रकार चौधरी बंसी लाल और भजन लाल ने बजट का पैसा अपने हल्के के लिए खर्चा, वैसे ही हमारी यह सरकार भी करे (विघ्न)हमारी सरकार बदले की भावना न रखे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो हमारे साथ आज तक ज्यादती हुई है, जो सिरसा जिला

का कोटा है और वाहर भेजा गया है, मै आदरणीय उप–मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमे दिया जाए। पिछले सालों को जो राशि इस जिले की बकाया है, वह सिरसा जिला को दी जाए, यह मेरी उप–मुख्य मन्त्री जी से रिक्वैस्ट है।

अब मैं दों–चार महकमों के बारे में अगने विचार रखना चाहूंगा। यहां पर इस समय कई मंत्री बैठे हैं और कई उठ कर चले गए हैं। सबसे पहते मैं श्री भारद्वाज साहब ने निवेदन करुंगा कि ओटू का एक पुल है। अध्यक्ष महोदय, अफसोस है कि मैं लगातार पिछने ग्यारह वर्ष से इसका जिक्र जरा इस विधान सभा में करता आ रहा हुं। एक बार भारद्वाज साहब ने इस गर दाम भी शुरु करवा दिया था। दो वजीरो ने मिल कर उन पुल का काम शुरु करवाया था लेकिन उसके बाद पता नहीं किस वजह से वह काम बन्द हो गया। फिर मैंने हाउस में उस बारे में क्वैश्चन दे दिया। जब भारद्वाज साहब को पता चला कि क्वैश्चन दे दिया है तो इन्होंने सोचा कि इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, इसलिए इन्होंने बताया कि उस पुल का काम चालु कर दिया है। उस पुल की वजह से दो सौ गांवों का रास्ता बन्द पड़ा है। पुल खराब होने की वजह से आज सिरसा से रानिया, सिरसा से डबवाली वाया संगरिया जाने के लिए बहुत चक्कर काट कर आना पडता है। पिछले लीजन में इन जगहो से जिन किसानों की फसलें सिरसा आनी थीं, वे नहीं आ पाईं। अब थोडे दिनों में बरसात आने वाली है, आखिर भगवान कभी तो हमारे से राजी होगा ही।

अध्यक्ष महोदय, इस पुल के जरिए सिरसा से रानिया 12– 13 किलोमीटर पड़ता है लेकिन अब 60 किलोमीटर का चक्कर काट कर सिरसा आना पड़ता है? मेरा भारद्वाज साहव से निवेदन है और आई० पी० एम० साहब तो बैठे नही हैं, इसलिए उप मुख्य मन्त्री जी को भी मेरा निवेदन है कि इनको साथ मिला लें और सारे मिल कर उस पुल का काम पूरा करवा दें। जब तक उसका काम पूरा न हो उसे बन्द न होने दें। इसी तरह आज एक सवाल था। मैंने पूछा था कि सड्कों की मुरम्मत करने का क्या क्राइटेरिया है? मेरे हल्के में एक सड़क 1977 में बनी थी, जो ओटू से ठोगरिया वाया कुतावड है। जब से यह सड़क बनी है तब से लेकर आज तक उसकी मुरम्मत नही हुई। बीच में मैं पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी बन गया था। उस समय मैंने इनसे कहा था कि मेरा यह काम करवा दो। मेरे अनुरोध पर इस सड़क पर रोडी–बजरी के कई ट्रक भी गिरवाए गए थे, वे अभी भी ज्यों के त्यो गड़े हैं। उसके बाद वहां पर कुछ भी काम नही हुआ। यह सडक इतने समय से ऐ से ही पड़ी है। वहां पर रोड़ी और दूसरा सामान पड़ा है लेकिन काम शुरु नही हो पाया। लोकल ऐलनाबाद के अन्दर मैंने बडी मुश्किल से मन्त्री जी से कह कर काम चालू करवाया था। सिरसा से गंगा नगर और हनुमान गढ को जो सडक जाती है, उस पर ट्रैफिक ऐलनाबाद के तंग बाजार से होकर जाता है। मेरा निवेदन है कि वहां पर बाई पास बनवा दें ताकि बाजार से ट्रैफिक को बाहर निकाला जा सके। दूसरे जो रोडी और बजरी, मन्त्री जी ने भिजवाई थी, उसे कृपा करके बिछवा दें तथा

तारकोल वगैरह डालकर काम करवा दें। स्पीकर साहब, आपने भी पढ़ा होगा और मन्त्री जी ने भी पड़ा होगा, अखबारों में रोज आता है। ऐलनाबाद राजस्थान बौर्डर के साथ लगता है। जब से चुनाव प्रणाली शुरू हुई, तब से लेकर अब तक, एक बार छोड कर, वहां से वह एम० एल० ए० जीता है जिसके सिर पर चौधरी देवी लाल जी ने हाथ रखा। एक बार चौधरी देवी लाल जी के खिलाफ एक एम० एल० ए० जीता था और वह भी केवल एक साल ही रहा था। मैं भी इस हल्के से लगातार तीसरी बार एम० एल० ए० बन कर आ रहा हू। अध्यक्ष महोदय, अब हम लोगों से कहते हैं कि हमारी सरकार आ गयी है, हम सारे काम आपके करा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, नहरें बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे,। अध्यक्ष महोदय, आज हमसे जब लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मेरा इतना–सा निवेदन है कि इन छोटी–छोटी बातों की तरफ ध्यान दें जैसे जिन सड्कों पर बजरी पडी हुई धै, उनका काम पूरा करवा दें। इससे आगे मैं रोडवेज की ताबत कुछ कहना चाहूंगा। रोडवेज से पहले मैं हैल्थ मिनिस्टर से चूंकि वे यहां पर बैठी हुई हैं, भी कुछ अपील करना चाहूंगा। कमला बहन से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह जरा मेरी बातों की ओर ध्यान दें। रानियां और ऐलनाबाद मेरे हल्के में दो कस्बे पड़ते हैं। मस्ती जी वहां पर गयी भी थीं। रानियां और ऐलनाबाद दोनों जगहों पर गयी थीं। अफसोस तो हमें तब होता है जब हमारे साथी यहां पर डिमांड करते हैं कि हमारे यहां पर 100 बैड का अस्पताल जो है, उसको 150 बैड का कर दिया जाए, या 150 बैड का अस्पताल है,

उसको 210 बैड का कर दिया जाए। कोई कहता है कि 200 बैड के अस्पताल को 250 बैड का कर दिया जाए। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने जवाब में बताएं कि ऐलनाबाद अस्पताल में इस समय कितने बैड हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक भी बैड नही है। कोई कहता है कि दो तो सुलवा दो। दो को सुलवाने के लिए एक बैड तो चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐलनाबाद में बैड नाम की कोई चीज ही नही है। रूरल डिस्पैसरी है। एक कमरा है। उसी में कुर्सी है, उसी में अलमारी है, उसी में दवाईयां हैं, उसी में डाक्टर बैठता है और उसी मे मरीजों को देखता है। एक छोटे सें कमरे में सारा कुछ पड़ा हुआ है। वहां पर मैं कोई 100, 150, 200 या 250 बैड का अस्पताल नही मांगता। मैं चाहता हूं कि कम से कम वहां पर 30 मैड का अस्पताल तो बना दें। जिन बहादुर लोगों ने मुझे तीसरी बार चुनकर यहां पर भेजा है, वहां मैं यह कहने के लायक तो हो जाऊंगा कि मैंने यहां पर कम गै कम 30 बैड का अस्पताल तो बनवा दिया हूं। इसी तरह से रानियां के बारे मे भी यह निवेदन करूंगा कि वहां पर भो एक अस्पताल होना चाहिए।

स्वास्थय मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा): आप फैसला कर लें एक जगह. का कि कौन सी जगह पर बनवाना है। रानियां या ऐलनाबाद?

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मैं तीसरी बीर हाउस में आया हूं। अगर एक बार का एक अस्पताल बनाएं तो भी मेरे हिस्से

में तीन अस्पताल आने हैं लेकिन मैं तो फिर भी दो की मांग कर रहा हूं। इमलिए मेरा निवेदन यह है कि रानियां और ऐलनबाद दोनों जगहों पर इस तरह के अस्पताल बनाए जो कम से कम 30 बैड्ज के तो हो। बाकी जो जगहें हैं जैसे जगमरा, तलवाड़ा आदि इनमें प्राइमरी हैल्थ सैटंर्ज अवश्य खुलवा दें। (व्यवधान)आपके पल्ले से थोड़ा ही लगना है। मैं खजाना मन्त्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें। उप–मुख्य मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मुझे आशा है, वे मेरी बात को नोट करेंगे और ऐलनाबाद हल्के की तरफ दूसरे हल्कों की बनिस्बत जरा ज्यादा ध्यान देंगे।

अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहुंगा। मेरा हल्का ऐलनाबाद राजस्थान बौर्डर पर लगता है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी के मास्टरों की कुल संख्या, अगर मुझे ठीक तौर पर पता है तो शायद 2– 4 से ज्यादा नहीं होगी। मेरी कांस्टीच्यूएंसी के 2– 4 मास्टर ही होंगे, इससे फालतू नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, हम लोग अनपढ़ इसलिए हैं क्योंकि वहां पर स्कूल ही नहीं हैं। मास्टर ही नहीं हैं। वहां पर हाई स्कूलों और मिडल स्कूलों की संख्या बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि चूकि शिक्षा मन्त्री जी यहां पर बैठे नहीं है, इसलिए उप–मुख्य मन्त्री जी, जो यहां गर बैठे हुए है, नोट करके शिक्षा मन्त्री जी को बता दे वरना हो सकता है वह भूल– भाल जाएं। जैसे मैंने बताया है कि तीन–चार जे० बी० टी० मास्टर्ज ही मेरी कांस्टीच्यूएंसी के होंगे। कोई भी स्कूल मेरे हल्के

में ऐसा नहीं है, जिसमें मास्टर्ज पूरे हों। किसी स्कूल मे तीन मास्टर्ज की कमी है तो किसी में दो की कमी है। कहीं पर अगर प्राइमरी स्कूल है तो मास्टर नही है। कहीं पर एक ही मास्टर होता है और वह भी कई बार नहीं होता। कहने का मतलब यह कि स्कूल में कई बार हाजरी लगाने वाला भी नही होता। इसका आखिर इलाज क्या है? अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ से इसका इलाज करने के लिए एक सुझाव है। वह यह कि जब तक मेरे हल्के के, उस एरिया के मास्टर नहीं होंगे, तब तक इस समस्या का सही समाधान नही हो सकता। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)मेरा निवेदन यह है कि इसके लिए ऐलनाबाद में एक परमानैंट तौर पर जे० बी० टी० ट्रेनिंग सैटर खोल दिया जाए। एक प्लान में ही नही बल्कि हर प्लान में यह सैटर चलता ही रहना चाहिए ताकि मास्टरों की कमी न रहे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए जो सरकार की शर्त होगी वह पूरी करेंगे। मैंने इस बारे में शिक्षा मन्त्री जी से बात की थी। वह कहने लगे कि क्या दस एकड़ जमीन दे दोगे? मैंने कहा कि आग परमानैन्ट जे (1 बी० टी०)स्कूल दे देंगे नो मैं पचास एकड़ दिलवा दूंगा। उपा– ध्यक्ष महोदय, मैं तो सौ एकड़ जमीन भी पंचायत से दिलवाने के लिए तैयार हू। मुझे आशा है कि उप–मुख्य मन्त्री महोदय जी मेरी इस काम में सहायता करेंगे और ऐलनाबाद मे एक जे० बी० टी० स्कूल खुलवाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आई० पी० एम० साहब बैठे नहीं हैं। मेरे हल्के की दो चार मांगें सिंचाई के बारे में हैं। लोगों

को बहुत तकलीफ है और पिछले कई सालों से ऐलनाबाद के हल्के के साथ बहुत बेइन्साफी हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्यूसी में एक मल्लेका माइनर 1977 में निकलनी थी। 1977 में उसका काम चालू हुआ था और जिस दिन भजन लाल इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने उसके बारे में किसी आदमी ने बता दिया होगा या किसी अफसर ने अपनी मर्जी से कर लिया होगा, वहां से टोकरी और कस्सी उठवा ली और वहां पर आज तक काम चालू नही हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आज तो चौधरी देवी लाल की सरकार है। चौधरी साहब, लोगों के, किसानों के और मजदूरों के हित को समझते है। मेरा निवेदन है कि कम से कम उस माइनर पर काम शुरु करवा दिया जाए। अगर वह माइनर बन जाएगी तो 15 गांवों को फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, 99 प्रतिशत वोट मुझे सिर्फ इसलिए मिले है कि तैयब हुसैन की सरकार ने बहु माइनर बन्द करवा दी थी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस बजट सैशन के बाद उस माइनर पर काम अवश्य ही शुरु करवा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में ओटू मे एन० जी० सी० एक पैरेलल पक्की नहर बनी थी। इस नहर का काग 1977 में शुरु हुआ था और उसके बाद सरकार बदलने पर काम बन्द करवा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, तकरीबन सारी नहर बन चुकी है, लेकिन कहीं पर दस फुट का फासला है, कहीं पर बीस फुट का है। मतलब यह है कि बीच में कई सोते रह गए हैं। अगर इन सांतों

पर काम चालू करवा दिया जाए तो कम से कम बीस पच्चीस गांव ऐसे है जिनके लोग इस सरकार के गुण गाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सरकार इस नहर को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक सैरा वाला पैरेलल चौनल है। यह फतेहाबाद ब्रान्च मे निकलती है। यह मलिका गांव तक पक्की बन गई है। सरकार इसको बनाएगी तो अवश्य लेकिन अगर यह लेट बनेगी तो इससे लोगों का नुकसान होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको टेल तक पक्का कर दिया जाए और इसका वैड लैवल अगर अढ़ाई फ्ट ऊंचा कर दिया? जाए तो वहां के लोग खुश हो जाएंगे।

11.00 बजे

डिप्टी स्पीकर साहब, एक कर्मशाल माईनर है। 8 साल हो गए हैं इसके लिए गाव के लोगों ने 60 हजार रुपया इकट्ठा करके सरकार के पास दे रखा है लेकिन सरकार ने बदले की भावना से उस काम को अभी तक शुरु नहीं करवाया है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस माईनर के काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए ताकि उस इलाके के लोगों को फायदा हो सके इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी माईनर्ज घोलपालीया, बरेवाला और किशनपुरा इत्यादि हैं, इनकी तरफ भी सरकार को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक एस० जी० सी० नहर है जिस पर मिट्टी गिराने काकाम सन 77 में चालू किया गया था। जो मौजूदा मन्त्री हैं उन्होंने ही पीछे इस काम को चालू करवाया था और ज्यों ही हमारी सरकार गई तो इन्होंने वहां से कस्सी–टोकरी भी उठवा ली और वह काम ठप्प हो गया। उस नहर के ऊपर केवल दो सांखें बनानी बचती थीं जोकि आज तक नहीं बनी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस काम को जल्दी पूरा करवाया जाए। जो कुछ मेरे हल्के के साथ किया जा रहा है, यह भेद भाव की भावना के कारण ही किया जा रहा है। सरकार इस ओर ध्यान दे और जो काम इस तरह का बकाया है, उसको जल्दी ही पूरा करवाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में एक दो बातें हाउस के सामने कहना चाहता हूं। पी० डब्ल्यू० डी० का राक डिवीजन पहले सिरसा में हुआ करता था उसको अब भिवानी में भेज दिया गया हैं जोकि उप मुख्य मन्त्री महोदय से संबंधित है। मेरा उनसे यह नम निवेदन है कि सरकार चाहे तो एक और नया डिवीजन भिवानी में खुलवा दे लेकिन जो डिवीजन पहले सिरसा में होता था, उसको वापिस सिरसा में भिजवा दिया जाए।

इसी तरह से एक एक्सीयन का दफ्तर जो इरीगेशन से ताल्लुक रखता है, वह फतेहाबाद में हए और उस से ज्यादा ताल्लुक मेरे हल्के के लोगों को रहता है जिनको अपने काम काज

के लिए वहां आने–जाने में काफी दित–कते होती है। लगभग 100 किलोमीटर तक लोगों को वहां पहुंचने के लिए सफर करना पड़ता है। इसलिए मेरी इस लोकप्रिय सरकार से प्रार्थना है कि उस एक्सीयन के दफ्तर को फतेहाबाद से सिरसा में तबदील कर दिया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और लोग आसानी से अपना काम करवा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक मिल्क प्लांट भी है उसको भी चालू करवाया जाए। इन बातों के साथ मैं सरकार के इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो जो प्रार्थनाएं मैंने सुझाव के रूप मे की हैं उनकी ओर गी व ही ध्यान दिया जाए और जो काम पिछले कई सालों से रुके पडे हैं उनको जल्दी ही करवाया जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हू।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान (कैथल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इस के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे उप मुख्य मन्दी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हू। हमारे उप–मुख्य मन्त्री जी ने एक बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया है। इस बजट में जो 36 करोड रुपए का घाटा दिखाया गया है, वह पिछले सारे घाटे को कवर करके दिखाया गया है। इस वार्षिक योजना मे जिन कामों के लिए जितना पैसा दिया गया है, शायद उतना पैसा पहले कभी नहीं दिया गया। जैसे पैशन देने की

योजना है, कर्जे माफी की योजना है, और भी कई प्रकार के जनहित के लिए इस सरकार ने कदम उठाए हैं, वे वाकई ने सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के कैथल के बारे में अपने माननीय उप–मुख्य मन्त्री जी को कुछ बातें बताना चाहूंगा। कैथल ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है,। वहां पर 9 गृह हैं जिनके नाम से 9 कुण्ड बने हुए हैं जो काशी के अलावा हिन्दुस्तान में दूसरी जगह कहीं नहीं हैं। वहां पर एक शिव मंदिर है जिसके अन्दर 11 शिवलिंग हैं। ऐसा मंदिर या तो कैथल में है या फिर काशी जी में है और कही भी नही है। अब मैं आर्थिक दृष्टि से भी कैथल के बारे में बताना– चाहूंगा वहां पर जो मंडी है वह ज्वायंट पंजाब से है और बहुत ही मशहूर मंडी है! कैथल मंडी से जितना बिजनैस होता है शायद उतना बिजनैस हरियाणा प्रदेश की एक या दो मंडियों में ही होता होगा। ज्वायंट पंजाब के समय कैथल जिला होता था और जिस समय हिन्दुस्तान पर अंग्रेज राज किया करते थे उस समय भी कैथल जिला होता था लेकिन आज तहसील बन कर रह गया है। कैथल के अन्दर उपायुक्त महोदय और पुलिस कप्तान के आफिसों के अलावा दूसरे सभी आफिस मौजूद हैं। जब चौधरी भजन लाल मुख्य मन्त्री हुआ करते थे, उस समय वे कई बार कैथल गए और हर बार उन्होंने घोषणा की कि कैथल को जल्दी ही जिला बना दिया जाएगा। कैथल को जिला बनाने के लिए बहुत पहले से कहा जा रहा है लेकिन उस बात को अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से और उप–मुख्य मन्दी

जी से प्रार्थना करूंगा कि कैथल को शीघ्रातिशीघ्र जिला बनाया जाए और उसके अंडर गुहला, पेहवा और पाई जैसे बड़े कस्बे शामिल कर लिए जाएं। इसके अलावा, मैं कहना चाहूंगा कि कैथल के लिए एक कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम है, उसके बारे में हमारे जन स्वास्थ्य मन्त्री जी ने अभी बताया था कि वह 1982 से अधर में लटक रही है। कैथल की लगभग एक लाख से ज्यादा की आबादी है लेकिन वहां केवल 6 ट्यूबवैलज हैं। उन ट्यूबवैल्ज से इतनी जनसंख्या को पीने का पानी मुहैया नहीं किय जा सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कैथल में लोगों के पीने के पानी की जरूरत को पूरा किया जाए। यदि कैनाल वाटर बेस्ड लीन को पूरा कर दिया जाए तो इस शहर की पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन उस –स्कीम के बारे में 1982 से फाईल यहां चण्डीगढ़ में चक्कर लगा रही है, उस बारे में कोई गोर नही किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसी तरह से कैथल सिविल होस्पीटल की बात है। वहां पर लगभग 2 साल से 100 बैड का होस्पीटल मंजूर हो चुका है और डाक्टर्ज भी 100 बैड होस्पीटल के हिसाब से मौज्द हैं लेकिन मरीजों के. लिए बैड नही है यदि बैड्ज की सुविधा नहीं दी जाती तो फिर 100 बैड के हिसाब से डाक्टर्ज भेजने की क्या जरूरत है? इसके अलावा, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि कैथल होस्पीटल मे दिन के समय में लाइट नहीं होती, शाम को 5 बजे बिजली आती है। होस्पीटल में दिन के समय बिजली न होने के कारण देहात से आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना

करना पड़ता है। यदि देहात से कोई मरीज एक्स–रे करवाना चाहे या दूसरी कोई बीमारी टैस्ट करवाना चाहे तो वह काम शाम को 5 बजे के बाद हो सकता है, इससे पहने नही हो सकता क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद ही बिजली आती है। यदि देहात से आया हुआ मरीज शाम को पांच बजे के बाद अपना एक्स–रे या दूसरी बीमारी टैस्ट करवाएगा तो वह वापिस अपने गांव नही जा सकेगा क्योकि शाम को पांच बजे के बाद बसें बन्द हो जाती हैं। मेरी प्रार्थना है कि कैथल होस्पीटल मे 24 घंटे बिजली देने का प्रबंध किया जाए ताकि मरीजों कों कोई दिक्कत न हो। यदि दिन में होस्पीटल को बिजली दी जाती है तो देहात से आए हुए मरीज उस होस्पीटल में अपनी टैस्टिंग वगैरह करवा करके समय पर अपने गांवो में आसानी मे वापिस जा सकेंगे।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि कैथल में दुन्दरहेडी और सुजमा दो माइनर हैं जिनको बनाने के लिए कांग्रेस के राज मैं श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला ने पत्थर भी रखा था और उसका एस्टिमेट भी बन चुका था। मुझे यह नहीं पता कि यह काम उस सरकार ने वोट बटोरने के लिए किया था या उसका कोई और मकसद था, लेकिन वे दोनों माइनर अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन दोनों माइनरों को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। इसी तरह सें वहां पर एक कलिया माइनर है जो एक कलिराम नाम के किसान के नाम से है। उस किसान की उम्र

80 साल के करीब है और वह 40 साल से उस माइनर को पूरा करवाने के लिए सरकार के पीछे लगा हुआ है लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। मेरी प्रार्थना है कि उस माइनर को अवश्य बनाया जाए। इस समय वह बूढा व्यक्ति आखिरी सौसे ले रहा है। इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस माईनर को बनवाने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए ताकि मरने से पहले वह देख सके या सुन ठके कि यह माईनर उसके जीते जी बन चुकी है। इसलिए मैं उप–मुख्य मन्त्री जी से दरख्यास्त करता हू कि इस माइनर को अवश्य बनाया जाए क्योंकि इसके साथ किसी बूढ़े व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यदि सरकार ऐसा कर देती है तो मैं समझता हूं कि उस बुढे व्यक्ति के मन को भी शांति मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कैथल में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय है। इसकी नई बिल्डिंग बनाए जाने के लिए पिछले साल से 26 लाख रुपया मन्जूर हुआ पड़ा है लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है। इस बारे में मैंने कई बार अधिकारियों से कहा है 1 मुझे बताया गया कि जहां पर यह बिल्डिंग बनाई जानी है उसका कोई झगड़ा चल रहा है। यदि उस जमीन का झगड़ा चेल रहा है या किसी ने स्टे लिया हुआ है तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कोई और जगह तलाश करके इस बिल्डिग को अवश्य बनवाया जाए ताकि बच्चों को सुविधा हो सके। इस समय वहां पर एक छोटी सी बिल्डिग है। जिस की वजह से सर्दियों में बच्चों को दो–दो शिपटो में आ कर पढ़ना पड़ता है।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। इसी प्रकार से ग्हना मे एक आई० टी० आई० खोलने के लिए गांवों के लोगों ने 7 एकड़ जमीन दी हुई है और इसके लिए पैना भी मन्जूर हुआ पड़ा है। यह बात समझ नहीं आती कि जिस स्कीम के लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ हो, उस पर काम क्यों एरु नही हो पाता? इस बारे में भी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर जल्दी से जल्दी आई० टी० आई० की बिल्डिंग बनाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेरे हल्के के एक गांव क्योड़क को कुछ समय पहले फोकल ग्राम घोषित किया था लेकिन फोकल ग्राम घोषित होने के बाद भी उस पर आज तक उतनी कार्यवाही नही हुई जितनी कि एक फोकल ग्राम में की जानी चाहिए। इस गांव का काम भी बीच मे ही लटका हुआ है। पहले तो अवश्य कुछ सुविधाएं देनी शुरू की गई थीं लेकिन बाद में वे सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इस सरकार के आने से वहां के लोग अपने गांव का काम किए जाने के लिए बहुत सी आशाएं लगाए बैठे हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस फोकल गांव में जो सुविधाएं दी जानी हैं, वे जल्दी से जल्दी दी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के पाढला और रडाना बावा दो गाव हैं जहा कोई मण्डी नहीं है वहां के लोगों को अपना अनाज बेचने के लिए 25– 30 किलोमीटर चल कर कैथल आना

पड़ता है। उनको बहुत दिक्कत होती है। दूसरे कैरिज का भी अधिक खर्च आता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यदि पाढला या रडाना बाबा गांव में मण्डी बना दी जाए तो लोगों का कैथल आने से पीछा छूट जाएगा और वे अपना अनाज वहीं पर बेच सकते हैं जिससे उन्हें काफी सुविधा हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपका धन्यवाद करते हुए और इस बजट भाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण, करता हूं।

चौधरी तैयब हुसैन (तावडू): मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट से बहुत उम्मीदें हरियाणा की जनता को थीं। लोग यह आशा लगाए बैठे थे कि जब बजट आएगा तो गवर्नमैंट से उन्हें काफी राहत मिलेगी और बहुत सारी सहूलियते सरकार की तरफ से लोगों को दी जाएंगी। खास तौर से हरियाणा के लोग उप–मुख्य मन्त्री जी पर आशा लगाए बैठे थे क्योंकि इनके पास सरकार के खजाने की चाबी है और इनका पोलिटिक्स में काफी तजुर्बा भी है। दूसरे, इस सूबे के ये पहले एक बार मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं। इनके अनुभव से लोगों को बहुत सी आशाए थी। लेकिन इनके तजुर्बे की कोई बात इस बजट में देखने को नही मिली जिससे इस सूबे का विकास बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता। मेरा कहना यह है कि जिस तरह की लोगों को आशाएं थी वह कोई बात इस बजट में नही आई। यह बजट इन के द्वारा प्रस्तुत किए जाने से हरियाणा सूबे के लोगों को निराशा ही हुई है क्योंकि लोगों की जो

उम्मीदें, थी वे पूरी नहीं हो पाई हैं। ये अपने बजट में ऐसी कोई आशा ते कर नहीं आए जिससे लोगों की आशा पूरी कर पाते। अब मैं टैक्सेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं बजट पेश करने से पहले ही टैक्स लगा दिए गए। इस सरकार का नया तरीका है। हर गरीब आदमी बस में सफर करता है, उसका भी बजट आने से पहले किराया बढा दिया गया। इसी प्रकार से बिजली की दरें भी बढ़ा दीं। इफकी अजीब बात एक अरि भी है कि पहले टैक्स लगा दें, फिर घटा दें। इस सरकार ने कम्बलों पर जूट के थैलो पर और ढाबे वालो पर पहले तो बिक्री कर, लगा दिया फिर घटा दिया या खत्म कर दिया। अभी पिछले दिनों एम० एल०ए० हास्टल के सामने लकड़ी के व्यापारी आए हुए थे, वे भी कुछ अपनी मांगे कर रहे थे। इस सरकार की कोई प्लानिग और सूझ–बूझ नही है। आज एक आर्डर कर देते हैं, कल को उसे ही रिवाइज करके डायरेक्शनलैस और कलरलैस कर देतें हैं। ऐसा करने से सरकार की साख गिरती है बढ़ती नही है। इन्हें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। मोहम्मद तुगलक का नाम लिया जाता है कि उसने अपनी राजधानी को बदला था। यह सरकार भी वही बात क्यों करना चाहती है? इन्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। आज टैक्स लगा दिया और कल को हटा दिया, ऐसा नही करना चाहिए। जब इस सरकार ने बजट आने से पहले ही टैक्स लगा दिए तो फिर बजट मे टैक्स लगाने की बात कहां रह गई? सब से ज्यादा तकलीफ की बात ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है। यह सरकार किसानों और ग्रामीण लोगों की बात करती है। मैं आपके जरिए

इस सरकार के लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने ग्रामीण लोगों के लिए क्या किया था और आपकी सरकार ने क्या किया है? यह रिकार्ड की बात है। इरीगेशन के ऊपर पहली सरकार ने 60 प्रतिशत रुपया खर्च किया था। इस सरकार ने उसे घटा कर 40 प्रतिशत कर दिया। कल ही सरकार ने हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि बेरोजगार नौजवानों को बेकारी भत्ता मिले क्योंकि चुनाव के अवसर पर इन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा लेकिन उसे पूरा नहीं किया। यहां हाउस में रेजोल्यूशन लाने से बात नहीं बनती। जब एक मामला तय किया गया थी तो उसे पूरा करना चाहिए था। जब आप उस वायदे को पूरा नही कर सकते थे तो उस पर बन न दे कर लोगों को समझाते कि यह बात हों नहीं पाएगी।

दूसरी बात मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं। सरकारी मुलाजमों को पहले वाली सरकार ही फौर्थ कमीशन लागू कर के गई थी। (विघ्न)इन्होंने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से कारपोरेशन का भी उस सरकार ने फैसला किया था कि उनको भी फौर्थ कमीशन के ग्रेड दिए जाएं। कारपोरेशनज के मुलाजमों को आज तक ग्रेड नही दिए गए। फैसला उस सरकार में होने के. बाद भी ये ग्रेड नही दे सके। मैं एक बात इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन मुलाजमों को ग्रेड 1 – 1– 1986 से दिए गए और बाद मे वे रिटायर हो गए तो उन्हें पेन्शन भी उसी दिन से दी जानी चाहिए। वे रिटायर हुए है, रिटायर्ड आदमी को पैसे की

अधिक आवश्यक्ता होती हे। जुडिशियरी का भी वरडिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उन्हें उसी तारीख से पेन्शन मिलनी चाहिए। अच्छा तो यही है कि उन्हें उसी तारीख सै पेन्शन मिले बजाए इसके कि वे अदालत में जाएं और सरकार पर डिग्री हो। इस प्रकार बाद मैं कोर्ट फीस और वकीलों का खर्चा बढेगा। क्या यह बेहतर नहीं कि इस बात को पहले ही देख लिया जाए इसी तरह से कई बातें और भी हैं जो करना चाहिएं। इसके साथ–साथ ही मैं यह अर्ज करूंगा कि बजट में उन कामों को पूरा करने के लिए प्रोविजन नही रखा गया। जो काम शुरू हुए थे, उस सरकार फै बदलते ही वे काम बन्द कर दिए गए हैं। ऐसे कामों को बन्द कर देने से जो पैसा उन कामों पर खर्च हुआ है, क्या यह सरकार उस को वेस्ट करना चाहती है मैरी कान्स्टिच्यूएंसी मे पहलू और करिज के दो पुल थे जिनकी डाईवर्शन बन चुकी थी और इन पुलों पर 70–70 या 80– 80 हजार रुपया खर्च हो चुका था। सरकार बदलने के बाद वहां काम बन्द कर दिया गया है। (विघ्न)सरकारें तो बदलती रहेंगी धीरपाल जी, सरकार बनना तो कंटिन्युअस प्रोसैस है, सरकारें आएंगी और जाएंगी, आदमी बदलते रहेंगे लेकिन जो सिस्टम है वह चलता रहेगा। यह कोई ऐसी बात नही है जिससे आज हम अपने आद को अलग कर लें। सिस्टम को अगर बदलने की बात नहीं होती तो आज शायद आप यहां पर न आते। यह सिस्टम की ही मेहरबानी है कि आप यहां आए। यह जो बार–बार कहां जाता है कि आप को जनता ने फतवा दिया है। इस

बात के लिए तो हमने आपकॉ पिछले सैशन मे ही बधाई दे दी थी। मैंने पहले भी कहा था–

जन्नत की हकीकत है मालूम है लेकिन,

दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। (विघ्न)

गुप्ता जी आपको तो पता ही है, 1977 मैं आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आपने मुख्य मन्त्री रहते हुए तजुर्बा देखा है और आपके मुख्य मन्त्री काल मैं परिवार कल्याण का जो काम हुआ है, उसे सारा. हरियाणा जानता है। आप जब बहादुरगढ़ से गुड़गांव गए थे तो मैंने रैस्ट हाऊस में आपको कहा था कि गुप्ता ली फैमिली प्लानिंग गलत तरीके से हो रही है और आपने अपनी पब्लिक स्पीच में कहा था (विघ्न)

उप–मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, ये केन्द्रीय सरकार से यह आदेश दिलवा दें कि इस देश में फैमिली प्लानिंग नहीं की जाएगी। यह सारे कारनामे इनकी उस सरकार के हैं, उन नेताओं के हैं जिन्होंने यह सारे आदेश दिए थे (विघ्न)

चौधरी तैयब हुसैन: गुप्ता जी आप उस समय चीफ मिनिस्टर ये। (विघ्न)मैं यह अर्ज करूंगा और आप मानेंगे भी। (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः आन ए प्यायंट आफ आर्डर सर। गुप्ता जी के बारे में जो यह कह रहे हैं यह ठीक है इन्होंने उस वक्त जो कुछ किया था वह कांग्रेस की सरकार के कारण ही किया था और आपने तो बिना एमरजैसी के ही जुल्म ढा दिए जिसका कोई जवाब नही। (विघ्न)

चौधरी तैयब हुसैनः मैं यह अर्ज कर रहा था कि गुप्ता जी ने उस समय यह कहा था कि अगर जबरदस्ती मार मार कर खीर खिला दी जाए तो उस में कोई बुराई नहीं है। गुप्ता जी को अपनी यह बात याद होगी। (शोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आपने भी वह खीर खाई थी या नही?

चौधरी तैयब हुसैनः उस समय इस संबंध में जो कुछ हुआ उसका नुकसान तो सारी पार्टी को भुगतना पड़ा।

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मान लेता हूं कि उस वक्त मेरी कारगुजारी सारी पार्टी ने भुगती। क्या यू० पी० के अन्दर भी मेरी कारगुजारी थी? क्या पंजाब में भी मेरी कारगुजारी थी क्या मध्य प्रदेश में भी मेरी कारगुजारी थी? उस समय कांग्रेस जो सब जगह थी का पट्टा सभी जगह साफ हो गया था। उसी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमन्त्री थे, दूसरे बड़े नेता थे जो सब जगह थे और आज भी सैंटर में वही बैठे हैं। अगर तैयब हुसैन जी को ऐतराज है तो उनसे होना चाहिए। ये आज भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं की पार्टी ने सारे देश के अन्दर

ऐसा किया था। मुझे सिर्फ हरियाणा में ब्लेंम किया जा सकता है, सारे देश के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। सारे देश के लिए तो स्लेम किया जा सकता है राजीव गांधी को, उनकी मां को और कांग्रेस के नेताओं को।

चौधरी तैयब हुसैनः मैं यह कहना चाहुंगा कि आप इस तरह की बातें न करें। आपने सदन के नेता के बारे में जो अपने विचार प्रकट किए थे, अगर डिप्टी स्पीकर साहब मुझे इजाजत दे दे तो मैं उनको यहां पर प्ले कर दगा। (जोर)

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, ये कौन से विषय और किस सिलसिले पर बोल रहे है। आप बजट पर बोल रहे थे और हम सुन रहे थे। आपने जो कुछ कहा अगर यी सारा रिकार्ड हो जाता है तो आप वही तैयब हुसैन साहब हैं जो चौधरी देवी लाल के पैरों मे पडा करते थे और चुनाव क्षेत्र मे उनके साथ घूमा करते थे। (शोर)

चौधरी तैयब हुसैनः मैंने कही भी जो कुछ कहा है और यहा पर जो बातें कही हैं, मैं उनको ओन करता हू। ठीक है 1984 मे चौधरी देवी लाल जी ने मेरी मदद की थी, मैं इस बात से इन्कार नहीँ करता और न मुझे उस बात की कोई झिझक है। (शोर)

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। चौधरी साहब अगर विषय के अन्दर

रहते हुए बोलें तो अच्छी बान होगी। पहले किसने क्या किया था और किस ने क्या कहा था इन बातों में न जाए। अब कांग्रेस के दो माननीय सदस्य यहा बैठे हैं। इनके बारे में पिछला रिकार्ड और आज का रिकार्ड उठा कर देखा जाए तो उन सब बातों पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसलिए ये बोलने से पहले अपने गिरेबान में हाथ डाल कर देख लें। (शोर)मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने विषय के अन्दर रहते हुए अपनी बात कहें तो ज्यादा अच्छा है। क्या करोगे पुरानी बातें खोल कर, पता नहीं क्या क्या पुरानी बातें हुई है। (शोर)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, चरित्र के मामले में तो हमारे मुकाबिले में कोई नही ठहरेगा। आप जांच करवा लें उसके लिए हम तैयार हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, हाउस की एक समिति बना दो जो सारे पुराने मामलो की जांच करे।

श्री रघु यादवः डिप्टी स्पीकर साहब, तैयब साहब नसबन्दी का जिक्र करते हुए गुप्ता जी की ओर नही बल्कि अपनी पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं। (शोर)

चौधरी तैयब हुसैनः सैटंर की स्कीम को जो सूबे में इम्पलीमैंट कर रहे थे मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हू। (विघ्न)तैयब हुसैन तो पंचायती आदमी है, न कोई बात मुंह पर कहने से हटे और न सुनने से हटे। (शोर)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, खीर वाली बात आई थी, वह खीर तो थी लेकिन कह खीर ठंडी करके देनी चाहिए थी लेकिन गर्म गर्म मुंह में डाल दी। (शोर)

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैं सन् 1977 की बोत करता हू। उस समय फैमिली प्लानिंग के बारे में यह सब कुछ हुआ था। जब 1977 का लोक सभा का इलैक्शन हुआ तो केन्द्र में जनता की सरकार बन गई थी। उस समय हमारी सरकार हरियाणा में थी और मैं मु ख्य मन्त्री था। मैंने इसी स्थान पर खड़े होकर एक बात कही थी कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमने कुछ गल्तियां की थीं। उन गल्तियों का फल जनता ने हमें दिया है जिसकी वजह से हम हार गए। यह बात आन रिकार्ड है, जो नीति निर्धारित की गई थी वह गलत थी। हमने उन नीतियों को अमली जामा पहनाया इसलिए हमको सजा मिली इनको भी सजा मिली। हम ये सारी बातें हाउस में कर चुके हैं।

चौधरी तैयब हुसैनः उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात बहुत कही जाती है कि प्रधान मन्त्री जी जब पलवल में आए तो 403 करोड़ रुपए हरियाणा को देने की घोषणा करके गए थे लेकिन वह रुपए अभी तक नहीं दिए गए। (विज)उपाध्यक्ष महोदय, सब को मालूम है कि एस०वाई०एल० का सारा खर्चा पहले हरियाणा ने बर्दाश्त करना था। यह अच्छी वात होती कि आज की सरकार कांग्रेस सरकार की इस बात के लिए मशकूर होती क्योंकि

उस वक्त की सरकार के मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल के कहने पर एस० वाई० एल० का सारा खर्चा सैट्रल सरकार ने अपने जिम्मे लिया। इसके लिए इनको मशकूर होना चाहिए था लेकिन यह बात ही कुछ और करते हैं। यह कहते हैं कि यह पैसा नहीं आया, वह पैसा नही आया। हमारे रैवेन्यू मिनिस्टर साहब तो कुछ और भी कह गए। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता। खैर, गुप्ता जी के पास तो फाईनांस का महकमा है। इनके पास तो सरकारी आकड़े हैं। मैं उस 403 करोड़ रुपए की तफसील देने लग रहा हूं, उसको गुप्ता जी बेशक लिख लें। एस०वाई०एल० का 262 करोड़ रुपया उस वक्त के ड्राउट रिलीफ के लिए, 16. 74 करोड़ रुपया नवोदय विद्यालय या सैट्रल स्कूल्ज के लिए, 13 करोड़ रुपया फ्लड कंट्रोल के लिए, 55 लाख रुपया ट्यूबवैल्ज इनर्र्जाइ– जेशन के लिए, इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए 12 करोड़, ऐग्रीकल्चर के लिए 5. 93 करोड़, रूरल सप्लाई के लिए 4 करोड़ और एम० आई० टी० सी० को 35 करोड़ रुपए दिए जाने थे (व्यवधान व शोर)मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सारा रिकार्ड किताबों में मौजूद है। कोई रिकार्ड सरकार अपने साथ नहीं ले जाया करती। गुप्ता जी के पास सारा रिकार्ड और किताबें मौजूद होगी। जब आपको हरियाणा की जनता वोट नहीं देगी और आप विदा होंगे तो वह आकडे वहीं पर रहेंगे, कोई साथ नहीं ले जाएगा।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): आन रा प्यावंट आफ आर्डर, सर हमारे माननीय सदस्य चौधरी तैयब हुसैन

जी जिस मामले को रैफर कर रहे हैं, उसको रैफर करके यह बार–बार एक बात कह गए हैं। हमारे उप–मुख्य मन्त्री जी ने कहा, लोगों ने यह कहा कि यह जो 403 करोड़ रुपए की बात है, जिस तरह से और जिस अन्दाज से पलवल में घोषणा की गयी थी, उस का इम्प्रैशन पूरे हरियाणा के लोगों को यही था कि यह 403 करोड़ रुपए उसी तरह से दिए गए हैं जिस तरह से एक कोच फैक्ट्री दी गयी है। इसी तरह की कोई स्पैसिक्कि ग्रान्ट हरियाणा को दी गयी है। इसी तरह से जो एस० वाई० एल० का 262 करोड़ रुपया बता रहे हैं और ट्यूबवैल्ज वगेरा का, यह सब प्रोपोजल सैटर गवर्नमैंट के पास स्टेट गवर्नमैंट की पहले से चल रही थी। यह जो 403 करोड़ रुपया था, यह अलग से था और स्पैसिफिक था। जैसे कोच फैक्ट्री का एलान किया जो पंजाब को चली गयी, 403 करोड़ रुपए हरियाणा के लोगों की मदद के लिए अलग से अनाउंस किए गए थे। अलग से यह अमाउन्ट आया हो, ऐसा कोई अमाउन्ट नही है।

चौधरी तैयब हुसैनः माननीय सदस्य, चाहे अपनी कोई भी इन्टरप्रेटेशन निकालते रहें, यह उनकी अपनी मर्जी है। एक दिन माननीय गुप्ता जी ने कह दिया कि रोहतक मैडिकल कालेज के लिए कुछ रुपया दे दिया गया। वहां पर बौडी स्कैनर्ज हो और इसके लिए 3.35 करोड़ रुपए देने से कोई अच्छी मैडीकल फैसिलिटी हो जाए तो क्या वह बढ़िया बात नही है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः यह काम बढ़िया नहीं है, यह किसने कहा है? (व्यवधान)

चौधरी तैयब हुसैनः रोहतक मैडीकल कालेज में कोई अच्छा काम हो तो उसके लिए भी आपको गिला था। (व्यवधान)जो मैं कह रहा हूं, उसे आप समझो। आपकी बात तो जनता समझ लेगी। (व्यवधान)पचास करोड़ की स्पेशल असिस्टैंस है। यह सारा टोटल 402.57 करोड़ करोड़ बनता है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः क्या यह सारा आ चुका है?

चौधरी तैयब हुसैनः आप बता दें कि आया है या नही आया है। मेरे पास तो ये फिगर्ज हैं। (व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ताः मैंने कहा था कि दो सौ करोड़ के करीब आ चुका है।

चौधरी तैयब हुसैनः आपकी प्रैस काफ्रेंस में जो महकमें के अधिकारी थे उन्होंने माना था कि 258 करोड़ आया है। (व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ताः मैंने यह कहा था कि ऐग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन दो सौ करोड़ से अधिक आ चुका है। जो बात हम मान चुके है, हम कह रहे हैं। उनको दोहराने का मतलब है सदन का समय खराब करना।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धीरपाल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, ये बजट पर तो बोलना ही नही चाहते। यह तो बताना चाक्ते हैं कि हम यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आपको बाईस मिनट बोलते हुए हो गए हैं You 'are inviting interruptions. You are not addressing the Chair. आप कन्वरसेशन में लग जाते हैं। आप तो पुराने लेजिस्तेटर हैं, बजट पर ही बोलें।

श्री हीरा नन्द आर्यः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चौधरी तैयब हुसैन कह रहे हैं कि 403 करोड़ रुपया दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, 438. 97 करोड़ का तो पिछले साल का वजट था। 403 करोड रुपया ये कह रहे है केन्द्रीय सरकार ने दिया है। फिर हरियाणा सरकार का बजट कहा गया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्यांवट आफ आर्डर नही है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आर्य जी ने अभी कहा कि 438 करोड़ रुपए का हरियाणा का बजट था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह रकम पिछली सरकार के 585 करोड के योजनागत व्यय में से 150 करोड़ रुपए के लगभग कम करके दिखाई गई थी।

श्री उपाध्यक्षः आपके नेता बोल रहे हैं।He will explain everything. You are not to reply. It is not the procedure of the House to speak like this.

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर यह भी कहा राया है कि हम खजाना खाली छोड़ कर गए। डिप्टी स्पीकर साहब, खजाना तो कंटीन्युअस प्रोसैस है। स्टेट बजट और इंडिविजुअल बजट में बुनियादी फर्क है। स्टेट बजट में हर महीने पैसा आता है और खर्च होता रहता है। जिस दिन हम गए उस दिन 45 करोड़ रुपया छोड़ कर गए थे। हर महीने पैसा आता रहता है और खर्च होता रहता है। स्टेट बजट में यह होता है कि पहले खर्च की बात आती है और इंडिविजुअल बजट में आमदनी की बात पहले आती है। उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा के सिलसिले मे बहुत बातें कही गई और काफी कुछ अखबारों में आया है कि दो सीनियर अधिकारी जो इससे संबंधित थे, उनको हटाया गया और फिर वे बहाल हुए। डिप्टी स्पीकर साहब, हुड्डा की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए ताकि सारे मामले साफ हो सकें। इसके साथ साथ मेरा एक और निवेदन है कि जुडिशियल इक्वायरी करवाने से पहले व्हाईट पेपर शाया करवाया जाए ताकि सब लोगों के सामने सारी बातें साफ तौर पर आ सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, सदन के नेता ने जो ऐन्टी करप्शन बोर्ड बनाया है वह वाकई स्वागत के काबिल है लेकिन इसके मैम्बर सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया। वह मामला मैंने उठाया भी था लेकिन इसका जवाब श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने नही दिया। अब देखेगे कि माननीय उप–मुख्य मन्त्री महोदय शायद जवाब देते

समय इस बारे में कुछ बताएं। हमे उम्मीद है कि उन्हें इस बारे में इस सम्मानीय सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी भी चाहिए।

इससे अगली बात मैं डिप्टी स्पीकर साहब, जे० बी० टी० के बारे मे कहना चाहता हूं। जे० बी० टी० के दाखिले के समय काफी गड़बड़ हुई है। जो डिजर्विंग केसिज थे, ज्यादा नम्बरों वाले लड़के लड़कियां थी, वे तो रह गए और दूसरे भर्ती हो गए। इसलिए यह मामला भी– जनता की नजरों मे काफी गंभीर है। इसकी भी सारी जांच पड़ताल करवानी चाहिए ताकि वहां पर जो धाधले बाजी हुई है, वह हमारे सामने आ सके। यहां इस बात का भी जिकर आया था कि सारे डिवेल्प– मैट के काम बन्द हो गए हैं। जैसे मार्किट कमेटी, तावडू का मामला है। वहां बाउंडरी वगैरह सब कुछ बन चुकी है, पैसा खर्च हो चुका है लेकिन अब काम बन्द हो गया है। एक सरकार जाती है, दूसरी आ जाती है यह तो सरकार का कंटीन्युअस प्रोसैस है लेकिन यह नही होना चाहिए कि चल रहे डिवैल्पमैंट के काम ही बन्द हो जाए। काम तो चलते रहने चाहिए। इरीगेशन के मुताल्लिक तो मे पहले ही कह चुका हू कि कुछेक माईनर्ज जैसे दुबालू माईनर, बढ़ासी और लडवासी बनाई जानी है। इसके इलावा, साहबी और रिजका वगैरह नदियों पर पुल बनाए जाने बाकी हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे इस तरफ तवज्जो दे ताकि इनको पूरा किया जा सके। जहां तक पब्लिक के पैसे का सवाल है, वह डिवैल्पमैन्ट के कामी पर लगाया जाना चाहिए। तामीर के काम होने चाहिए। जहां

तक मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड को ऊपर उठाने की बात है, उसके लिए स्पैशल ग्रांट्स, दूसरे महकमों से ओवर एण्ड अबव देकर, उस की डिवैल्पमैंट की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो इलाके पीछे रह गए हैं, वे भी साथ आ जाए। हमने इसके लिए कोशिश की थी.. (विघ्न)

आवाजें: पर आपने किया कुछ नही, तैयब साहब

चौधरी तैयब हुसैनः जनता ने आप को यहां पर इसलिए भेजा है कि अगर हमारे से कोई कमी रह गई है तो आप उस को पूरा करो और हम आपसे यह उम्मीद भी करते हैं कि आप मेवात के लोगो की भलाई के लिए डिवैल्पमैंट के कामों की तरफ खास ध्यान देंगे।

इसके बाद मैं यह कहूंगा कि यहां सदन के पटल पर ला एण्ड आर्डर के बारे में भी काफी चर्चा हुई है। कई माननीय सदस्यों ने भी यहां इस बारे में बातचीत की है। भाई जय नारायण जी ने किसी थाने का जिकर भी किया है। रोहतक के कल केस का भी यहां पर जिकर किया गया। इस लिए सरकार को इस ओर तवज्जो देने की जरुरत है। बहराल एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सब–डिवीजन हैड क्वार्टज पर जुडीशियल कोर्टस हैं लेकिन नूह और फिरोजपुर झिरका में कोई जुडिशियल कोर्टस नही है। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि इस कमी को पूरा किया जाए। पिछले रुके हुए काम आप पूरे करवा दें, लोग आपको याद रखेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, पैंने पहले भी कहा था कि आजादी के बाद दीन बन्धु सर छोटूराम जी ने एक वड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया था। हरियाणा के अन्दर और पंजाव में भी उस काम को दोहराया गया और लौगों को कर्जों से राहत दिलवाई गई थी। इसी वजह से लोग उनके वहुत मशकूर है और आज वे लोग भी उनके मशकूर है जो उसे वक्त काला कानून बनाने की बात कर रहे थे।. सर छोटू राम जिस तरह से किसानों के कर्जे माफ किए थे उसकी वजह से आज उनका नाम याद किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा के पिछड़े हुए किसानों के लिए जो काम किया था। उसका व्यान मैं लफजों में नही कर सकता। उन्होंने आने वाली नस्ले। कं बहुत ही सराहनीय काम किया था। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कहना चाहता हू कि जो किसानों के कर्जे माफ करने की बात है, उसके बारे मे सदन के नेता ने जो बात कही है, उसको वजीरे खजाना इम्पलीमैंट करें, उसको दाएं बाएं करने की बात न करें। ऐसा करना ठीक नहीं है? क्योंकि वजीरे खजाना ने जो बजट स्पीच दी है, उसमें इन्होंने फरमाया है कि कर्जे मुआफ करने की बात इम्पलीमैंट की जा रही कुंए। लेकिन इन्होंने यह बात सिरे नही चढ़ाई। इस बजट स्पीच में किसानों के कर्जे माफी के बारे में कोई प्रावधान नही किया गया है। जिस दिन गुप्ता जी ने अपनी बजट स्पीच दी उस दिन इन्होंने हमारे माननीय सदस्य मोहम्मद असलम खां को बताया था कि 8 करोड़ रुपए कोआप्रेटिव बैक्स को बतौर लोन दिया गया है और दो करोड़ रुपए लैड मोर्गेज बैक्स को बतौर लोन दिया गया है।

इस बारे में तो गुप्ता जी तफसील से बता देंगे कि यह पैसा क्यों दिया गया है? लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि सदन के नेता का किसानों के कर्जे माफी के बारे में जो ख्याल है उसको पूरा करने के लिए खजाना मन्त्री उनकी मदद करें। उन्होंने लोगो के सामने जो बात कही है, वह सही हो जानी चाहिए। जो बूढ़ों को पैशन देने की बात है वह अलग बात है। यह बात तो ठीक है कि जो 65 साल से ज्यादा उमर के बूढ़े हैं, उनको पैंशन देनी चाहिए लेकिन उनको भी 4 महीने 13 दिन की पैशन मिली है। यह बात हमारे सामने आई है। इसी तरह से किसानों के कर्जे माफ करने की बात हमारे सामने आई है। यह बात हम तो समझ नही पाए हैं, कोई भी नहीं? समझ पाया है कि यह कैसे माफ करना चाहते हैं 1 इसके अलावा, मैं अर्ज करना चाहूगा कि इरीगेशन का बजट इस साल पहले से कम कर दिया गया है यानी पहले 60 परसैटं होता था। आपने उसके घटा कर 40 परसैटं कर दिया है। इस मद मे आपको इस तरह से नही करना चाहिए था। आपको देहात के लोगों के सामने अपने प्रोग्राम रखने चाहिए थे। अभी पिछले दिनों ओले पड़े थे और यह अच्छी बात हुँ कि सदन के नेता मौके पर गए और जा कर किसानों की बात सुनी, यह बडी खुशी की बात है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह जो 300 या 400 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दैने की बात है, यह काफी पहले से है। इस बारे में मेरी रिक्वेस्ट है कि इस राशि को बढ़ाया जाए क्योंकि आज हर चीज की कीमतें बढ़ गई हुं। यह 300 या 400 रुपए मुआवजा देना 1977– 78 में शुरू किया गया था और यह

इन्होंने ही दिया था इसलिए मैं चाहता हूं कि इस राशि को और बढाया जाए। इसके अलावा, मैं एस० वाई० एल० नहर के बारे में अर्ज करना चाद्रूंगा। एस० वाई० एल० नहर का जो मामला है, वह हरियाणा के लिए जिन्दगी और मौत का सवाल है। यह बात तो आप सभी महसूस कर रहे होंगे और इस बात की हमेशा डिमांड रही है कि नहर को मुकम्मल किया जाए। इसी हाउस में 20 फरवरी 1986 को बाकायदा एक रैजोल्यूशन पास किया गया था कि इसको मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा, पिछले साल के गवर्नर ऐडैरस में और बजट स्पीच में यह वात स्पैसिफिकली कही गई थी लेकिन यह अभी तक पूरी नही हो सकी है। हरियाणा प्रदेश की यह बदकिस्मती रही है कि पंजाब, जो हमारा बड़ा भाई है, वह अपने छोटे भाई के साथ बड़े भाई वाले ताल्लुक नहीं रख रहा है। जब शुरू में हरियाणा बना था, उस सम ह शाह कमिशन बैठाया गया था। उस शाह कमिशन ने हरियाणा को चण्डीगढ़ और खरड तहसील दी थी लेकिन बाद में ये इलाके नही दिए गए। उसके बाद फिर हमारे प्राईम मिनिस्टर का अवार्ड आया उसको भी पंजाव ने नहीं माना। उसके बाद फिर तीन चीफ मिनिस्टर्ज ने बैठ कर जो फैसला किया था उसे भी पंजाब वालो ने नहीं माना। नतीजे के तौर पर ऐसी बातें होती रहीं। जब मैं पार्लिया– मैट का मैम्बर था, उस समय हरियाणा के जो मैम्बर पार्लियामैंट थे, मैं उनका कनविनर था। हमने एक रैजोल्यूशन पास करके प्रधान मन्त्री को दिया था और यह कहा था कि एस० वाई० एल० नहर को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करवाया जाए। हम अव भी यही चाहते णै

कि इस नहर को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए। इसके अलावा, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नहर को सैंटर की कोई एजेंसी अपने हाथ में लेकर इसको जल्दी से जल्दी पूरा करे, क्योंकि यह हमारे हरियाणा के लिए बहुत जरूरी बात है। इसके लिए मौजूदा सरकार जो कोशिश करेगी उससे अधिक कोशिश हम भी करेंगे। हम इस नहर की खुदाई के लिए अपने एम० पीज० से भी केन्द्र पर दबाव डलवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक सूबे के हितों का मामला है, उसके लिए कोई भी पीछे नहीं रहेगा। हम तो इस मामले में आपकी मौजूदा सरकार से आगे ही रहेंगे, इस मामले में यह आश्वासन मैं आपको दिलाता है। मोहतरिम स्पीकर साहब, इतनी. बान कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हू।

श्री जय नारायण खुण्डिया (कलानौर, अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, श्री बी० डी० गुप्ता जी ने जो इस साल का बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थ न करने के लिए खडा हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, मन 1977 के अन्दर भी जनता पार्टी की सरकार सत्ता मे आई थी और उस समय भी हमारे आज के सदन के नेता चौधरी देवी लाल ही मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने मुख्य मन्त्री बनने के वाद इस प्रदेश के अन्दर जो कार्य किए थे वे बहुत ही सराहनीय थे। सबसे पहले इन्होने उस समय अपने चुनावी वायदे के अन्दर लोगों से कहा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं किसानों का सवा छः एकड तक का मालिया माफ करूंगा। इसी तरह से ट्रैक्टर्ज पर जो टोकन टैक्स था, माफ करूंगा और तम्बाकू

पर जो टैक्स लगता है, उसे भी माफ करूंगा। पहले गांव के लोग टैक्स लगने के कारण तम्बाकू बोने से बहुत डरते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि चौधरी देवी लाल जी ने उस समय सत्ता मे आते ही ट्रैक्टरों का टोकन टैक्स, सवा छः एकड जमीन तक का मालिया और तम्बाकू पर जो टैक्स लगता था, वह माफ कर दिया था। पहले कांग्रेस पार्टी हरिजनों, गरीब मजदूरो को लगातार यह आश्वासन दे ती रही कि हम आपके लिए यह करेंगे, वह करेंगे। वे बेचारे कांग्रेस पार्टी के नारों में ही उलझे रहते थे और काग्रेस पार्टी के बहकावे मे आ कर ही अब तक वे कांग्रेस पार्टी के साथ थे। कांग्रेस के समय हमारे यहां जो लैण्डलैस आदमी थे और जो मजदूरी का काम करते थे, उनको सिर्फ 5 रुपये रोजाना मजदूरी के मिला करते थे। हमने इस बारे में उस समय जब चौधरी देवी लाल जी को बताया कि 5 रुपये मजदूरी बहुत कम है, तो इन्होंने हमारी बात मानते हुए मजदूरी 5 रुपये से बढ़ा कर 15– 16 रुपये रोजाना कर दी थी। अब यह मजदूरी बढ कर शायद 19– 20 रुपये रोजाना दी जा रही हुं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नही, जितनी भी हरिजनों की या बैकवर्ड क्लासिज की चौपाले जनता पार्टी के शासन के अढ़ाई साल के दौरान चौधरी देवी लाल जी ने बनवाई थी, उतनी चौपालें कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 साल के शासन के दौरान भी नहीं बनाई थीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे नेता ने अपने शासन के अढ़ाई साल के अरसे के दौरान कांग्रेस पार्टी से 3 गुना चौपाले बनाई थी, जो एक रिकार्ड है। चौधरी तैयब साहब जी एक मौके पर बोलते हुए कह रहे थे कि

जब चौधरी बंसी लाल जी केन्द्र में रेल मन्त्री थे, उन्होंन भिवानी और हिसार में आकर कहा था कि मैं हरियाणा के लोगों के लिए एक नया तोहफा लाया हूँ। उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि हांसी के पास एक कोच फैक्टरी लगाई जायेगी और हरियाणा के 20–30 हजार आदमियों को रोजगार दूंगा। उस समय हरियाणा के लोगों को यह बात सुन कर बहुत खुशी हुई थी कि यहां के 20 – 30 हजार आदमियों को रो जगार मिलेगा। लेकिन आज मैं इन काग्रेंस के भाइयो से पूछना चाहता हूं कि वह फैक्टरी कहां गई? कांग्रेस सरकार के वजीरो ने वायदा किया था लेकिन पूरा नही कया। चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया, आज यह उसी का नतीजा है कि 90 सदस्यों के हाउस में ये केवल पांच ही चुन कर आये हैं।

इसी तरह से पलवल के अन्दर हरियाणा में भारत के प्रधान मन्त्री ने ऐलान किया था कि 403 करोड़ रुपय हम हरियाण प्रदेश को देंगे लेकिन उन्होंने वह पैसा नहीं दिया। आज दोबारा 1987 में चौधरी दे वी लाल की सरकार बनी है। यह सब संघर्ष समिति की देन है। चौधरी दे वी लाल और मंगल सैन जी ने अढ़ाई साल तक संघर्ष कया। जगह जगह जा कर इन्होंने कांग्रेस भाइयों के कारनामों के बारे में लोगो को अवगत कराया। एस० वाई० एल० के मामले में राजीव लौंगोवाल जो समझौता हुआ था, उसमें भी हरियाणा प्रदेश के साथ अन्याय हुआ। चौधरी दे वी लाल और मंगल सैन ने इस समझौते को पसन्द नहीं किया। इन

दोनो नेताओ ने विधान सभा से इस्तीफा दे कर फिर से चुनाव लड़ा क्योंकि हरियाणा प्रदेश के साथ बे –इंसाफी हुई थी। जगह जगह जा कर सभायें की रास्ता रोको आन्दोलन किया, जीन्द में बीस लाख लोगों की सभा हुई जिसमें हर एरिया के लोग पहुंचे। आज यह सब उन्ही बातों का नतीजा है। 90 विधायकों में से 85 विधायक चुन कर आये है। ये विधायक भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के है। यह सारी देन चौधरी देवी लाल की है। उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है। उन्होंने चुनाव में लोगों से जो वायदे किये थे, वे पूरे किये। बुजुर्गो को पेंशन देने का मामला हल किया। बे रोजगारों का जब भी कोई इन्टरव्यू हो, वे बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। ये सब सुविधायें दी गई। इस प्रकार से जो भी वायदे किये थे वे पूरे किये। हमारी सरकार ने बडे सराहनीय कार्य किये हैं।

12.00 बजे

डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपका ध्यान हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। चालीस साल से काग्रेंस पार्टी की हकूमत थी। इन दो वर्गो की तरफ कांग्रेस पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिश। हरिजनों के लिए जो 20 परसैन्ट रिजर्वेशन का कोटा हैं, उसे भी पूरा नही किया। क्लास वन और क्लास टू में तो रिजर्वेशन जीरो है। क्लास थ्री मे भी पांच या छः परसैन्ट ही कोटा पूरा किया गया है, उनकी पोस्टों को भी उस सरकार ने फिल–अप नहीं कया। हमारे कांग्रेस के साथी चालीस

साल तक हरिजनो के साथ अन्याय करते रहै हैं आज मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हू कि कांग्रेस हकूमत मे हमारे साथ जो अन्याय हो रहा था, वह दूर किया जाए और जो 20 प्रतिशत आरक्षित कोटा हैं, वह टाप पराईओरिटी बेसिज पर पूरा किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं रोहतक जिले का जिक्र करना चाहूंगा। जिला रोहतक एक क्रान्तिकारी जिला है जो हमेशा से कांग्रेसियों कैं लिये विपक्ष का गढ़ रहा है। इसी कारण कांग्रेसियों ने इस जिले कें साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया है। इस जिले के अन्दर कोई भी तरक्की का काम नही हुआ है। कांग्रेसी यह जानते थे कि यह जिला विपक्ष का गढ़ है और वे यहां से वोट प्राप्त नही कर सकते इसलिये उन्होंने इस जिले की उपेक्षा की है। हमारे यहां सड्कों की हालत बड़ी बुरी है। सड्कों पर गहरे–गहरे गढ्ढे हैं लेकिन उस सरकार ने सड्कों की मुरम्मत करवाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रोहतक शहर की हालत भी बहुत बुरी है। यहां तक कि एप्रोच रोड्ज भी ठीक नहीं हैं। हमारे मन्की भारद्वाज साहब यहां बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बजट के अन्दर रोहतक शहर और जिला रोहतक की सड्कों की ओर टॉप प्रायरिटी से ध्यान देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान रोहतक शहर के अस्पताल की ओर दिलाना चाहता हू जब वर्षा होती है तो अस्पताल मे दो–दो, तीन–तीन फुट पानी खड़ा हो जाता है। जनाना अस्पताल और सिविल अस्पताल के बीच में से

एक सड़क गुजरती है। यह दोनों बिल्डिंगें बड़ी खस्ता हालत मे हैं और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर सिविल अस्पताल की जमीन ज्यादा है तो जनाना अस्पताल की बिल्डिंग को बेच कर जो पैसा मिले, उससे सिविल अस्पताल की बिल्डिंग के साथ नई बिल्डिंग तैयार करवाई जा सकती है। इस प्रकार इस बिल्डिंग पर पैसा कम खर्च होगा। उपाध्यक्ष महोदय बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिविल अस्पताल रोहतक में पिछले डेढ़ साल से एक बड़ी बीमारी घुसी हुई है। (घंटी)

श्री उपाध्यक्षः आप वाईण्ड अप करिये और दों–तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जय नारायण खुण्डियाः उपाध्यक्ष महोदय, सिविल अस्पताल में पिछले डेढ़ साल से एक बहुत बुरी बीमारी बैठी है और वह बीमारी है एकस–रे मशीन की। पिछले डेढ साल से यहां की एक्स–रे मशीन खराब पड़ी है और इस एक्स–रे प्लांट पर जो महानुभाव लगे हुए हैं, वे इससे पहले बहादुरगढ़ अस्पताल में रहे थे, इन्होंने वहाँ की मशीन खराब की थी। जीन्द अस्पताल में भी इस महानुभाव ने नौकरी की और वहां की एकस–रे मशीन भी खराब की। पिछले डेढ़ साल से यह महानुभाव रोहतक सिविल अस्पताल मे डटे हैं तब से ही सिविल अस्पताल, रोहतक की मशीन खराब पड़ी है। गरीब आदमी जब एक्स–रे करवाने आते हैं तो उनको सीधा जवाब देता है कि एक्स–रे करवाने के लिये नरुला के

पास जाएं क्योंकि नरूला से इसकी मन्थली बन्धी हुई है। गरीब आदमी को 40– 50 रुपये खर्च करके एक्स–रे अस्पताल से बाहर करवाना पड़ता है। इस महानुभाव का भी कोई इलाज करवाया जाए। जहां पर भी इसने सर्विस की वहां की एक्स–रे मशीन का भट्ठा बैठाया है। वैसे भी मुझे यह महानुभाव कुछ करैक ही लगे हैं, इसलिये क्यों न इनका मैडिकल चौक–अप ही करवा लिया जाए? इससे पहले भी मैंने असैम्बली में यह कवैश्चन किया था कि इस महानुभाव का इलाज करवाया जाए।

इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कलानौर क्षेत्र के अन्दर हमे कई बातों के बारे में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहां आस पास. महम के अन्दर भी सब–तहसील है, झज्जर के अन्दर भी सब– तहसील है और बहादुरगढ़ के अन्दर भी है लेकिन कलानौर क्षेत्र ऐसा है जहां सब–तहसील नही है, जो कि होनी चाहिए। कांगेस वालों ने इस तरफ कोई ध्यान नही दिया थो उनको तो अपने मेक–अप से मतलब था। (हंसी)मै आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हू कि वहा एक तो सब –तहसील होनी चाहिए, दूसरे सब–ट्रेजरी भी होनी चाहिए। सब–ट्रेजरी की बिल्डिग बनी हुई है, गुप्ता साहब इस समय बैठे नहीं हैं, यह उनका महकमा है इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द उसका उद्घाटन किया जाए। इसके साथ साथ वहां पर कोई बसों का सब–डिपो भी नहीं है, वह भी बनाया जाए। वहां पर आई० टी० आई० भी नही है, मैं

सरकार से पुरजोर अपील करता हू कि आई० टी० आई० का स्कूल भी वहां खोला जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, इस देश को आजाद हुए 40 साल से भी ज्यादा समय हो गया बै। उस वक्त से जो गरीब आदमी अनाज मंडियों में काम करते हैं, उनकी मजदूरी वही है जो आज से 40 साल पहले थी। वे गरीब आदमी मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं इसलिये उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। अब वे अपने बच्चों का गुजारा नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे गरीब भाई जो भट्ठों पर काम करते हैं, वे गरीब हैं और उनको गरीबी सताती है। सुबह से शाम तक वे मिट्टी का काम करते हैं लेकिन अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो भट्ठे 10—15 साल से चल रहे हैं, वहां पर प्राइमरी स्कूल खोले जाएं ताकि वे लोग अपना काम भी कर सकें और अपने बच्चों कौ शिक्षा भी दे सकें। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार मुश्किल से हर साल में 10— 15 हजार आदमियों को रोजगार दे सकती होगी। पूरा तो मुझे शान नहीं लेकिन लाखों बच्चे हर साल बेरोजगार होते जा रहे हैं। उनकी तरफ भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पिछली सरकार का तो इस तरफ कोई ध्यान ही नही था क्योंकि वे लोग तो फाइव स्टार होटलों के अन्दर मौज मारा करते थे। यह सरकार गरीब किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी की सरकार है इसलिये मैं इसका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि चाहे हमें जितना भी कर्जा लेना पड़े, हमें अपने प्रदेश के अन्दर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। अगर

बैकों से कर्जा लेकर 4– 5 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाए तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। नौकरी के मामले में तो हम सब को सुविधा प्रदान रही कर सकते। अब जो कडक्टरो की पोस्टों का मामला चल रहा है, इनके लिए 85 हजार ऐप्लीकेशंज आई है और 500 लोग लेने है। एम० एल० एज० और मन्त्रियो की खाट खड़ी हुई पड़ी है। आज एक एक के पास 3–3 सौ, 5–5 सौ और 9–9 सौ नाम आये हुए हैं।

श्री उपाध्यक्षः क्या सिर के बाल इसलिये उखड़ गये हैं? (हंसी)

श्री जय नारायण खुडियाः मैं यह कहना चाहता हू कि बड़ी–बड़ी फैक्ट्रीज हरियाणा में लगायी जाये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एम्पलाईज की हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, एम्पलाईज ने जी तोड़ कर इस सरकार की मदद की है। बंसी लाल की सरकार ने बोट क्लब पर जो एम्पलाईजं के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उसी के नतीजे के तौर पर एम्पलाईज हमारे साथ हैं। उनकी जो मांगे हैं, वह पूरी की जानी चाहियें। खास कर पब्लिक हैल्थ और पी० डब्ल्यू० डी० के विभागों में, 10– 10 या 12– 12 साल से वर्कचार्च पर कफी एम्पलाईज लगे हुए है, मेरी सरकार से अपील है कि उनको जल्दी से जल्दी रैगुलेराईज किया जाये। इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अन्त में

मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हू। धन्यवाद।

श्री भाग मल (सढौरा–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आज इस सदन में पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, ने जो यह बजट पेश किया है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हू। इसको पढ्ने से यह पता लगता है कि इन्होंने कितनी मेहनत बजट अनुमान तैयार करने में लगायी है। हमारे यहां इस साल 1988–89 का 600 करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया गया है, इसमें केवल 36.32 करोड़ रुपये के घाटे का प्रोवीजन है। मैं यह समझता हूं कि हमारी सरकार जो मेहनत कर रही है, अपनी सूझ–बूझ से आइन्दा साल में किफायत करके यह घाटा पूरा कर लेगी। हमारे यहा कोई भी किसी किस्म का घाटा नही बचेगा। इस सरकार ने इस बात की बड़ी कोशिश की कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जायें। पिछली बार बड़ा भारी सूखा पड़ा। सूखा इतना पड़ा जिसकी वजह से लोगों को पानी, मवेशियों को चारा और इसी तरह की दूसरी चीजें मुहैया करवाने के लिये लोगों को काफी पैसा वर्ष करना पड़ा। हमने सैडल गवर्नमैंट को यह कहा और कोशिश की कि वह हमें कुछ पैसा दे लेकिन उसने हमें जीरो के बराबर पैसा दिया। हमारी मांग बहुत थी उन्होंने अलावपूर्ण स्थिति में भी हमे कोई मदद नहीं की। हमने यह भी

कोशिश की कि हमें 100 करोड़ रुपया लोन के रूप में ही मिल जाये लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने वह भी नही दिया। ऐसी हालत में यह सरकार सूखे की मारी होने के बावजूद भी लोगों को सुविधा देना– चाहती है। हमने अपने माता–पिता को जो बूढ़े हो चुके हैं, पैन्शन दी है और अपने नौजवानों को जो इन्टरव्यू के लिये बाहर जाते थे, की ट्रैवलिंग की इजाजत दी है। ट्रैवलिंग में भी बड़ा भारी खर्च होता है और इससे सरकार को लास ही होता है। हमारे एक साथी ने कहा कि हमने पहले से किराया बढ़ा दिया है। हम यह कहते हैं कि यह कोई नई बात नही की है। इनकी सैन्ट्रल सरकार बजट आने से ठीक पहले किराये बढ़ा देती है और फिर भी टैक्स लगा देती है। हमारी यह कोशिश है कि हमारे अनुमान पूरे होने चाहियें। मैं समझता हूं कि अगर किराया बढ़ाया भी गया है तो कोई बुरी बात नही की गयी है। यह जो बजट पेश किया गया है, इसके अन्दर कोई टैक्स नही लगाया गया है। इसके लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं

अब मैं एस० वाई० एल० के बारे मे कहना चाहता हू। 1981 में इसके लिए 176 करोड रुपए का प्रावधान था और 1988 – 89 के लिए 366 करोड़ का प्रावधान किया गया है मैं पूछना चाहता हूं कि इतना पैसा कहां से पूरा करेंगे? हम सैडल गवर्नमैंट से पैसा लेना चाहते हैं लेकिन वह हमारे साथ कोआप्रेट नही करती। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए लाइफ लाइन है। इसके बगैर हम रह नहीं सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, इस साल भंयकर

सूखा था अगर एस० वाई० एल० का पानी हमें मिला होता तो हम सूखे का मुकाबला आसानी से कर सकते थे। सैन्ट्रल गवर्नमैंट की यह कोशिश है कि हमारी सरकार फेल हो जाए लेकिन हमें विश्वास है कि चौधरी देवी लाल और दूसरे मिनिस्टर्ज जितनी कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी सरकार फेल नहीं होगी और केन्द्रीय सरकार का मंशा कभी पूरी नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ को रोकने के लिए 1987– 88 में सात करोड़ रुपया रखा गया था और वर्ष 1988– 89 में 13 करोड़ रुपया रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस एरिया में रहता हूं जहां बारिश होती है लेकिन पानी ठहरता नही है। सारा पानी नीचे वह जाता है इससे जमीन का इरोजन होता है। उस ऊंचे इलाके में नहर नहीं जा सकती। वहां पर छोटा मोटी इन्तजाम नलकूपों का था लेकिन जमीन में जो पानी का जखीरा था, वह भी कम हो गया। इस वजह से नलकूप फेल हो रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, छछरौली, सढ़ौरा, नारायणगढ़ और बिलासपुर प्लौक्स में पानी की बहुत किल्लत है। यह ठीक है कि बारिश अब हो गई है और कुछ माहौल बदल गया है। लेकिन मवेशियो के लिये पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, अम्बाला जिला को सूखे से निकाल दिया गया है लेकिन वह इलाका ऐसा है जहां ने तो बारिश हुई है और न ही डीप ट्यूबवैल्ज काम कर रहे हैं क्योंकि पानी का लैवल नीचे चला गया है। इससे लोगों को बड़ी दिक्कत है। बारिश न होनें से फसल नहीं बोई गई है। मेरी

सरकार से प्रार्थना है कि इस तरफ सरकार ध्यान दे और लोगों की तकलीफ को कम करे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे इलाके के लोग फौरैस्ट विभाग के लोगों से बहुत परेशान है। फौरैस्ट विभाग के लोगो ने मेरे इलाके में नाकाबन्दी कर रखी है। अगर कोई अपनी लकड़ी उगाता है और काटना चाहता है तो वे लोगों को काटने नही देते। अगर कोई काटने की इजाजत मांगता है तो महीनों लग जाते है। पब्लिक के लोगों को फौरैस्ट विभाग. के लोगो से बहुत ज्यदा गरज है। मै कहना चाहता हू कि फौरैस्ट विभाग के कर्म चोरी लोगों के साम कोआप्रेट नही करते। एक छोटा सा कर्मचारी भी लोगों को नाजायज तंग करता है और लोगों से पैसा बनाने की कोशिश करता है। अगर कोई गरीब आदमी एप्ली– कैशन देता है कि उसको पैसे की बहुत तंगी है और वह भूत्वा मर रहा है तो उसको लकड़ी काटने की इजाजत नही दी जाती और दूसरी तरफ अपने आप चोरी से लाखो रुपए की लकड़ी कटवा कब बेच देते है। मैं सरकार के नोटिस मे लाना चाहता हूं कि इस विभाग के एक सीनियर औफिसर का भाई, बेनामी बिजनैस किसी कौंट्रेक्टर के नाम से कर रहा है और लाखो रुपए कमा रहा है। दूसरी तरफ लोग सूखे के कारण भूख से मर रहे हैं लेकिन उनको अपनी लकड़ी नही काटने दी जाती।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके मे से मारकंडा सरस्वती, सोम और टांगडी नदियां गुजरती हैं जिससे हजारों एकड़ जमीन

में कटाव हो जाता है। इस कारण किसान वहा पर खेती नहीं कर सकते। अगर छोटे–छोटे बांध बना दिए जाएं तो बारिश का पानी रोका जा सकता है। वह पानी खेती के लिए भी काम आ सकता हे और मवेशियों के काम भी आ सकता है। पानी वाली–उत्तमवाली मे एक छोटा सा बाध बनाकर पानी इकट्ठा किया गया था। वह तजुर्बा बहुत ही कामयाब रहा। इससे लोगो की समस्या काफी हद तक हल हो गई। मेरी प्रार्थना है कि इस तरह के छोटे–छोटे बांध काफी बनाए जाएं। ऐसा करने से फसल को भी पानी मिल जाएगा पीने के पानी की सुविधा भी हो जाएगी और मवेशियों को भी पानी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ बाढ नियन्त्रण भी हो सकेगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब बिजली की बात ले लीजिएगा। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने काफी सराहनीय काम किये हैं। बिजली पैदा करने के लिये बहुत पैसा खर्च किया है और कर भी रही है। इसके लिये हमारे योग्य मिनिस्टर महोदय, श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने ठीक ही अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है लेकिन इसके बावजूद भी बिजली की बहुत सारी समस्याएं है, लोगों को अब भी बिजली पूरी नहीं मिल रही है। मेरे सढ़ौरा हल्का में एक जौली जगह है। वहां पर पावर सब–स्टेशन लगाया जाना था। वहां पर पहले 33 के० वी० सब–स्टेशन बनना था लेकिन बाद में पता नहीं सरकार ने अपना विचार बदल लिया और यह कहा कि यहां पर 66 के०वी० का सबस्टेशन बनाया जाएगा।

आज तक वहां पर कोई भी सब–स्टेशन नहीं बनाया गया और जो मशीनरी वहां पर आई थी, वह भी उठा ली गई है। इस सब–स्टेशन के न बनने से उस इलाके की हालत बड़ी दयनीय है और लोगों को बिजली न मिलने के कारण काफी मुशकलातों का सामना करना पड रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार उस सबस्टेशन को जल्दी बनाये ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। यह सबस्टेशन बनना बड़ा ही आवश्यक है जब तक यहां पर बिजली का कोई खास प्रबन्ध नहीं होता तब तक किसी और जगह से इस इलाके को बिजली सप्लाई करवाई जाए। जैसे मुलाना को कुछ दूसरे एरियाज के साथ जोकर बिजली सप्लाई की जा रही है उसी तरह से यहां भी बिजली की सप्लाई किया जाए। केवल नारायणगढ़ से सारा इलाका सर्व नही हो सकता। इसके साथ साथ मैं यह भी बनाना चाहता हूं कि उस इलाके में पानी इतना डीप है कि आम आदमी अपना ट्यूबवैल नहीं लगा सकता। अगर ट्यूबवैल्ज लगाते भी हैं तो बिजली नहीं मिलती। इसलिये वह इलाका बिजली न मिलने के कारण बुरी तरह से सूख रहा है और हमारा इलाका अभी भी सूखे की लपेट में है। दूसरी जगहों पर सूखे के कारण सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी गई हैं, वह हमारे इलाके को नहीं मिली हैं। एक तो हमारा वैसे ही वह प्रिया बैकवर्ड है और दूसरे इस तरह की भेदभाव की नीति के कारण हम और बैकवर्ड हो गये हैं इसलिये मैं चाहता हू कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे अगली बात मैं कृषि से सम्बन्धित करना चाहता हूं। आज कृषि पर लगभग 78 परसैन्ट की आबादी निर्भर करती है और यह भी सही है कि हमें खेती से 42. 8 परसैन्ट आमदनी होती है। खेती के काम को बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है और इसके लिये हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो काम किया है वह सचमुच सराहनीय है। जहां जहां ओलावृष्टि हुई है, वहा वहां चौधरी देवीलाल जी स्वयं गये और लोगों को अपने हाथों से दो दो सौ रुपये पर एकड़ के हिसाब से राहत दी है। अब स्पैशल गिरदावरी की बात भी हो रही है यह अच्छी बात है। ऐसी बातें पहले कभी किसी सरकार ने सोची तक नही थीं। यह सचमुच सराहनीय बात है। डिप्टी स्पीकर साहब जहां इस सरकार ने ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुक्स के कारण लोगों को जो मुआवजा दिया है वह पर दूसरी कई जगहों पर लोग इस मु आ बजे से वंचित रह गये हैं। जगाधरी के अन्दर महामारा एक जगह है। उस एरिया मे 1986 में ओलावृष्टि हुई थी। उस वक्त कांग्रेस सरकार थी लेकिन आज तक उस एरिया के लोगो को उस बरबादी का पैसा नही मिला कुए। यह सारा कुछ रिकार्ड मै है। पैसा स्वीकृत हुआ था, पता नहीं लोगो को क्यों नही दिया गया। आप अन्दाजा लगा सकते है कि वहां पर लोगों की आज क्या दशा होगी उस इलाके में आज भी सूखे का असर पडा हुआ है लेकिन फिर भी लोग. बुवाई कर रहे हैं। उन बेचा रो के पास अपनी जमीन में खाद डालने के लिये पैसे नहीं हैं। जगाधरी एरिया में जो ओला– वृष्टि से नुकसान

हुआ है, उसके लिये तो पैसा मन्जूर हुआ है, उसके लिये मैं चाहूगा कि डी० सी० वगैरह को पैसा ठीक समय पर बांटने के आर्डर दे देने चाहिये ताकि वह पैसा जल्दी ही लोगों तक पहुंच सके और लोग उससे पूरा पूरा फायदा उठा सकें। अगर इस तरह से सरकार की ओर से रा हत मिलती रहे गी तो लोग अपने खेतों में अच्छी फसल उगा सकेंगे और ज्यादा पैदावार कर सकेंगे। इस लि ये मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे इन सुझावों पर अवश्य गै करे। उपाध्यक्ष महोदय, इनके अलावा मुझे अपनी सरकार से एक गिला भी करना है। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हू कि हमारे ऐग्रीकल्चर डिपाट मैट के कर्मचारियो की फौज की फौज फील्ड में है। जहां देखो वहां कोई ऐग्रीकल्चर सब–इस्पैक्टर है कोई ए० डी० ओ० है, लेकिन आप मौके पर जा कर देंखे उनको खेती के बारे में कुछ भी पता नही है। मैं समझता हूं कि किसानो को अपनी खेती के बारे मे उनसे ज्यादा पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसानों की सहायता के लिये सरकार ने फील्ड में एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के जो कर्म चारी भेजे हुए हैं, उनको खे ती के बारे में कुछ भी पता नही है। वे अपने दफतरो में ही बैठे रहते हैं, फील्ड में जा कर यह नही देखते कि खेतों मे जो गेहूं की फसल खडी है, उसकी बाल काली क्यो पड़ गई है और उसको क्या बीमारी लग गई है? उल्टा वे जमींदारों से पूछते हैं कि यह गे हूं को कौन सी बीमारी लग गई है और आप इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हो? इन कर्मचारियो को पे स्केल भी सबसे ज्यादा मिले हुए हैं। वे किसानों के लड़के हैं,

एग्रीकल्चर की ट्रे निंग ले कर जाते हैं। वे सब हमारे है, हम उनके हैं लेकिन वे खेतों में जा कर यह नहीं देखते कि किसान अपनी फसलों की बीमारी की रोकथाम के लिए क्या उपाय करें? इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार अपने अधिकारियो को हिदायतें दे कि वे मौके पर जा कर देखे कि ये कर्मचारी वहां पर क्या करते हैं।

इसी तरह से मैं पशु पालन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। पशु पालन भी हमारे किसानो के लिए बहुत जरूरी है। पिछले साल हरियाणा में 40 नए पशु चिकित्सालय खोलने का सरकार का विचार था और मैं समझता हूं कि वे खोल भी दिए हों गे। इनके अलावा भी सरकार पशु चिकत्सालय और खोलने जा रही है। हमारे आदरणीय मन्त्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी यहां हाउस में बैठे हैं मैं उनसे कहूंगा कि ज्यों ज्यों सरकार के पास साधन बड़े त्यों त्यों पशु चिकित्सालय ज्यादा से ज्यादा खोले जा ने चाहिएं। मैंने अपने हल्के के बारे में दो तीन जगहों के लिए डिमांड की हुई है। वहां पर कोई पशु चिकित्सालय इन जगहों पर नहीं हैं।

अब मैं मछली पालन के बारे में कहना चाहूंगा। लोग मछली पालन का काम करना चाहते हैं लेकिन इस विभाग के कर्मचारी एक जगह नही बैठते कोई जगाधरी में पलेगा तो कोई सढौरा में मिलेगा यानी बड़े बड़े शहरों में बैठे रहते हैं। उनके पास वहां पर जाओ और इस बारे में जानकारी लो, वे जगह जगह

जा, कर इस बारे मैं कोई जा नकारी नहीं दे ते। मैं सरकार से अपील करूंगा कि सरकार उनको हिदायतें दे कि वे गाव गांव में जा कर लोगों से सम्पर्क करें और उनको रास्ता बताए कि यह काम कैसे किया जा सकता है? यदि वे गांव गांव में जा कर लोगों से सम्पर्क करेंगे तो लोगों को सहायता मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इसके लिये जो कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं उन को हिदायतें दी जाएं कि वे लोगों तक जाएं, लोगों को समझाए और सम्पर्क करें ताकि लोग इस काम में तरक्की कर सकें।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहूंगा। यह बात ठीक है कि 1987 – 88 के लिए 445 नई बसें खरीदी गई हैं और 705 बसें और सरकार खरीदने जा रही है। इसके अलावा हरियाणा के अन्दर मिनि बसें भी चलाई जाएंगी। जहा पर ऐसे रोड हैं, जिन पर बड़ी बसें नही चल सकती वहां मिनि बसे चलाई जाएंगी। ये मिनि बसें चलाने वाली बात सरकार की बहुत अच्छी है इससे लोगों को काफी सुविधाएं मिलेगी। बहरहाल, हम लोग चाहते हैं कि जहा सड़के बनी हुई हैं वहां पर बसें जरूर चलनी चाहिएं। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कों के छोटे छोटे टुकड़े बने हुए नही हैं जिसकी वजह से सड़कों का लिंक ठीक नही है। इसी कारण लोगों को कई कई मील का चक्कर काट कर आना जाना पड़ता है, जिससे उनको काफी तकलीफ होती है। यदि मिनि बसे चलेगी

तो लोगों को आने जाने में और अपना माल ले जाने और लाने में सहूलियत होगी। उनको ड्राईवर के तौर पर और कंडक्टर के तौर पर नौकरी की सुविधा भी मिलेगी। मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो मिनि बसे चलाने का सरकार का विचार है, इसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट किया जाए बल्कि, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। इसके

अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि सढौरा से जगाधरी–बिलासपुर रोड पर बसें चलती हैं लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े गांव है जहां पर बसों की सर्विस नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि उन गांवों के लिए भी बसें चलाई जाएं। हम जब महकमे वालों से जा कर कहते हैं कि बसे चलाई जाए तो वे कहते हैं कि हमारे पास बसें नही है। मैं समझता हूं कि मिनि वसें चलाने का सरकार का यह कदम तरक्की की तरफ है और लोगों को सहूलियत देने के लिये है। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां जहां पर बसें नहीं चल रही है वहां–वहां पर बर्मे अवश्य चलाई जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में बोलना चाहता हूं। यह तो सभी को पता है कि हरियाणा में हर जगह पर सडकों का जाल बिछा हुआ है। अभी भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर सड़कें नही बनाई गई हैं। यदि सड़कें बनाई हैं तो उन को एक दूसरे गांवों के साथ जोड़ा नही गया है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यदि प्रमावली से जामनावास के बीच जो पौन किलोमीटर का टुकड़ा है, अगर इसे

बना दिया जाये तो एक लम्बे एरिया को फायदा हो सकता है और इस पर एक पूरी बस चल सकती है। इसी प्रकार से महेश्वरी से पिंजौरा का भी पौन किलोमीटर का टुकड़ा है यदि इस को बना दिया जाये तो जगाधरी आने जाने वाले लोगों का 25 कि० मी० का रास्ता कम हो सकता है। अब लोग मुस्तफाबाद से होते हुए जगाधरी आते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस टुकडे को अवश्य पूरा किया जाये ताकि लोगों को 25 किलोमीटर का जो नाजानायज सफर करना पड़ता है, वह बच सके। मेरे हल्के के गांवों का ब्लौक हैड क्वार्टर विलासपुर पड़ता है। जब बरसात के दिनों में बारिश होती है तो लोगों को बिलासपुर आने के लिए बहुत लम्बा चक्कर काटना पड़ता है। जिस सडक के बनाने के बारे में मैंने कहा है यदि इस टुकड़े को बना दिया जाये तो लोगों की काफी समस्याएं जैसा मैंने जिकर किया है, हल हो सकती हैं। इसी प्रकार बहुत से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जहां आधा–पौना किलोमीटर सड़क बनाने से लोगों की समस्याएं कम हो सकती हैं और उनका रास्ता कम हो सकता है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कल्याणा से ठाकुरपुरा का दो किलोमीटर, मिर्जापुर पाठका से बेर खेड़ी व मिलखानवाला से मंगसौर आधा आधा किलोमीटर, कोटला से बिजोली सवा किलोमीटर, भूखडी से नारायणगढ़ व जगाधरी एक एक किलोमीटर का सडक का टुकडा यदि बना दिया जाये तो इन सभी गांवों के लोगों को एक दूसरे के गांवों मे आने जाने के लिए या किन्हीं दूसरे स्थानों पर जाने के लिए रास्ता बहुत कम हो सकता है। मेरी सरकार से और

संबंधित मंत्री जी से प्रार्थना है कि इन सड्कों को अवश्य बनाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय जब मैं कुछ बाते पुल बनाये जाने के बारे में कहना चाहता हूं मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे हल्के में से जो मारकंडा नदी और दूसरी नदियां बहती है, यदि उन पर पुल बना दिए जायें तो लोगों को बरसात के दिनों में बहुत सी सुविधायें आने–जाने के लिए हो सकती हैं। अब पुल कही–कहीं पर हैं। इस समय लोगों कोअपना रास्ता कवर करने के लिए कई कई किलोमीटर तक इन पुलों पर से गुजरने के लिए तय करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एक तो सोम नदी पर पुल बना दिया जाये। इस समय जो पुल बना हुआ है वह काला आम के पास है। अब वहां के लोगों को नारायणगढ़ और सढौरा आने के लिए बहुत लम्बा फासला कवर करना पड़ता है। यदि मारकंडा नदी पर भी पुल बना दिया जाये तो सरकार की बहुत मेहरबानी होगी। सगरानी नदी पर पुल बनाने के लिए 1978 में काम शुरू हो गया था लेकिन उस समय बाढ़ आने की वजह से काम बंद हो गया था। उस बाढ़ से उस पुल की एक वाल गिर गई थी। दूसरी वात तो अभी भी खड़ी हुई है। हम लगातार कोशिश करते पे हैं कि वह पुल जल्दी से जल्दी बन जाये लेकिन आज तक वह पुल बन नही पाया है। हम कांग्रेस के शासन में हो इस पुल को बनाये जाने की लगातार कोशिश करते रहे हैं लेकिन उन्होंने हमारी बात की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया और

आज तक वह पुल बिना बने पड़ा हुआ है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अब तो हमारी अपनी सरकार है इसलिए अब इस–पुल को अवश्य बना दिया जाये। इस संगरानी पुल के बनाये जाने से लडकियो को भी स्कूलों में आने–जाने के लिए काफी आसानी हे सकती है। इसी प्रकार से सामनदी पर मलिकपुरा–रंजीतप्रुरा गांव के पास भी एक पुल बनाया जाये ताकि वहां के लोगों को भी आसानी हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कैं नेता ने चुनाव घोषण पत्र में कहा था कि यदि हमारी सरकार आयी तो हम नगरपालिकाओ का चुनाव करवायेंगे। इस वायदे को सरकार नें पूरा भी किया है। मेरे हल्के में सढौरा नगरपालिका का चुनाव दूसरी नगरपालिकाओं के साथ नहीं हुआ था क्योंकि उस का केस कोर्ट में चल रहा था। अब मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि कोर्ट से वह केस क्लीयर हो गया है इसलिए वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव करवा दिए जाएं ताकि यहां के लोकल लोग अपना काम स्वयं कर सकें। हमारा सढौरा का इलाका एक बैकवर्ड एरिया है। वह पहले हिस्टोरिकल प्लेस होता था। हिस्टोरिकल प्लेस तो अब भी है लेकिन अब उसकी वह शानो–शौकत नही रही जो पहले हुआ करती थी। इस बारे मे मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर जो सड़कें बनानी हैं या ड्रेनें बनानी हैं, वे जल्दी से जल्दी बनायी जायें। मेरे हल्के में कोई पैसा लोगों को ऐड के रूप में नही दिया

गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर कुछ पैसा ऐड के रूप में देकर जों टूटी फूटी सड़कें हैं, उनको ठीक करवाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों का जिकर करना चाहता हूं। मेरे हल्के सढौरा में एक छोटा सा हस्पताल है। उस की बिल्डिंग एक बार गिरने को हो गई थी लेंकिन बाद में उसे, ठीक करके गिरने से बचा लिया गया। इस बारे मे मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सढौरा और बिलासपुर में 30— 30 बैड्ज के दो हस्पताल अवश्य बनाये जाने चाहिएं। दूसरें सढौरा में हस्पताल तो अवश्य खोल रखा है लेकिन उस में कोई डाक्टर बैठने या ठहरने के लिए तैयार नहीं होता। मै सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार लोगों की सुविधा के लिए हस्पताल खोले और स्टाफ के ठहरने का अच्छा इन्तजाम करे। इसी तरह लखनौर में आयुर्वेदिक डिस्पैसंरी तो खोली हुई है लेकिन इस में कोई डाक्टर ठहरने के लिए तैयार नही होता। इस संबंध में भी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस दिशा में ध्यान दिया जाये और वहां पर डाक्टरों को भेजा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जन स्वास्थ्य सम्बन्धी बातो पर चर्चा करते हुए आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हू कि मेरे क्षेत्र में भट्टूआला योजना को तैयार किया जाये। इस योजना के अन्दर 6—7 गांवों का चक है। इन गांवों के लोंगों के लिए पीने के पानी का कोई प्रबंध सरकार की तरफ से अभी तक नही हुआ है। मैंने भट्टूकलां योजना को पूरा कराने के लिए कई बार

डी० सी9 को डी०ओ० लैटर्ज भी लिखे हैं और संबंधित मंत्री जी से भी प्रार्थना की है लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कदम आगे नही बढाया गया है। इन गांवों में पीने के पानी की बहुत समस्या है। वहां के कुओं में पानी नही है। वहां पर एक जमींदार ने एक खेत में अपना टयूबवैल लगाया हुआ है। 6– 7 गांवों के लोग वही से पीने का पानी ले जाते हैं। उन गांवों के लोगों ने एक टैंकर हिमाचल से, कही से लिया हुआ है। आसपास के लोग उस टैंकर को ट्रैक्टर से जोड़ कर अपने लिए पानी ले जाते हौ लेकिन मेरे द्वारा बार बार अनुरोध करने पर सरकार ने अभी तक ध्यान नही दिया है। कृपा करके वहां पर पानी का प्रबन्ध किया जाये और रिग मशीन भेज कर ट्यूबवैल बोर किया जाये।

इन सारी बातों को कहते हुए अन्त मे एक वात कहूंगा कि जो ओल्ड ऐज पैन्शन सरकार ने दी है, यह बहुत अच्छा काम किया है। यह करना भी जरूरी था। बहुत सारे लोगों को पैन्शन मिल रही है लेकिन बहुत जल्दी में इस स्कीम को लागू करने से इसमें कुछ कमियां रह गई हुँ। जो लोग पैन्शन डिजर्व नही करते थे उन्होंने फार्म भर दिये और वे पैन्शन ले गये। अब उनसे रिकवरी की जा रही है लेकिन मैं एक बात और अर्ज कर दू कि अभी और भी छानबीन करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो किसी वजह से फार्म नही भर सके थे, उन लोगों के फार्म भरवाये जाने चाहिए। उन लोगों को बैक डेट से पैन्शन मिलनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री (राजौद): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय उप–मुख्य मती महोदय ने जो बजट पेश किया है, यह बहुत ही अच्छा बजट है। आप को पता है कि जब हम जीत कर आये हैं तो हमारी सरकार भी पापुलर है और पापुलर बजट ही पेश करना था। ऐसी मैं उम्मीद करता था। अपोजीशन के साथियों ने यह कहा कि इस सरकार ने लोगों को खास रियायतें नहीं दी, यह केवल कहने मात्र की बात है। उन्होंने वैसे ही कह दिया। मैं संसदीय मामलों के मती जी से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में जब कभी भी सम्बोधन करें वे इनकी सरकार कह कर न करें। इनको कुछ न कहा जाये। इनको बोलने के लिए पूरा समय मिलना चाहिए। यह अच्छी परम्परा है। डिप्टी स्पीकर साहब और स्पीकर साहब को मैं भी बधाई देता हूं कि वे भी उन्हें पूरा समय देते हैं उप–मुख्य मती महोदय ने जो 1988–89 का बजट पेश किया है, यह बहुत ही सराहनीय है और इस सरकार से लोग यही उम्मीद करते थे। मेरे से पूर्व वक्ताओ ने भिन्न भिन्न महकमों के बारे में अलग अलग बाते कहीं हैं लेकिन जो हरियाणा स्टेट के लिए बहुत जरूरी बातें हैं, उनके बारे में मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए इस प्रदेश में शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है। सरकार ने एक दो मदों में

खर्चे का प्रोविजन कम किया है। शिक्षा की मद में खर्चे का प्रोविजन कम किया है, इसके लिए ज्यादा पैसा होना चाहिए। मैं तो यह भी अनुरोध करूंगा कि हर हल्के मे कम से कम एक माडल स्कूल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जब तक समानता नही होगी तब तक देहात के बच्चे कम्पीटीटिव ऐग्जाम में पास नहीं हो सकते। जो बच्चे शहरों और अच्छे विद्यालयों से आते हैं, वही आगे आने है। नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यह दूर–दराज के इलाकों में की जाती है। वे ऐसी जगहों पर खोले जायें जहां समान शिक्षा के आधार पर वे अपने स्तर को ऊंचा कर सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, चुनाव के बाद एक बड़ी समस्या हमारे सामने आई। वह समस्या है बेरोजगारी की। अगर किसी विधायक के पास करीब 100 आदमी मिलने को आए तो उनमें एक दो व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो काम की बात करते है या किसी सामूहिक समस्या का जिक्र करते हैं। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि लड़के को कही फंसा दो, नौकरी लगवा दो। लोग बेरोजगारी से तंग आए हुए हैं और इसी बेरोजगारी के कारण ही अपनी औलाद से दुखी हैं।

इस समस्या का समाधान तब तक नही हो सकता जब तक हम कोई ऐसी योजना निर्धारित न कर लें जिससे प्रत्येक हल्का में कम–से–कम 5000 रोजगार उपलब्ध हो सकें। एक और बड़ी समस्या जो हमारे सामने आई है, वह पै चिकित्सा सुविधा

की। प्रत्येक गांव की स्थिति को देखते हुए डाक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए। अक्सर गांवों मे लेडी डाक्टर नहीं होती डॉक्टरों से ही काम लिया जाता है। वहां पर लेडी डॉक्टरज का होना भी बेहद जरूरी है। गांवों मे जब कभी ऐसा मौका आता हे तो हस्पतालों में लेडी डॉक्टरज नहीं होती। प्रसव आदि के समय कई बाते ऐसी होती हैं जो औरतें डॉक्टर से नहीं कर सकती। ऐसे समय पर उन्हें लेडी डॉक्टर की जरूरत होंती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक गांव में ट्रैण्ड दाई या लेडी डॉक्टर जो भी उपलब्ध हो, की नियुक्ति की जानी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने सिचाई की है। बहुत से खेत सूखे पड़े हैं जहां पानी नहीं पहुंच पाता। हमारे पास लोग बार–बार रिप्रैजैंट करते हैं कि सिंचाई की कोई व्यवस्था करें लेकिन हम कोई व्यवस्था नही कर पाते। सिंचाई की व्यव्स्था के लिए बजट में ज्यादा पैसे का प्रावधान करवाया जाना चाहिए। कई गांव ऐसे है जहां नहर मे ट्यूबवैलों की व्यवस्था है, ऐसी जगहों पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की ओर ध्यान देना चाहिए। आने वाले वजट में चिकित्सा सुविधायें, सिंचाई व्यवस्था और बेरोजगारी मिटाने की जो समस्याएं है, उनको हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय इसके इलावा एक–दो छोटी–मोटी बातें मेरे हल्के की हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना

चाहता हू। अलेवा मण्डी एक परचेज सैन्टर है जो बीच में पड़ता है। इसकी तरफ कभी ध्यान नही दिया गया। मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सैटर को मंडी का पूरा दर्जा दिया जाये। राजौन्द कांस्टीव्युएंसी के कुछ गांव जीन्द में पड़ते हैं और कुछ सफीदों मे पड़ते हैं। 15 गांव पिलुखेड़ा की मार्कीट कमेटी में पड़ते हैं और 28 गांव जीन्द मार्कीट कमेटी मै आते है 1 जो पैसा सैस या मार्कीट फीस द्वारा आता है, वह दूसरी जगह चला जाता है और इसमें इसके लिए पैसे का कोई प्रावधान नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन 15 और 28 गांवों को मिला कर अलग से एक मार्कीट कमेटी बना दी जाए। कुछ गांव अलेवा से चारों तरफ एक जैसी दूरी पर पड़ते है। हमारा यह ब्लॉंक जिला कुरुक्षेत्र के एक किनारे पर पड़ता है मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एडल्ट एजुकेशन, बी०डी० पी० ओ० आदि के दफ्तर यहा खोले जाएं। इसी प्रकार से एक पुलिस स्टेशन है जो बिल्कुल ऐक सिरे पर पड़ता है। वहां पर स्टाफ की कमी है उसे पूरा किया जाए। एक बी० डी० पी० ओ० का दफतर है, और भी कई दफतर हैं। मैं आपके द्वारा मरकार से अनुरोध करूंगा कि तमाम दफतर एक सैटरल प्लेस में ला दिए जाए। वहां अभी सरकार ने किसी भवन का निर्माण नही किया है, नई बिल्डिंग बननी है। वह इलाका भी ऐसा खुश्क है कि अगर जमीन एक्वायर भी हो जाए तो भी किसानों को कोई फर्क नही पड़ेगा। इसके अलावा मैं यह भी मांग करूंगा कि वहां पर एक सद–तहसील का दफतर वनाया जाए और एक नायब तहसीलदार

वहां बैठाया जाए। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)स्पीकर साहब, 11– 12 गांव मेरी राजौंद कांस्टीच्यूएंसी के पीलुखेड़ा में पड़ते हैं। पीलुखेड़ा में एक पुलिस चौकी है। उसके चार पाच गाव जदि की तरफ है। और कुछ दूसरी तरफ. पड़ते है, यानी उप इलाके के गांव कई जगह बिखरे हुए है। मैं सरकार ले अनुरोध करूंगा कि इन सब गांवों को राजौद कांस्टीच्यूएसी में लाकर नउ ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए ताकि लोगों के सारे काम एक ही जगह पर हो सकें। अब किसी को करनाल जाना पडता हैं, किसी को कैथल जाना पडता। इस तरह से लोगो को परेशानी होती हैं। कई जगह इस हल्के के थाने भी बंटे हुए हैं।

स्पीकर साहब, अब मैं आपके द्वारा आई० पी० एम० साहब से अनुरोध करूंगा कि एक दो माइनर हैं, जैसे हुसैनपुर माइनर है। इसका आफ टेक 23 हजार फीट है, इसकी एक्सटैन्शन होनी गै जो पहले ही मंजूर हो चुकी है। इसी तरह से एक माजरा पेगान माइनर है जिसका कमांड एरिया एक हजार एकड़ है, यह भी सैकंशंड है। मैं चाहूंगा कि इन पर जल्दी काम चालू करवाया जाए। स्पीकर साहब, एनीमल हसबैंडरी मिनिस्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ गांव बिल्कुल एकांत में और दूर दराज के इलाके में पड़ते हैं जैसे कुछराना खुर्द, कुछराना कलां, बधाना, थुवा, सांडिंल और थाल हैं। ये चार पांच गांव करनाल में पड़ते है। मैं अनुरोध करूंगा कि इन को करनाल से हटा कर जींद में राजौंद कास्टीव्यूएंसी में दोबारा शामिल कर दिया जाए। क्योंकि ये

गांव पहले भी जीन्द जिले के थे लेकिन बीच में किसी दूसरी सरकार ने ऐसी बात कर दी कि इनको तोड़ कर दूसरे जिले में मिला दिया। इन गांवों के लोगों को बहुत असुविधा होती है इसलिए इस मसले पर दोबारा विचार कर लिया जाए। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री रतन लाल कटारिया (रादौर– अनुसूचित जाति): मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री जी ने कर– रहित बजट देकर हरियाणा की जनता की उन भावनाओ की कद्र की है जिन के तहत हरियाणा प्रदेश के लोगो ने लगातार तीन साल तक संघर्ष किया और भारत के प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने हरियाणा के साथ एक समझौते के तहत अन्याय किया था। हरियाणा से उसका पानी छीन लिया गया, अबोहर फाजिल्का छीनने की बात कही गयी और चण्डीगढ छीनने की बात कही गयी। हमारे माननीय चौधरी देवी लाल जी और डाक्टर मंगल सैन जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता ने एक संघर्ष किया और संघर्ष समिति के माध्यम से अढ़ाई साल तक लगातार हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ी गयी। उसके बाद चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनी। इसके बाद एक भंयकर सुखा पड़ा। यहां पर भी भारत के प्रधान मन्त्री ने किस तरह से हरियाणा के साथ अन्याय किया, यह सभी जानते हैं। यह बात हुमारे आदरणीय चौधरी सूरज

भान जी ने बतायी है कि किस तरह से गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों को कई–कई सौ करोड़ रुपया सूखा राहत के तहत दिया गया लेकिन हरियाणा प्रदेश को मात्र 35 करोड़ रुपये के लगभग देकर हरियाणा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। लेकिन इस बात का श्रेय हरियाणा की लोकप्रिय सरकार को जाता है कि इतना भयंकर सूखा होने के बावजूद भी हम अपने पांव पर खडे हैं। एक अच्छा बजट हरियाणा के लोगों के सामने रखा है जिसके अन्दर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। इस बजट के अन्दर शिक्षा के बारे में जो प्रावधान किया गया है, मैं उस पर अपने विचार रखूंगा। शिक्षा के बारे में कई जगहों पर स्कूल खोले जाने की भी योजना बनाई गयी है। मैं यह कहूंगा कि रादौर मेरा एक ऐसा इलाका है जहां पर आज तक एम० एल० ए० लूटते रहे हैं। जिस तरह से महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी हिन्दुस्तान के अन्दर आये और वे यहां से सारा रुपया, पैसा और साधन लूट कर ले गये उसी तरह से आज तक रादौर के हल्के से जितने भी एम० एल० ए० रहे हैं, वे वहां के लोगों का शोषण करते रहे और अपनी जेबें भर कर जाते रहे हैं। श्री जय प्रकाश नारायण जैसे देशभक्त की पीठ में छुरा घोंप कर दल–बदल कर, जीत कर तो इधर से आये थे लेकिन बाद में वे कांग्रेस के अन्दर चले गये। इसी तरह से मेंरे हल्के रादौर के साथ सरकार की अब तक दुर्भावना रही है और यह हल्का तरक्की के लिये तड़पता रहा है। मैं अपने उप–मुख्य मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि मेरा जो हल्का रादौर है, उसकी हालत यह है कि अव्वल तो गांवों के

अन्दर स्कूलों के भवन हैं ही नही, अगर कहीं हैं तो बैठने के लिए टाट नही, अगर टाट हैं तो चाक नही, चाक हैं तो अध्यापक नहीं। इस तरह से रादौर हस्के का शोषण हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसी तरह से हो रहा है। कही दर भी स्वास्थ्य सुविधा पूरी नही मिलेगी। जहां तक जनता का सवाल है, तीन लाख जनता के लिए चिकित्सा सुविधा अपर्याप्त है। मैं उप–मुख्य मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि रादौर हल्के के अन्दर इस प्रकार के कोई दो बड़े अस्पताल बनाये जायें ताकि तीन लाख की पापुलेशन को राहत मिल सके और चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस सूखे के कारण जल का स्तर बहुत गिर गया है। आप यी सुनकर हैरान होंगे कि रादौर हल्के के अन्दर जल स्तर 70– 70 फुट नीचे चला गया है जिसकी वजह से किसानों और मजदूरों को अपनी जीविका कमाने मे बहुत समस्या खड़ी हो रही शै। वहां पर हर वर्ष कुंओं की हौदी के अन्दर जहरीली गैस बन जाने के कारण 10– 20 मौतें अवश्य ही हो जाती हैं। इसी तरह से पिछले हफ्ते मेरे हल्के रादौर के एक गांव रपौली में 20 साल का एक लड़का जब कुछ की हौदी के अन्दर 70 फुट नीचे चिनाई कर रहा था तो ऊपर से ढांग गिर जाने से उसकी मृत्युं हो गयी। ठीक उसी तरह से एक दूसरे गांव लखमणी में पिछले हफते 70 फुट नीचे एक नवयुवक पानी का प्रबन्ध कर रहा था। वह भी हौदी की चनाई वार रहा था। ऊपर से डांग गिर जाने के कारण उस नवयुवक की मृत्यु हो गयी। मेरे हल्के के अन्दर इसी तरह से सैंकडों लोग इस जहरीली गैस के

कारण कुओ के अन्दर दब कर मर जाते हैं। मैंने कल अपने प्रश्न के जरिये माननीय आई० पी० एम० साहब के ध्यान में एक बात लानी चाही थी। जो दादुपुर नलवी नहर है, उसके बिना सारा अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिला त्राहि–त्राहि कर रहा है। वहां का जल स्तर नीचे चला गया है। जब तक दादुपुर नलवी नहर नहीं बन जाती तब तक यह त्राहि–त्राहि होती रहेगी। यह एक सुनहरी बैल्ट गिनी जाती है। केन्द्रीय भडार में अनाज की हर छठी बोरी मेरे जिले से होती है। अगर हमारी सरकार इस इलाके की उपेक्षा करेगी तो इसका नुक्सान न केवल मेरे हल्के को होगा, बल्कि सारे हिन्दुस्तान को होगा, जहां से अनाज की हर छठी बोरी सारे भारत वर्ष में जाती है।

स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे हल्के में कोई भी औद्योगिक केन्द्र आज तक सरकार की तरफ से स्थापित नहीं किया गया जिस के कारण मेरे हल्के में वहुत ज्यादा बेरोजगार लड़के फिर रहे हैं। लोग दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मेरे हल्के से पिछले तीस साल से कांग्रेस के लोग चुनकर आते रहे हैं और अगर कोई दूसरा आया भी है तो वह अपने स्वार्थ के कारण कांग्रेस के अन्दर चले गए। उन्होंने इस हल्के के लिए कुछ भी काम नहीं किया और इसका नतीजा यह है कि हजारों किसान और मजदूर आज सड्कों पर भटक रहे हैं। जब तक मेरे हल्के में कोई मिल नहीं लग जाती, तब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान

नहीं हो सकेगा। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं।

इस बजट के अन्दर नगरपालिकाओ को कोई विशेष ग्रांट देने की बात नहीं आई है। इस सरकार ने बीस साल के बाद नगरपालिकाओं के चुनाव कराए हैं। इसलिए मैं इन से प्रार्थना करना चाहता हू कि शहरों के अन्दर जगह–जगह गन्दगी के ढेर लगे हुए– हैं और सीवरेज कहीं नजर नही आता। म्युनिसिपल कमेटी के चुनावो में यंग ब्लड चुनकर आया है और वह कुछ काम करना चाहता है। वे लोग परेशान है कि बगैर पैसे के क्या करें कमेटीज की कोई आय नही है जिससे वे कुछ काम कर सकें, उन शहरों और कस्बों की समस्या को हल कर सकें और उनका विकास कर सकें। इन कमेटीज को विशेष धन देने की आवश्यकता है।

स्पीकर साहब, अब मैं हरिजनो के बारे में कहना चाहता हूं। आजादी के चालीस साल के बाद भी हमारे हरिजन भाइयो की हालत वैसी की वैसी ही है। बाबा अम्बेदकर ने पार्लियामैंटरी सिस्टम आफ गवर्नमैंट इसलिये दिया था ताकि लोगों को समता मिल सके। 150 मुल्कों का संविधान पढ्ने के बाद कास्टीचूऐंट असैम्बली इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर पार्लियामैंटरी सिस्टम आफ गवर्नमैंट देकर गरीबी का उन्मूलन करेंगे और करोड़ों हरिजनों को कुछ न कुछ आर्थिक समता प्रदान करेंगे। लेकिन देश की पूंजीवादी व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ मे

आर्ड जिस के परिणामस्वरूप आज भी करोड़ो हरिजन बेचारे रोजगार की तलाश में भूखे मर जाते हैं। आज देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रान्तों मे सूखे की वजह से इक्कीस इक्कीस दिन भूखे रहकर मर जाते हैं। मैं समझता हूं कि हरियाण प्रदेश आज तरक्की की तरफ अग्रसर है। मैं चाहता है कि हरिजनो को यहा पर क्लास वन और क्लास टू की जो पोस्ट्स हैं, उनमें सही रिजर्वेशन दी जाए और प्रोमोशन में जो रिजर्वेशन उनकी बनती है, वह दी जाए।

स्पीकर साहब, जहा तक वनों के डिवैल्पमैंट की बात है, मेरे जिले कुरुक्षेत्र के अन्दर मोटी ऐसी जगह है जिसको डिवैल्प करके, वन विभाग की तरफ से, एक बहुत ही अच्छी, देखने लायक चीज बनाई जा सकती है। स्पीकर साहब, परिवहन की दृष्टि से मेरे रादौर हल्के में एक सब–डिपो बनाया जाए। जहां तक त्तको की बात है, मेरे हल्के में सड्कों की हालत बहुत खराब है। वे सड़कें हैं चमरोड़ा से बकाना, रामनगर से मंडोखरा, बुवाई से बेरथली, कालवा से सन्नायो, बूखडी से गूडा, मधार से कडरौली अलहार से जयपुर, कांजलु से अलहार, अलहार से जटलाना, कोलापुर से मुकरपुर, छारपुर से मुकरपुर, कन्दौली से रामपुर और बोडला से बांगडो। पिछले चालीस सालों में मेरे हरके में सड्कों की जितनी तबाही हुई है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सारी सड़कें अधूरी पड़ी हैं। इसलिये मेरी उप–मुख्य मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि मेरे हल्के में सड्कों का निर्माण किया जाये। जिस तरह से

हरियाणा प्रदेश तरक्की की तरफ जा रहा है, उसी तरह से मेरे हल्के में भी थोड़ी सी आजादों की रोशनी की झलक दिखाई जाए ताकि यहां के किसान और मजदूर अपने पौधों पर खड़े होकर अपने हल्के की तरक्की कर सकें।

13.00 बजे

स्पीकर साहब, मेरे हस्के के अम्बर भी ओलावृष्टि हुई है। सोनीपत में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय गये और लोगों को उन्होने अपने हाथों से नुक्सान का मुआवजा दिया है। लेकिन मेरे रादौर हल्के में इससे पहले ओलावृष्टि हुई थी जिस में 50 परसैन्ट गायों के अन्दर लगभग 100 परसैन्ट फसलें तबाह हो गई थीं। स्पीकर साहब, आपको यह सुनकर खुशी होगी कि इतने भयंकर सूखे के बावजूद भीं मेरे हल्के के किसानों ने और मैंने हौंसला नहीं छोड़ा। सरकार से ट्रांसफारमर्ज लेकर और बिजली वालों से बिजली मांग–मांग कर एक अच्छी गेहूं की फसल का उत्पादन किया है जो शायद आज हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में पैदा नहीं हुई होगी। एक बेहतरीन गेहूं की फसल का उत्पादन किया लेकिन प्रकृति के प्रकोप के कारण ऐसी भयानक ओला वृष्टि हुई जिससे उस हल्का में कहर ढह गया और सैन्ट परसैंट फसलें तबाह हो गई। कम से कम 70 गांवों के अन्दर फसल बुरी तरह से बरबाद हो गई है। इसलिये आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि मेरे हल्के के जिन किसानों का नुक्सान हुआ है, सरकार उनको कम से कम 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे, राहत

दे ताकि किसानों का हौसला. बढ सके और वे बेचारे मायूस न केकर आगे से और हिम्मत के साथ खेती कर सके।

स्पीकर साहब, इससे अगली बात मैं लैन्ड रिफार्मज से सम्बन्धित कहूंगा। पिछले 40 वर्षों से हरिजनों के लिये सरप्लस जमीन का जो वितरण हो रहा है, उसमें काफी गड़बड़ हो रही है और उन बेचारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है क्योंकि वे जमीनें कागजों के अन्दर ही उन गरीब हरिजनों को दी गई हैं, वास्तव में उनको कुछ नहीं मिला है। जब हरिजन उन जमीनों का कन्ना लेने की कोशिश करते हैं तो कास्टिइजम के झगड़े वगैरह आरम्भ हो जाते हैं और इसी बात को बहाना बनाकर हरिजनों के कतल कर दिये जाते हैं। मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि अगर सरकार दिल से ईमानदारी से, और सच्चाई से हरिजनों को जमीन देना चाहती है तो सब से पहले उस जमीन का पोजेशन सरकार स्वय अपने हाथ में ले ले। उसके बाद उन गरीब हरिजनों में उस जमीन को बांटा जाए ताकि बाद में कब्जों से सम्बन्धित किसी बात का बहाना बनाकर हरिजनों के ऊपर कहर न ढाया जाए। अगर सरकार पहले आप कब्जा लेकर फिर हरिजनों मैं जमीन बाटेगी तो उन लोगों को बाद में किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा, चाहे किसी भी गुट की सरकार क्यों न आये। अगर सरप्लस जमीन में किसी तरह के झगड़े अटके रहे तो कई बार गरीब हरिजनों को कतल कर दिया जाता है, उनके बच्चों की कतल करे दिया जाता है और वे बेचारे सड्कों पर आ जाते हैं।

इसलिये सरकार सरप्लस जमीन बांटते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखे कि जो जमीन हरिजनों को दी जाए, उस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा वगैरह न हो। इन शब्दों के साथ मैं सरकार के इस बजट का, जो वित्त मन्दी महोदय जी ने जनता की भावनाओं को देखते हुए प्रदेश की जनता के हित को देखते हुए, इस सइन में रखा है, का स्वागत करता हूं और उबका समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ने इस सदन के बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कूर मुझे यहां अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान किया है। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस राजनीतिक जीवन से पहले अध्यापक के रूप में काम करता था। अध्यापन मेरा व्यवसाय रहा है। मैं शिक्षा, सिंचाई, बाटू नियन्त्रण, बिजली कृषि, सहकारिता, स्वास्थ्य सेवाएं समाज कल्याण, कर्मचारियों की समस्याएं और व्यापारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विचार इस सदन में रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं शिक्षा पद्धति के बारे में अपने विचार सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नही कि 40 साल के बाद भी आज देश के अन्दर सब से बड़ी समस्या शिक्षा की ही रही है। हमारे यहां पर अविकसित शिक्षा प्रणाली ही प्रचलित रही है। यही कारण है कि आज 40 साल के बाद भी देश का ढांचा इस अविकसित शिक्षा प्रणाली के कारण बदल नही पाया है। शिक्षा

की समस्याओं को देखते हुए हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय और उप मुख्य मन्त्री महोदय से मेरा यह पुरजोर आग्रह है कि अगर हम अपने बजट में सदा ही शिक्षा को उत्तम स्तर पर लाने के लिये प्रयत्न करते रहेंगे, शिक्षा के लिये ज्यादा से ज्यादा बजट का प्रावधान करते. रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये, नवजात शिशुओं और नौजवानों को कालेजों और स्कूलों में शिक्षा लेने के लिये काफी सुविधाए उपलब्ध होंगी और वे अपना विकास जल्दी ही कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे इस बजट में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये काफी प्रावधान किया गया है और साथ ही तकनीकी भिक्षा पर भी दल दिया गया है लेकिन जब तक शैक्षणिक. संस्थाएं हर इलाके में नहीं होंगी, तब तक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार असम्भव है। इसलिये मेरा निवेदन है किं आज 30 साल की आजादी के बाद भी शिक्षा कें क्षेत्र में हम अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। दूसरे राज्यों से हम कही पीछे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हू, उस में कोई कालेज नहीं है और अगर पड़ोस में कोई कालेज है तो वहा पर साइंस और मैडिकल की क्लासिज की कोई सुविधाएं नही हैं। यह बडे अफसोस की बात है कि एक तरफ तो हम चांद पर पहुंचने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आज 20 वीं सदी में अपने बाल बच्चों को साईस की शिक्षा देने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसलिये मेरा आग्रह है कि हथीन क्षेत्र में एक कालेज खोल कर बच्चों को पूरी शिक्षा दी जाए और जय तक किसी और दूसरे कालेज का प्रबन्ध न हो जाए तब तक होडल में जो कालेज है,

उसमें साइंस और मैडीकल की क्लासिज पढाने का प्रबन्ध किया जाए ताकि साथ लगते क्षेत्रों के बच्चे भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त मैं अपनी सरकार का धन्यवाद किए बगैर नहीं रह सकता क्यों कि उसने अल्प बजट होते हुए भी उटावड में जो मेरे क्षेत्र में, पलता है, एक बहुतकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने की कृपा की है। इसके लिए मैं अपनी सरकार, अपने आदरणीय नेता चौधरी देवी लाल जी और गुप्ता जी का धन्यबाद करना चाहता हूं। मैं एक गत यह भी कहना चाहूंगा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भिक्षा संस्थाओं और शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा अन्तर है। कल हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया था कि शहरों में लोगों के पास साधन होते हैं, सम्पत्ति होती है और हर तरह से सम्पन्न लोग रहते हैं इसलिये उनके पास शिक्षा की ज्यादा सुविधाएँ उपलब्ध होती है। इस बात को सुन कर मुझे खुशी भी हुई थी और दुख भी हुआ था। दुख इसलिये हुआ था कि ग्रामीण जनता, जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान की सुविधाएं नहीं हैं, वे अपने अल्प साधनों में से साधन जुटा कर शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देते हैं। अपनी जो बुनियादी जरुरतें हैं, उनमें कटौती करके वे स्कूलों के कमरे आदि बनाने के लिये राशि जुटाते हैं। इसके विपरीत जब हमें अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की बात जनती है तो आज भी हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। लेकिन बड़े अफसोस. के साथ कहना पड़ता है कि चौथी, पांचवीं, आठवी और दसवी की परीक्षाएं पास करने के बाद जब हमारे बच्चे शहरों

के स्कूलों और कालेजों में दाखिला लेने के लिये जाते है, तो वहां पर प्राईवेट स्कूलों और कालेजों की जो बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, उनमें सबसे पहली कंडीशन इंगलिश मीडियम की होती है। हमारे बच्चों का मीडियम हिन्दी होने के कारण पहले तो उनको उनमें दाखिला नहीं मिलता, अगर दाखिला मिलता भी है तो बच्चे उन स्कूलों या कालेजों के बच्चों के साथ अपने आपको एडजस्ट करने में असमर्थ रहते हैं। मैं अपनी सरकार से आग्रह करूगा कि कम से कम ब्लाक लैवल पर और जिला स्तर पर जो नवोदय विद्यालयों और सैन्ट्रल पब्लिक स्कूलों की स्कीम लागू की गई है, उसी तरह से मेरे क्षेत्र हथीन मे, जो शिक्षा के लिहाज से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, प्राथमिकता दे करके नवोदय विद्यालय और सैडल पब्लिक स्कूलों की तरह, शिक्षण संस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी बडे लोगों के साथ जुड़ सके और हम लोग तरक्की करने में उन का मुकाबला कर सके। इसके अलावा, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा राज्य की जनता का भविष्य कृषि से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज 40 साल के बाद भी चाहे पिछली कांग्रेस सरकारों ने विकास के कार्यों पर कितना ही पैसा खर्च किया हो, किसानों को वे सुविधाएं नहीं दी गई जिससे हमारे देश का विकास हो। मुझे बडे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसान वर्ग का, जिसने अपने देश के आत्म सम्मान को बढ़ाया है, दुनिया की नजरों में भारत का सिर ऊंचा उठा या है, उस किसान को पिछली सरकारों ने सुविधाएं नही दीं। मैं यह. भी कहना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा

उन प्रान्तों में से हैं जो अधिकांश राज्यों की अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थो. की पूर्ति करने के लिए उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा राज्य में कांग्रेस सरकारें होने के बाद भी किसानों को वे सुविधाएं नहीं जुटा पाई जिससे देल का सम्मान ऊंचा होता और समस्याओं से छुटकारा मिल पाता। एस० वाई० एल० नहर का पानी आने के बाद भी फरीदाबाद और गुडगावां के कुछ हिस्सों को नहरी पानी का उपलब्ध होना असंभव है। अध्यक्ष महोदय आपको मालूम है कि कांग्रेसी लोगो ने 40 साल में कभी भी इस बात को नहीं सोचा कि एक ही राज्य के रहने वाले किसानों के लिए नहरी पानी की दरें अलग अलग हों। मेरे क्षेत्र के किसानों को हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा और 8 गुणा तक नहरी पानी की दरें देनी पड़ती हैं। इसलिये मैं—सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि तत्कालीन रूप से हरियाणा की किसान परस्त सरकार, चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में किसानों और मजदूरों की सरकार गठित हुई है। इसलिये यह सरकार सुविधायें देकर हमारे ऊपर एहसान करे। हम भी हरियाणा प्रान्त के दूसरे किसानों की भान्ति रहना चाहते हैं, हमें भी वे सारी सुविधायें मिलनी चाहिए जो प्रान्त के दूसरे किसानों को मिल रहीं हैं। जैसे प्रान्त के दूसरे किसानो को पक्के वाटर चौनल्ज के थ्रू सुविधाएं उपलब्ध हैं, वही सुविधाएं हमें भी मिलनी चाहिएं। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप यहां पुर जो सहकारिता की मद देख. रहे हैं, मुझे बडी खुशी कें साथ आपकी मारफत सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि

ऐसे ऐतिहासिक कदम चौधरी देवी लाल जी ने उठाएं हैं जिनकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। जो हरियाणा पहले चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसी लाल के कुकृत्यों के कारण जाना जाता था और कभी हरियाणा की आया राम गया राम के नाम से प्रसिद्धी थी, आज अगर हम बाहर किसी प्रदेश में जाते हैं तो लोग चौधरी देवी लाल के नेतृत्व वाला हरियाणा कह कर पुकारते है। मैं समझता हूं कि गांवों में रहने वाले लोग जिनमें गरीब और मजदूर लोग रहते है, उनकी बहुत ही दयनीय हालत है। गांवों में ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां पशु और मनुष्य एक ही स्थान पर रह रहे हैं। वे लोग कर्जे से दबे हुए हैं। हमारी सरकार ने कुछ कर्जे माफ करके एक अच्छा काम किया है। अभी भी गांवों के बहुत से लोग, को–आप्रेटीव बैकों और लैण्ड डिवैल्पमैंट बैकों के कर्जे से दबे हुए हैं। हमारी सरकार ने इन बैकों के कर्जों के नीचे दबे हुए लोगों को छुटकारा दिलाने की जो योजना बनाई है उसके लिये सरकार बधाई की पाव है। इसके लियै हमारी सरकार ने बजट में कुछ प्रावधान भी किया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मैंने पहले भी कई बार जिकर किया है कि मेरे हल्के के सबसे बड़े गांव और–गाबाद में 1958– 59 में एक पी० एच० सी० खोली गई थी। जब हमारी सरकार पहली बार 1977– 78 में सस्ता में आई थी तो उस समय उस बिल्डिंग के लिये और दूसरें कामों के लिए 16 लाख रुपये मन्त्र हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि कुछ दिनों वाद हमारी सरकार सस्ता से बाहर हो गई और

वहां पर जो काम होना था, वह आज तक नही हो पाया है। भजन लाल और बंसी लाल ने एक पैसा भी उसके लिए नहीं दिया जिसकी वजह से आज तक हमारा यह काम लटका हुआ है। वहां पर जो ब्लाक मैडिकल आफिसर था, स्टैनो वगैरा था या दूसरा स्टाफ था श्री बंसी लाल जी उनको वहां से स्थानान्त्रित करवा कर कहीं अन्यत्र ले गए। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम बुनियादी सेवाए जो जरूरी हैं, जिनकी लोगों को बेहेद आवश्यकता है और मौलिक अधिकार हैं, उनका स्वास्थ्य सबंधी सेवाएं अवश्य उपलब्ध कराई जायें। मेरा हल्का पिछले 40 सालों से पिछड़ा हुआ रहा है और शुरू से ही विपक्षी गढ़ रहा है जिसकी वजह से आज तक शासन ने इस ओर ध्यान महीं दिया है। अव हमारी चौधरी देवी लाल जी से पूरी आशा है कि जिस हल्के की ओर विपक्षी गढ़ होने की वजह से पिछली सरकारों का ध्यान नही गया है, उसके विकास कार्यों की तरफ अब ध्यान दिया जाये। हमारे आदरणीय मुख्य मुन्त्री जी ने एक स्कीम शुरू की है कि जो भी गांव कोई सामूहिक काम शुरू करना चाहेगा, उसके लिये जितना पैसा वै इक्ट्ठा करेगे उतना ही पैसा सरकार उस गांव को ग्रांट के रूप में अपनी तरफ से देगी। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी जो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कायम की है। हमारी सरकार अपने सीमित साधनों के बावजुद, घाटे के बाबजूद और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद भी विकास कयॉ में कोई रुकावट नहीं आने देना चाहती। हमारे महान नेता ने कल सदन में लड़कियों की शिक्षा कौ कावा देने के लिये घोषणा की थी कि जो कोई गांव

लड़कियो के स्कूल खोलने के लिये जितने पैसे इकट्ठे करेगा उससे दो गुणा नहीं बल्कि तीन गुणा पैसे उन गांवो को सरकार की तरफ से दिए जायेंगे। यह बात कहते हुए तो मुझे खुशी हो रही हूं कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे रही है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के हथीन मे एक अन्धोप गाँव है। इस गांव मे लडकियों का एक स्कूल श्री सतबीर सिंह के नाम से खोला जाये। श्री सतबीर सिंह, श्री लंका मे अपने देश की सेवा मै रहते हुए, सरकार के आदेश पर श्रीलंका में गये थे लेकिन वे वहीं पर सेवा करते हुए शहीद हो गये। मेरी माग है और मेरे हल्के के उस गाय की मांग है कि श्री सतबीर सिंह ने जो अपने प्राणों की आहुति श्रीलंका में दी है, उसके नाम से गाव में एक कन्या पाठशाला खोली जाये। मेरे हल्के के गांवों में आय के बहुत ही कम साधन है। वे लोग तो अपनी तरफ से स्कूल खोलने के लिये पैसे इकट्ठे करेंगे ही, लेकिन मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह शहीद सतबीर सिंह के नाम पर अपनी तरफ से ग्रांट दे कर कन्या पाठसाला उस गांव में खोले ताकि उन लोगों की जो भावनाएं उस शहीद से जुड़ी हुई हैं, वे पूरी हो सकें। मेरी सरकार से पुनः प्रार्थना है कि लड़कियो के स्कूल के लिये ग्रान्ट के रूप में दी जाने वाली राशि की जो शर्त लगाई है, उससे इस गांव को मुक्त कर दिया जाके। वहां पर लड़कियों के लिये शिक्षण संस्था सरकार को खुद ही खोल देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के हथीन कस्बे में जो सीजनल मण्डी बनी हुई है, उसको सीजनल मण्डी न रख कर पूरी मण्डी बनाया जाये। वहां पर जमीनै अधिग्रहण कर

ली गई है लेकिन उसका विकास अभी तक नहीं हो पाया है। काफी कोशिशों के बावजूद केवल गेंहू और जौ की ही सीजनल परचेज हो पाती है। बाकी फसलों को किसान होडल या पलवल ले जाने हैं। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि हथीन में एक सब्जी मण्डी और कृषि मण्डी जल्दी से जल्दी सबयार्ड के रूप में मन्जूर की जाये और उस पर तुरन्त कार्य आरम्भ करवाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश टूरिज्म के मामले में सारे देश में शुरू से ही अग्रणी रहा है। परन्तु मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है. कि मेरा इलाका जहां सुविधाओं से वंचित रहा है यंहा टूरिज्म के मामले में भी पिछडा हुआ रहा हैं। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर 4– 5 कमरों का एक पर्यटक स्थल अवश्य बनाया जाये। यह पर्यटक स्थल प्रोपर हथीन में हो ताकि हथीन को भी टूरिज्म, की सेवाओं का लाभ पहुंच सके। यदि सरकार कोई पर्यटन स्थल खोल देती है तो हमें भी वहां पर एक साथ बैठकर उठने–बैठने, खाने–पीने और मिलने–जुलने का मौका मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कर्मचारियों के बारे में कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। हमारी इस सरकार को बनाने में सरकारी कर्मचारियों ने बहुत योगदान दिया है। मेरा कहना यह है कि इस सरकार को बनाने में जहां व्यापारियों, मजदूरों और किसानों ने साथ दिया है, वहां कर्मचारियों ने भी कम सहयोग नही दिया है। हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने

कर्मचारियों को काफी राहतें दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह सुविधा हमारी सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति ठीक न होते हुए भी अपने कर्मचारियो को प्रदान की है। लेकिन अब भी हमारे कर्मचारियों में यह समस्या बनी हुई है कि वे शहरों से गांवों में जाना नही चाहते। इस संबंध में मेरी सरकार मे प्रार्थना है कि सरकार अपने कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दे या और कोई सुविधा दे ताकि कर्मचारियों को शहरों से गांवों में जाने में कोई कठिनाई महसूस न हो सके। यदि सरकार उनको कोई विशेष लाभ दे कर गांव में जाने के लिये तैयार करती है तो जो हमारे ऊपर ट्रांस्फर्ज का बोझ बना रहता है, उससे भी हमें छुटकारा मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के हथीन में 10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत दो स्कूल हैं। इन दोनों स्कूलों में कोई प्रिंसिपल और लैक्चरार जाने के लिये तैयार नहीं होता क्योंकिं वहां पर न तो कोई कालेज हैं और न ह्वीं उनके रहने के लिये रैजिडैंशियल फैसेलिटीज हैं उनके बच्चों के लिये इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। ये सारी– सहूलियतें इन्टरलिकड हैँ। ताक लैवल पर आवासीय विद्यालय स्थापित होने चाहिएं। मेरे क्षेत्र में कालेजिज और सैकिन्डरी विद्यालयों में मैडिकल और साईस के विषय होने चाहिए। प्राचार्य और आचार्यो के या दूसरे अध्यापकों के जो स्थान रिक्त पड़े है. उनकी भर्ती करवा केर हमारे एरिया के बच्चो के भविष्य का सुधार करने का प्रयास किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

डा० बृज मोहन (जगाधरी): अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट सदन मैं पेश हुआ है, यह हर दृष्टि से सराहनीय है। इसमे कोई कमी मुझे नजर नही आती। हमारे ओपोजीशन के साथियों को भी कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए लेकिन उन्होंने इस पर नुक्ताचीनी जरुर की है और वह नुक्तानीनो भी केवल कहने के लिये ही की है। उनके पास कहने के लिये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने इन्टरप्शान्ज में ही अपना टाईम पूरा कर दिया। हरियाणा की सारी जनता को पता है कि यह सरकार किन घोषणाओं और किन वायदों से चुन कर आयी थी। क्या क्या अन्याय हरियाणा की जनता के साथ पिछली सरकार मे किया था? इस सरकार ने चुनाव से पहले जो घोषणायें की थी उनको पूरा किया। अब उन घोषणाओं मे कोई कमी न करते हुए हरियाणा के विकास का बजट इस सरकार ने रखा है। जहां हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणाओं को पूरा किया वहां इस प्रदेश के विकास का भी– पूरा ध्यान रखा है। इस बजट मे भी पूरा ध्यान रखा गया है। कल यहां सदन में एक बात और भी आयी थी जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मुझे पता लगा है कि हमारी सरकार उसकी तरफ पहले ही ध्यान दे रही है। पता लगा है कि डिमांड नम्बर वन पर कोई बिल आ रहा है उपसे हुमारे भाई, जिन्होंने उसके बारे में जिक्र किया था वे भी खुश हो जायेंगे और उसकी सराहना भी करेंगे।

इसके साथ साथ मैं कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, शायद कुछ मेरे साथी उन समस्याओं का यहां जिक्र न कर सकें। ये समस्यायें मैडिकल और पब्लिक हैल्थ के बारे में हैं। पहले तो मैं हस्पताल, प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज, कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर्ज और डेन्टल ट्रीटमैन्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इन समस्याओं की ओर सरकार को विशेष ध्यात देने की आवश्यकता है। प्राइमरी सैन्टर्ज में स्टाफ की कमी है और कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर्ज में भी जितना स्टाफ चाहिए उतना नहीं है। इसी प्रकार से शहरों के हस्पतालों में जितने डाक्टर्ज, नर्सिज और फार्मेसिस्ट चाहिए उत्तने नही हैं। जो रूल्स बने हुए हैं वे बहुत पुराने बने हुए हैं। उस समय आबादी भी कम थी और मरीज भी कम थे तथा इसी लिहाज से अस्पतालों में अटैण्डैन्स भी बहुत कम थी। लेकिन आज चालीस साल के बाद, इस युग को आम– तौर पर वनस्पति का युग कहते हैं, हर चीज में मिलावट है। पहले लोग असली थी खाते थे, दूध पीते, थे और बीमार कम पड़ते थें। आजकल दूध और घी भी डुप्लिकेट मिलते है और लोग बीमार भी ज्यादा होते हैं। मेरे पास डाक्टरज के नार्म का चार्ट है। 25 या 30 बिस्तर के अस्पताल में 3 डाक्टर हैं और जो अस्पताल सब–डिविजन लैवल के हैं, वहां पर तीव डाक्टरज बहुत ही थोड़े हैं। मिसाल के तौर पर मैं जगाधरी की बात कहता हूं। सब–डिविजनल अस्पताल होने के नाते वहां पर पोस्ट–मार्टम सैन्टर मी है। एक डाक्टर तो पी०पी० सैन्टर में रहेगा और दूसरा कोर्टस में शहादतें आदि में लगा रहेगा। एक डाक्टर को अस्पताल

की एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करनी पड़ती है। कभी–कभी डांक्टर छुट्टी पर भी होता है तो अस्पताल में कौन रहेगा? यह नार्म बहुत ही पुराना है, इसको बदलना चाहिए। जो प्राइमरी हैल्थ सैन्टर है और पैप्सु के पुराने हैल्थ सैन्टर हैं जो हरियाणा में आए हैं, उनमें भी दो डाक्टर्ज का प्रोवीजन है जो मैं समझता हूं कम हैं। मेरे विचार में इन में तीन डाक्टर्ज होने चाहिए जिनसे एक लेडी डाक्टर का होना बहुत जरूरी है लेकिन लेडी डाक्टर्ज कम मिलती है। इस बारे मे मैं सुझाव दूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ट्रेन्ड दाई या ट्रेन्ड नर्सें भी लगाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि अगर वहां पर लेडी डाक्टर की व्यवस्था हो जाए तो गांव के लोगों को विशेषकर महिलाओं को बहुत सुविधा हो जाएगी। कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर में इस समय चार डाक्टरों की सुविधा रखी गई है और डैण्टल की सुविधा भी रखी गई है। मेरा सुझाव है कि आज के जमाने में कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर में लेडी डाक्टर और कुछ स्पैंशलिस्टों का भी प्रोवीजन होना चाहिए जो आजकल नहीं है। स्पैशलिस्ट भी पूरे होने चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो अस्पताल 25 या 30 बिस्तर के है, जिनमें नार्म के मुताबिक तीन डाक्टर्ज हैं। नार्म को बढा कर वहां पर 5 डाक्टर्ज किये जाएं और जो 50 बिस्तर के अस्पताल मे नार्म के अनुसार 5 डाक्टर्ज की सुविधा है, उसे भी बढ़ाया जाए क्योंकि इनडोर पेशन्ट काफी ज्यादा होते हैं। ऐक्स–रे के लिये भी डाक्टर का होना जरूरी हैं, केवल टैक्नीशियन से काम नही चलेगा क्योंकि कई वार टैक्नीशियन की रिपोर्ट के आधार पर डायग्नोजिज मिसलीड हो

जाते है मुझे पता चला है कि हरियाणा के अन्दर अभी भी 40 क्लाज–1 और 274 क्लास डाक्टरों की जगहें खाली है। बार–बार इन्टरव्यू होते है, सिलैक्शन्ज होती है लेकिन डाक्टर्ज ज्वाईन नही करते और खासतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं जाते जब कि वहां पर थोड़ा–बहुत रूरल अलाऊंस भी मिलता है। मेरा एक सुझाव है कि सरकार यह तजुर्बा करके देखे कि डाक्टरों को जौ एन०पी०ए० मिलता थैं, वह हटा दिया जाए और डाक्टरों को थोड़ी–प्राईवेट प्रैक्टिस एलाऊ कर दें तो शायद ज्यादा डाक्टर सर्विस में आ सकते है। इसके साथ साथ जो हस्पतालों में मैडिकल और डैन्टल सर्विस है, वह पुनाने रूल्ज के मुताबिक और तनखाह के मुताबिक लोगों को मिलती हैं। कल ही मेरा एक सवाल था। दांत का कोई भी ट्रीटमैंट बगैर पैसे के हस्पताल में नही होता। उसके जवाब में कहा गया कि 1200 रुपए साल यानी 100 रुपए महीने की इंकम वाले आदमी के लिए यह ट्रीटमैंट की है।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, आपके केवल चार मिनट रह गए हैं।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहव, मैंने तो अभी शुरू ही किया है, मैं आगे फिर बोल लूंगा अगर आप इजाजत देंगे। इस तरीके से मैडिकल नाइन में, लैबोरेटरी एक्सरे और अन्य टैस्टों मे पे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। यह पता लगाना बडा मुश्किल होता है कि किस की कितनी पे है। अगर इस बात का

ध्यान न रखते हुए डाक्टर गलती कर जाता है तो आडिट वाले डाक्टर से पैसा रिकवर करने के लिए कहते है। इस बारे मेरा सुझाव है कि बाकी मामलों को छोड कर डैंटल ट्रीटमेंट हम सब के लिये फ्री कर दें। ऐसा करने से ज्यादा से ज्यादा लोग हस्पतालों में आएंगे आज कल लोग हस्पताल में इसलिये नही आते क्योकि वहा पर वगैर फीस के ट्रीटमैंट नही होता। मैं तो यह भी कहता हूं कि मैडिकल साइड में जो तनखाह के मुताबिक कर्मचारियो से चार्ज करते है इसकी जगह सबसीडाइज्ड रेट कर दें। एक्सरे का लैबोरेटरी का तथा जो और टैस्ट होते हैं, सब के चार्ज एक जैसे हो जाएं और नोमिनल चार्ज रखे जाएं ताकि लोग हस्पतालों में आ सकें। आजकल एलोपैथी का ट्रीटमैंट बहुत मंहगा है, यह आम आदमी के बस की बात नहीं है। आजकल आयुर्वेदिक और होम्यो– पैथिक का ट्रीटमैंट लेना ज्यादा लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनका लम्बा ट्रीटमैंट है और कुछ टाइम के बाद आदमी को रिलीफ मिलता है। आज के जमाने में–आदमी चाहता है कि उसे फौरन आराम मिले इसलिये वह ऐलोपैथी ट्रीटमैंट की तरफ जाता है। आज ही एलोपैथी के बा गे मन्त्री जी ने बताया कि सारे हरियाणा के लिये दवाइयों का जो बजट है, वह केवल अढाई करोड़ रुपए है। मैं एक आदमी का हिसाव नही बताता बल्कि एक युनिट जो 5– 6 व्यक्तियों की होती है, उसके हिस्से साल में कैवल साढ़े छः रुपए आते हैं। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में यह कुछ भी नही है। साढ़े छः रुपए अगर 5– 6 आदमियों के लिये साल भर मे बजट हस्पताल में होगा, तो आप

अन्दाजा लगा लें कि इससे क्या होता है, यह बहुत थोड़ा है। खास तौर पर जो लोग एमरजैसी मे आते है उनकी हालत बडी नाजुक होती है। एमरजैंसी ड्रग्ज वैसे भी बहुत मंहगी होतीं हैं। ये दवाइया हस्पतालों में सरकार की तरफ से बगैर पैसे के और बगैर रिप्लेसमैंट वो मिलनी चाहिएं। इस लिए बजट में इसके लिए प्राव–धान करना बहुत जरूरी हैं।

श्री अध्यक्षः डा० साहब आप बैठिए। आप कंटिन्यू करेंगे। अब हाउस मंडे, 28 मार्च, 1988 को बाद दोपहरें दो बजे तक के लिये ऐडजर्न किया जाता है।

13:30 बजे।

(तत्पश्चात सदन सोमवार, 28 मार्च, 1988 को बाद दोपहर दौ बजे तक के लिये स्थगित हुआ।)